

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 2000

खण्ड-1, अंक-7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार 15 मार्च, 2000

पृष्ठ संख्या

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
पंचायत चुनावो के लिए अध्यापको को प्रतिनियुक्त करने संबंधी	(7)1
वक्तव्य:—	
शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी	(7)1
उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी घोशणा	(7)4
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(7)4
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएं	(7)5
वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7)6
वाक-आउट	(7)36
वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)36
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	

श्री बलबीर पाल भाह द्वारा	(7)46
वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)47
भोक प्रस्ताव	(7)73
वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)74
वाक आउटस	(7)81
वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)81
उपाध्यक्ष का चुनाव	(7)89
वर्ष 2000-2001 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(7)92

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 15 मार्च, 2000

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a calling attention notice given by Sh. Karan Singh Dalal regarding deputing the teachers for Panchayat Elections. I admit it. Sh. Karan Singh Dalal may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पंचायत चुनावों में शिक्षण अमले की चुनावों में ड्यूटी लगाने के कारण हरियाणा राज्य के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है तथा बच्चों की परीक्षाएँ भी प्रभावित होने की संभावना है।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह सदन में इस संबंधी में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

वक्तव्य—

शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Education may make a statement.

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बहादुरग सिंह): इस बारे में निवेदन है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-12-1999 एवं आदेश दिनांक 21-2-2000 को प्रकाश में आई 2000 की विशेष राहत याचिका क्रमांक 1598-1599 एवं 2000 की विशेष राहत याचिका क्रमांक 1929-30, 1717-18 एवं 1705-06 द्वारा निर्देश दिए गये थे कि राज्य सरकार तथा राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायत, ग्राम समितियों, जिला परिषदों एवं नगर पालिकाओं आदि के चुनाव फरवरी, 2000 के अंत कर करवायें। राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में 2000 की 72-73 एवं 2000 की 774-79 सिविल अपील दायर करते हुये इस उद्देश्य से प्रार्थना की थी कि विधान सभा भंग होने के कारण जो चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी और जिसके लिये चुनाव की तिथि 22 फरवरी 2000 निर्दिष्ट की जा चुकी थी, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग इस उद्देश्य के लिये और अधिक समय दिये जाने की आवश्यकता थी। संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिए कि राज्य सरकार तथा राज्य चुनाव आयोग द्वारा जहां-जहां भी चुनाव करवाये जाने हों वहां पर ग्राम पंचायत आदि के चुनाव 31 मार्च, 2000 को या इससे पूर्व करवाये जायें। उक्त आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिये थे

कि राज्य एवं चुनाव आयोग नगर परिशद आदि के चुनाव भी करवायेँ और जहां-जहां चुनाव करवाये जाने आव यक हो, वहां पर चुनाव प्रक्रिया 07 अप्रैल, 2000 तक पूर्ण कर ली जाये। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 161 के तहत ऐसे चुनाव कराये जाने का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण राज निर्वाचन आयोग के पास है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम आयोग द्वारा व्यवस्था मे उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित सभी आव यक तैयारियां नोटिस आदि जारी करना और तदनुसार चुनाव करवाना आव यक था ताकि दिनांक 31-3-2000 तक पंचायत समितियों आदि के चुनाव सम्पन्न करवाये जा सके तथा दिनांक 07-04-2000 तक नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न करवाये जा सके।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 169 मे निम्नलिखित प्रावधान है:-

धारा 169: राज्य सरकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिशद के चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग को आव यकतानुसार मतदान सूची तैयार करने एवं चुनाव संबंधी अन्य कार्यों के लिये कर्मचारी उपलब्ध करवायेगी।

इसी अधीनियम की धारा 179 के अनुसार राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध करवायेगी जितने आयोग को चुनाव संबंधी कार्यों के लिये चाहिये। हर कर्मचारी उन निर्देशों का पालन करेगा जो उससे आयोग या आयोग द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिये जायेंगे।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्य चुनाव आयोग की इसकी आवश्यकतानुसार सभी सहायता दे। राज्य सरकार को 12 मार्च तथा 16 मार्च को करवाये जाने वाले पंचायत चुनावों के लिये कर्मचारी लगाने हेतु सभी तरह की आवश्यकताये पूरी करनी थी।

विधानसभा एवं लोक सभा चुनावों में अध्यापकों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी हमें लागू की जाती है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 185 के अन्तर्गत प्रावधान है कि इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारी को बिना उचित कारण के अपनी आफिसियल ड्यूटी को निभाने का दोषी पाया गया तो इस दोष के लिये सजा के रूप में जुर्माना लगाया जायेगा जो कि 2000 रुपये तक हो सकता है। जिला चुनाव अधिकारियों/राज्य चुनाव आयोग की आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग को चुनाव ड्यूटी करने के लिये विद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों के नाम भेजने पड़ते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि विद्यालय की आंतरिक परीक्षाएँ तथा बोर्ड की परीक्षाएँ पहले ही भंग हो चुकी हैं और अध्यापन कार्य नहीं हो रहा है। महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएँ अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आरम्भ होंगी और वहाँ तीन सप्ताह की परीक्षा तैयारी की छुट्टियाँ चल रही हैं और कक्षा अध्यापन का कार्य नहीं है। इस प्रकार पंचायत चुनावों के कारण विद्यार्थियों की पढाई पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है। पंचायत चुनाव 12 तथा 16 मार्च को निर्दिष्ट होने के कारण बोर्ड की परीक्षाएँ जो पहले 11 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च को निर्धारित थीं उन्हें पुनः निर्धारित किया गया है। आंतरिक परीक्षाएँ भी इसी के अनुसार पुनः निर्धारित की गई हैं।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप इस बारे में दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: ठीक है सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसे इसलिए संतोषजनक नहीं माना जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार को पहले से ही इस बारे में मालूम था। पंचायतों के चुनाव पहले भी करवाए जा सकते थे लेकिन इसके पीछे इनका यह ध्येय था कि कहीं इन चुनावों को पहले करवाने से विधान सभा के चुनाव पर असर न पड़े। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से गलत दलीले दी गईं, इसके लिए सरकार को सख्त फटकार लगी।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरा आपके माध्यम से इनको कहना है कि ये विषय तक सीमित रहे। इन्होंने अध्यापको की पंचायत इलैव इन मे ड्यूटी के बारे में कालें अटैं इन मो इन दी थी। इसमें फलाने को फटकार लगी। यह नहीं था। कोर्ट अंतिम निर्णय दे चुका है। कोर्ट में अपनी बात को लेकर हर आदमी जा सकता है। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गवर्नमेंट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया, उसको हमने माना है। अब ये अपने प्र न से बाहर जाकर बात कहें यह ठीक नहीं है। इन्होंने जो कालें अटैं इन मो इन दी है, उससे संबंधित प्र न ही पूछें।

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, किसको फटकार लगी किसको नहीं इस बात को छोड़कर आप अपना प्र न पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने यह माना है कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव करवाए जाने जरूरी थे। हरियाणा में हमारे और भी कर्मचारी हैं क्या अध्यापको को उनसे अलग नहीं रखा जा सकता था? ये दूसरे अधिकारियों को बुला सकते थे। मेरा अभिप्राय है कि हरियाणा में जो स्टूडेंट्स हैं, अध्यापको की ड्यूटी लगने की वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ है। हरियाणा में शिक्षा की स्थिति पहले ही खराब है। हरियाणा में परीक्षाएं चली हुई हैं और

अध्यापक बच्चो को नही पढाकर चुनावो की ड्यूटी मे लगे हुए है। मै इनसे इस बारे मे जानना चाहता हूं?

श्री बहादुरग सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन चुनावो मे अध्यापको की ही नही बल्कि हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियो की ड्यूटी लगायी गयी है। जैसा मैने पहले ही बताया कि आंतरिक परीक्षाएं और बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही भुरु हो चुकी थी इसलिए अब अध्यापन कार्य नही हो रहा था। अतः परीक्षाओ की तैयारियो मे अध्यापको की ड्यूटी लगाने से कोई फर्क नही पडता।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी नये है उनकी इज्जत करता हू। (विघ्न) मै आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि यह जो मेरी बात का ठीक से जवाब क्यों नही दे सके? राज्य में बहुत से अधिकारी है, इसलिए क्या यह जरुरी है कि शिक्षको की ही इन चुनावो में ड्यूटी लगायी जाती? अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस बात की कोई चिंता नही की। जबकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है। हमारे बच्चे नौवी या दसवीं एवं उससे आगे की पढाई के लिए स्कूलो मे और कालेजो मे जाते है उन्हे परीक्षाओ के दौरान शिक्षको की जरुरत होती है। क्योंकि उन्होने उनसे इस बारे मे विचार विमर्श करना होता है, पूछताछ करनी होती है। सरकार ने उनकी ड्यूटी चुनावो मे

लगाकर बहुत बड़ी कोताही की है। इनको इन चुनावो मे िाक्षको की ड्यूटी नही लगानी चाहिए थी। अगर इन्होने इस बारे मे सही तरीके से विचार किया होता तो राज्य के दूसरे अधिकारियो की इन चुनावो मे ड्यूटी लगायी जा सकती थी? अध्यक्ष महोदय, जब परीक्षाफल आएगा तब आप इसका नुकसान देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते ही है कि जब इम्तहानो के बाद हरियाणा मे परीक्षाफल आता है तो वह वैसे ही कम होता है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। पहले जो इनकी सरकार थी उसने ही स्टेट चुनाव आयोग का गठन किया था। ये चुनाव करवाने का काम उसी स्टेट चुनाव आयोग का है। अध्यक्ष महोदय, पहले जो चुनाव की तिथि निर्धारित हुई थी वह 12 और 19 तारीख की हुई थी। चूंकि 19 तारीख को होली थी इसलिए त्यौहार के दिन को देखते हुए ये चुनाव पहले करवाए गए। स्टेट गवर्नमेंट का काम तो सिर्फ यह है कि चुनाव आयोग को जिन जिन चीजो की जरूरत होती है, उसको वह पूरा करती है। चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए जितने कर्मचारी चाहिए, उतने स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है इसलिए इस विषय को इतना लम्बा चौडा बढाने की आवस्यकता ही नही है। आखिर चुनाव तो होंगे ही।

इनमें कौन-कौन से कर्मचारी हो, इसका फैसला करना चुनाव आयोग का काम है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो अभी रह ही गया है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आपके दोनों क्वै चंज हो गये हैं। आप सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। आपको मो इन माल लिया गया था और आपने अपने क्वै चन भी पूछ लिए हैं इसलिए आप बैठें। (विधन)

उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी घोशणा

Mr. Speaker: Under Rule 10(i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly, I fix today, the 15th March, 2000, as the date for the election of Deputy Speaker. This item will be taken up today later on.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Member, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 30.

Finance Minister (Sh. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly be suspended

and Government business be transacted on Thursday, the 16th March, 2000.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 16th March, 2000.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से उस दिन संपत सिंह जी से निवेदन किया था कि आप नानॉ आफि टायल डे को ऑफि टायल डे में कन्वर्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नये नये सदस्य चुनकर आए हैं और कोई अपना बिल रखना चाहता है कोई अपना प्रस्ताव रखना चाहता है। हरियाणा प्रदेश की कई समस्याओं पर चर्चा होनी है उस दिन भी चौधरी संपत सिंह जी ने आपका वासन दिया था कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर जरूर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक प्रस्ताव दिया था कि हरियाणा में लडकियों को मां-बाप की संपत्ति में से जो हिस्सा मिलता है वह भादी के बाद नहीं मिलना चाहिए, इससे हमारे गावों का भाई-चारा बिगड़ता है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आपको कोई सजै पान देना हो तो दे, आप तो भाषण देने लगते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि नाने आफि टायल डे को आफि टायल डे में कन्वर्ट न करें और जो प्रस्ताव मैंने दिया हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कल कोई वि शेष बिजनैस नहीं है और आज भी आपको बजट पर अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

Question is-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 16th March, 2000.

The motion was carried.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएं

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपकी सेवा में हमारे एक सीनियर मैम्बर कैप्टन अजय सिंह ने काले अटेंशन मोशन दी हुई है आज आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा कि उन्हें रद्द कर दिया था उस पर कोई बात होगी या नहीं?

Mr. Speaker: The Calling Attention notice No. 4 regarding suspension of disbursement of loan from World Bank has been sent to Government for comments. The Calling Attention notice No. 3 regarding abolishing of 29 Municipal Committies has been disallowed. The Calling Attention notice

No. 7 regarding the pollution in Dharuhera Industrial Complex is under consideration.

श्री अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि आप तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं कल चुनकर आया हूँ। आप हमारे कस्टोडियन हैं।

श्री अध्यक्ष: यह पौल्यू इन आपको कई दिन से नजर आता होगा या आज ही नजर आया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संपत सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव सदन की समीक्षा के लिए मैंने रखा है कि लडकियों को उनकी भाादी के बाद बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलना चाहिए उसके बारे में भारत सरकार से आप निवेदन करें कि कानून में तबदीली हो।

Mr. Speaker: Your Calling Attention Notice No. 2 regarding mixing of sewerage water into the drinking water in Palwal City has been admitted for tomorrow, the 16th March, 2000. लडकियों के जायदाद के हिस्से के बारे में जो नान-आफि टायल रैजोल्यू इन है उसे हम पहले ही डिसअलाउ कर चुके हैं उसे आप अगले सै इन में दें, फिर उस पर विचार होगा। इसके अलावा मैं हाउस को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हरियाणा विधान सभा के इतिहास में यह पहला अवसर है जब सदस्यों को सबसे ज्यादा बोलने का मौका दिया

गया। इससे पहले आज तक गवर्नरज ऐड्रेस पर उस समय को सबसे ज्यादा समय 13 घंटे 32 मिनट चर्चा के लिए दिया गया था। इस सत्र में 13 घंटे 53 मिनट का समय दिया गया है जोकि सर्वाधिक है। जिसमें से अपोजिशन बैंचेज को 432 मिनट का समय दिया गया और ट्रेजरी बैंचेज को 401 मिनट का समय दिया गया। इसके अतिरिक्त बजट पर भी बोलने का मौका दिया जाएगा।

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker: Hon'ble Member, now, the general discussion on Budget for the year 2000-2001 will take place.

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बजट पर हो रही बहस पर बोलने का समय दिया है। कल माननीय वित्त मंत्री जी ने चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी की नई सरकार का नया बजट पेश किया। जब वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो उस समय वे बहुत निराश थे और उनके साथ साथ ट्रेजरी बैंचिज के सदस्य भी निराश थे। हमें तो यह प्रथा रही है कि जब वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करते हैं तो उनकी पार्टी के सदस्य और सहयोगी पार्टी के सदस्य उनका स्वागत करने के लिए अपने मेजें थपथपाते हैं। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। जब माननीय चौधरी भजन लाल जी ने याद दिलाया जब जाकर इन्होंने मेजें थपथपाई थी, वरना बिल्कुल चुपचाप बैठे थे।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मांगे राम गुप्ता जी ने कहा कि सरकारी पक्ष के सदस्य निराग बैसे थे। इसमे निराग की कौन सी बात थी क्योंकि जब बजट पे आ होना होता है उससे पहले किसी सदस्य को यह मालूम नहीं होता कि बजट में क्या है। क्योंकि यह तो सिक्रेट डोक्यूमेंट होता है उसके लिए पहले से थंपिंग कैसे कर सकते हैं Even every announcement was appreciated and welcomed by you people also. जब पार्टी की कंट्रीब्यूशन की कोई बात होगी तो उस वक्त जरूर थंपिंग करेंगे। पढते वक्त जब माननीय सदस्यो को पता लगा कि यह तो बढिया बजट है तभी इन्होने बजट का वैलकम करना भुरु कर दिया था। इसके लिए हर पार्टी की तरफ से स्वागत किया गया। चौधरी भजन लाल जी ने भी लते समय यह कहा था कि बहुत बढिया बजट पे आ किया गया है।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मै तो अभी भी कहता हूं कि सरकार ऐसे जितने अच्छे काम करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे ताकि हमें जल्दी मौका मिल सके। अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी काफी पुराने और सीनियर सदस्य है और काबिल भी है। लेकिन आप जानते है कि जब वित्त मंत्री जी बजट पढने के लिए सदन मे खडे होते है तो सभी सदस्य तीन मिनट तक मेजे थपथपाते रहते है चाहे पार्लियामेंट हो या राज्य की विधान सभा हो। लेकिन कल वित्त मंत्री जी इस सदन मे बजट ऐसे पढ रहे थे जैसे किसी गांव के चौक पर खडे होकर भाशण दे रहे हो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। इन्होंने थंपिंग इसलिए नहीं की क्योंकि यह बजट ओपन बजट नहीं था बल्कि सीक्रेट बजट था और इसके बारे में किसी को पता नहीं था।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय ने ठीक फरमाया था कि यह बजट सिक्रेट बजट था और लोगों को इसके बारे में पहले पता नहीं था। लेकिन पिछले कई सालों से इस सदन की ऐसी प्रथा हो गई थी कि जिस दिन वित्त मंत्री महोदय का बजट पेश होता था उस दिन इस हाउस में हरियाणा के लोगों को यह बजट दिखाने के लिए टी0 वी0 सैट लगाए जाते थे। परंतु कल मुख्य महोदय ने इसका इंतजाम नहीं करवाया क्योंकि इस बजट में हरियाणा के लोगों के लिए कुछ रखा ही नहीं गया और हरियाणा के लोग यदि इस बजट को देखते तो सरकार को गालियां देते। वित्त मंत्री ने दिल से हमें बात कह डाली कि हमने पहली बार बजट को वेब साइट पर दिखाने के लिए सी0 डी0 तैयार की है जिसमें से एक सी0 डी0 मुख्य मंत्री महोदय को दी जाएगी और एक स्पीकर महोदय को दी जाएगी और तीसरी सी0 डी0 विरोधी पक्ष के नेता को दी जाएगी। ये कम्प्यूटर पर उस सी0 डी0 को देख ले उसमें आम जनता के लिए कुछ बजट नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चुनावों की बात तो नहीं करता लेकिन चुनावों से पहले व्यापारी वर्ग को इस सरकार ने बड़ी उम्मीदें थी कि यह सरकार उनको कुछ रियायतें देगी गवर्नरज़ ऐड्रेस पर पेश हुए धन्यवाद

प्रस्ताव पर बोलते हुए इन्होंने हरिजनो की कन्याओ को दी जाने वाली सुविधाओ की बात की लेकिन हरियाणा का किसान बडा निरा ा था, उन किसानो को मुख्य मंत्री महोदय ने एक बात कह रखी थी कि जो बी० जे० पी० वाले मेरे साथ काम कर रहे है वे मुझे अच्छी तरह से काम नही करने देते इसलिए मैने चुनाव करवाए है और अब की बार मै ये कांटा निकाल दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप ये बातें पहले भी बोल चुके है, आप कृप्या बजट पर बोलें।

श्री चन्द्र भाटिया: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुप्ता जी गलत बात कर रहे है। मुख्य मंत्री महोदय ने कभी इस प्रकार की बात नही की। ये अपनी बात छिपाने की कोि ा ा कर रहे है। विधान सभा मे गलत बात कहना ठीक नही है।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जब कोई सदस्य बजट पर बोल रहा हो तो वह बजट के पैसे की बात कर सकता है, कानून और व्यवस्था की बात कर सकता है और विकास की बात कर सकता है।

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये विकास की बात करे इनको कौन रोकता है?

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने तो तीन सी० डी० दी है,

एक मुझे भी दी है और एक आपको भी दी है क्या इसमें बजट की सीक्रेसी लीक नहीं हो जाएगी।

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ऐसे तो यह बजट टाइप भी हुआ है और प्रिंट भी हुआ है। (गोर)। अध्यक्ष महोदय, 9:30 बजे से पहले कहीं पर भी इस बजट की कोई भनक लगी हो, इसका एक भाब्द, एक लाईन या एक भी आंकड़ लीक हुआ तो हम उसके लिए जिम्मेवारी है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) (गोर)

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय की बात से सहमत होता हूं कि इस बजट की कोई सीक्रेसी लीक नहीं हुई। जो बात मानने वाली है मैं उसको मानता हूं लेकिन ये जो तीन सी० डी० दी गई है इनका क्या महत्व है। यह जो ओपन बजट पे 1 हुआ है। यह बजट हमारे हाथ में भी आ गया है, सी० डी० में देख लें, किताब में पढ़ ले इसमें जनता को विशेष कर हरियाणा के किसान को जिनको उम्मीद थी कि यह जो औम प्रका 1 चौटाला जी की सरकार बनी है अपने बजट अधिवेशन में उनको कोई विशेष पैकेज देगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया है और इसी कारण से इस बजट को टी० वी० 10:00 बजे पर दिखाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। क्योंकि बजट में दिखाने को कुछ है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा छोटी सी स्टेट है और मौजूदा सरकार ने 294.56 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है और वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने

कोई कर नहीं लगाया। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ओर कितना कर लगायेंगे ये तो लक्की है कि इंटर स्टेटस में एक समान कर प्रणाली भी इन्हीं की सरकार के समय में लागू हो गई। कांग्रेस की सरकार में जब नरसिम्हा राव जी दे 1 के प्रधान मंत्री थे, उस समय हमने यह प्रपोजल रखा था और इस बारे में हमारी एक नहीं 10 मीटिंग हुई थी। लेकिन मौजूदा सरकार इस बात के लिए लक्की है कि यह स्कीम इनकी सरकार के समय में लागू हो गई और एक समान कर प्रणाली लागू होने से सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा के अंदर 75 करोड़ रुपये टैक्स लगे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रणाली के लागू होने से 75 करोड़ ही नहीं बल्कि 150 करोड़ रुपये टैक्स लगे हैं।

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक समान कर प्रणाली के अंदर हमने तीन चीजों को नहीं लिया। फर्टीलाइजर, डीवीजन, पैस्टीसाइड और इनसैक्टीसाइड के ऊपर हमारी सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाये। क्योंकि ये तीनों ही चीजें किसान से संबंधित हैं। अगर हम इन पर भी एक समान कर प्रणाली के तहत टैक्स बढ़ा देते तो जरूर हमें 150 करोड़ रुपये का फायदा होता। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों की तरफ देखते हुए, इनके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया। (विधन एवं भाोर)

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी यह तो मान रहे हैं कि 75 करोड़ रुपये का फायदा इनको हुआ है

लेकिन 75 करोड रुपये के जो ये टैक्स इनको लगे हुए मिल गये इनको ये नये टैक्स के रुप मे बताना नही चाहते ।

श्री संपत सिंह: स्पीकर सर, ये टैक्स तो एक्सपैक्टिड थे । ये तो गैप को मीट-आउट करने के लिए किये गये है ।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपैक्टिड नही है, जिन वस्तुओ पर 0% टैक्स था उन पर 4% हो गया है । जिन पर 2% था उन पर 6% हो गया है और मौजूदा सरकार ने 1 जनवरी से ये लागू कर दिये ।

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रकाश चौटाला): स्पीकर साहब, ये टैक्स तो जरूरत पडने पर घटाये या बढाये जा सकते है । अभी तो सभी स्टेट्स के हिसाब से हमने भी कर दिया ।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन्होने वे टैक्स कम तो नही किये । इनसे इनको 75 करोड रुपये का फायदा हुआ है और उसे दारिद्र्य भी नही चाहते । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार को जो सबसे बडा फायदा हुआ वह यह है कि चौधरी बंसी लाल जी ने भाराब बंदी के नाम पर अपनी सरकार बनाई थी और हरियाणा मे भाराब बंदी भी कर दी थी । भाराब बंदी के नाम पर हरियाणा की जनता पर इन्होने 800 करोड के नये टैक्स लगाये थे और भाराब बंदी करने से एक वर्ष मे 800 करोड रुपये का स्टेट राजस्व घाटा होता रहा । चौधरी बंसी लाल जी ने 2 साल तक हरियाणा में भाराब बंदी रखी । जिसके कारण

दो साल मे हरियाणा स्टेट का राजस्व घाटा 1600 करोड रुपये का हो गया। हरियाणा स्टेट की हद पीट गई। विकास कार्य बंद हो गये और मजबूर होकर बंसी लाल जी ने दो साल बाद भाराब खोल दी और भाराब खोलने के बाद जो टैक्स भाराब बंदी के समय 800 करोड रुपये गाये थे वे वापिस भी नहीं लिये। चौधरी संपत सिंह जी तो 800 करोड रुपये के टैक्स ही बताते थे लेकिन चौधरी बंसी लाल जी ने 300 करोड माना था। उस समय संपत जी यह कहते थे कि जो टैक्स जनता पर भाराब बंदी के समय लगाये थे ये अब वापिस लिये जायें। लेकिन अब इनकी सरकार है, फिर भी इन्होने वे टैक्स विदड़ा नहीं किए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्स बंसी ला जी ने भाराब बंदी के नाम पर लगाये थे चाहे वे 300 करोड के थे या 800 करोड के थे, उन्हे ये विदड़ा करें। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चौधरी बंसी लाल जी ने अपनी सरकार के समय मे हुडडा के प्लाट्स बंद करके उनकी रजिस्ट्री-कंविंस डीड लागू कर दी थी। जिससे हुडडा का 200 करोड रुपये का रैवेन्यू बढ गया था। लेकिन हुडडा के प्लाट्स बिकने बंद हो गये और उन्होने दोबारा से ट्रांसफर करने भुरु कर दिये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चौटाला साहब की सरकार ने भी फिर से हुडडा के प्लाट्स की रजिस्टरी कंविंसड डीड 8 तारीख से भुरु कर दी। जिससे हुडडा का 200 करोड रुपये का रैवेन्यू सालाना बढेगा और ये भाई कह रहे है कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाये। टैक्स रहित बजट पे । किया है। अध्यक्ष

महोदय, जहां तक मेरा ख्याल है चौधरी संपत सिंह जी ने तो पहली बार ही बजट पे 1 किया है लेकिन हरियाणा सरकार के इतिहास मे सबसे ज्यादा बजट मैने पे 1 किये है। लगातार पांच बजट बल्कि छटा बजट भी मैने पे 1 किया था। 1996 मे जब हम सरकार छोडकर गये थे तो 1996-97 का बजट भी हमने पे 1 किया था। अध्यक्ष महोदय यह बात मै इसलिये कह रहा हूं कि क्योकि हमने जो बजट पे 1 किये उन मे कोई टैक्स नही लगाये बल्कि कई टैक्सो को खत्म किया या कम किया। हां, चुंगी हम समाप्त नही कर सके, इन्होने समाप्त की है उसके लिये तो मै इनको धन्यवाद देता हूं लेकिन बैरियर हमने खत्म किये जो बहुत बडी लानत थी। ट्रांसपोटरो और व्यापारियो को बडी दिक्कत आती थी। बैरियर खत्म होने के बावजूद भी हमने सरकार को घाटे मे नही रहने दिया। 1996-97 के बजट मे हम कोई घाटा छोड कर नही गये थे। जहां तक मेरा अंदाजा है हम 31 मार्च तक 500 करोड रुपया छोडकर गये थे जो कि नई सरकार के काम मे आना था। यह पैसा रिजर्व बैंक और कुछ दूसरे बैंको मे हम जमा कर के गये थे। अध्यक्ष महोदय बडे ही दुःख की बात है कि इस छोटी सी हरियाणा स्टेट के उपर 14418 करोड रुपये का ऋण हो जाएगा जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कैलकुलेट करके अपनी स्पीच मे कहा है। इस तरह से हरियाणा के बजट का 30% या 31% हिस्सा तो ब्याज के रुप मे इस कर्ज के उपर चला जाया करेगा। अध्यक्ष महोदय, 1996 मे हरियाणा बना था और जहां तक मुझे याद है कि जब 1991 से 1996 तक हमारी सरकार रही तब तक यानि 30 साल

मे वलर्ड बैंक या दूसरी स्टेटो अथवा संस्थाओ से केवल 6000 करोड रुपये के ऋण हरियाणा सरकार ने लिये थे लेकिन 1996 से 2000 तक की सरकारो की नाकामयाबी की वजह से ये कर्जे 14418 करोड रुपये तक पहुंच गये। अध्यक्ष महोदय, हमारी समझ मे नही आता कि ये इतने बडे कर्जे की कि तें कहां से देंगे क्योंकि नये टैक्स लगा नही सकते और अनाव यक आमदनी के जो सोर्सिज थो, वे सब ये लगा चुके है। सडके पक्की करानी हो तो ये वलर्ड बैंक से लोन लेते थे, बिजली के सुधारीकरण के लिये भी लोन लेते है। सरकार लोन लेकर ही काम कर रही है। मै पूछना चाहता हूं कि सरकार अपने साधनो से क्या काम कर रही है। सोचने का विशय यही है कि आपने इस विशय पर विचार क्यों नही किया है। जब आप बजट भाशण पढ रहे थे तो उस वक्त जब चुंगी को खत्म करने वाला प्वायंट आया था तो आपने मुझे टोका था कि गुप्ता जी आप सो तो नही रहे। मैने कहा था कि मै सो नही रहा बल्कि आपके बजट को गहराई से देख रहा हूं। (विघ्न) आपने अपने बजट मे मंडी व्यापार को बढावा देने के लिए जनवरी, 2000 से 21 वस्तुओ पर मार्किट भुल्क दो प्रति ात से घटा कर एक प्रति ात कर दिया। इसका उल्लेख तो आपने अपने बजट भाशण में किया है लेकिन रुरल डिवैल्पमेंट फण्ड का जो एच0 आर0 डी0 एफ0 का पैसा माफ किया था, उसकी चर्चा आपने इस बजट मे नही की। उस पैसे को आप कहां पर खा गए, या उसका उल्लेख करना भूल गए, यह तो आप जाने। लोगो को दिखाने के नाम पर तो आपने 21 चीजो पर सैस कम करे। सरकार कह रही

है कि पिछले साल सैस कम करने के कारण इस मद के तहत 100 करोड़ रुपये की इनकम हुई जबकि दूसरी तरफ कह रही है कि अगले साल इस मद के तहत 130 करोड़ रुपये आने की संभावना है। मैं पूछना चाहता हूँ जब आपने सैस कम कर दिया तो फिर आपकी आमदनी इस मद के तहत कैसे बढ़ेगी? (विघ्न) जो बात मैंने कही है उस हिसाब से आप देख लें कि आपने सैस खत्म किया है या नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री जी का चुंगी समाप्त करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अध्ययन से सदन के नोटिस में लाना चाहूँगा कि इन्होंने चुंगी क्या समाप्त की साथ ही साथ कई कमेटीज भी समाप्त कर दी। अब जो हमारी 54 कमेटीज रही है उनके लिए सरकार ने 23.84 करोड़ रुपये की ऐड देने की बात कही है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि इतनी कम राशि से कमेटीज का क्या भला होगा और क्या वे जनकल्याण के कार्य कर पाएंगी? कमेटीज के जो कर्मचारी हैं उनको पिछले तकरीबन 3-3 महीनों से पे भी नहीं मिल पाई है। चौधरी बंसी लाल जी ने अपने समय में एक बहुत अच्छा काम किया कि इनके वक्त में जब सफाई कर्मचारियों ने हडताल की थी तो इन्होंने उन सब को ठिकाने लगा दिया था। उस वक्त में वे कर्मचारी ऐसे ठिकाने लगाये गये कि अब वे आपके समय में हडताल करने लायक रहे ही नहीं।

श्री औम प्रकाश चौटाला: गुप्ता जी, हमने तो जो कर्मचारी बंसी लाल जी के वक्त में हटाए गए थे उन सब को

दुबारा नौकरी मे ले लिया है और इनके अलावा नये कर्मचारी भी लगाये है ।

श्री मांगे राम गुप्ता: आपकी बात हम मान लेते है लेकिन कर्मचारी कमेटीज़ मे काम कर रहे है उनको आप पे भी दिलवाने का प्रबंध करें। आज उनको 3-3 महीने से पे नही मिल पा रही है। अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण मे व्यापारियो को राहत देते हुए फार्म 14-15 जो खत्म किया गया है उसके लिए मै वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस बारे में मै सरकार के नोटिस मे लाना चाहूंगा कि ये फार्म तो जब हमारी सरकार थी उस वक्त खत्म किए गये थे। बाद मे जब बंसी लाल जी मुख्य मंत्री बने तो इन्होने फिर से उनको लगा दिया था। अब आपने उनको दुबारा से हटा दिया इसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हू।

अध्यक्ष महोदय, मै इस बात को समझता हूं कि सरकार के पास जितने रिसोर्सिज़ होंगे उतना ही बजट अलाट करेगी उससे ज्यादा बजट कहां से करेगी बजट स्पीच के पेज नं0 6 पर देखिये कि ग्रामीण विकास की मद मे कितना पैसा रखा गया है? अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा प्रदे 1 की 80% जनता गावों मे रहती है इसलिए उसका विकास सबसे ज्यादा होना चाहिए। हमारे गांव बहुत पिछडे हुए है लेकिन उनके लिए वित्त मंत्री जी ने 35.10 करोड रुपये की राशि 1 की अलाटमेंट का प्रावधान रखा है। मै वित्त मंत्री जी के ध्यान मे लाना चाहूंगा कि क्या इतनी राशि 1 से

गावो का विकास हो पाएगा? (विधन) वित्त मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि गावो के विकास के लिए और अधिक राशि का प्रावधान करना चाहिए। इसी प्रकार से आपने हरियाणा के हरिजन कल्याण निगम के लिए भी बहुत थोड़ी राशि का प्रावधान किया है।

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मांगेराम गुप्ता जी से यह कहना चाहूंगा कि एच0 आर0 डी0 एफ0 का पैसा कहां जाएगा वह पैसा भी उपलब्ध है जो कि गावों के लिए विकास कार्यों पर खर्च किया जाना है। इसी तरह से सडको के विकास के लिए जो पैसा रखा है उसमें रुरल डिवैल्पमेंट पर भी खर्च होना है। गावो के लिए अगर सडके ही नहीं बनाएंगे तो वहां पर विकास कार्य कैसे होंगे बिना सडको के गावो की तरक्की कैसे होगी। (विधन)

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में हरिजनो के करीब 12 हजार परिवार हैं और उनके लिए 37.23 करोड रुपये अलाट करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग कल्याण निगम है और अल्पसंख्यक वर्ग भी इसमें शामिल है और कमजोर वर्ग के लोग तथा माईनारिटीज़ के लोग भी इसमें शामिल हैं उन सबके लिए आपने 6.50 करोड रुपये का प्रावधान बजट में रखा है जो कि उंट के मुंह में जीरा है।

श्री संपत सिंह: मांगे राम जी, आप तो खुद भयाने आदमी हो और वित्त मंत्री बने हुए हो फिर भी इस किस्म की

बावली बात क्यों करते हैं। आपको तो इस बारे में खुद ही पता है।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार गावों के विकास के लिए पैसा दे रही है लेकिन हमारे समय में हमने हर एम0 एल0 ए0 को चाहे वह रुलिंग पार्टी से हो, यहाँ अपोजीटिव पार्टी से हो, विशेष ग्रांट विकास कार्यों के लिए दी थी। वह ग्रांट इसलिए दी थी क्योंकि हर एम0 एल0 ए0 का अपने क्षेत्र के बड़ा भारी लिंक रहता है क्योंकि वह गांव में जाता था और गांव की गलियों में घूमता था। चुनाव के समय आपने खुद भी गावों में जाकर देख लिया होगा कि वहाँ पर कितना बुरी हालत है। गोड़े गोड़े तक गावों में कीचड़ होता है जिसके कारण गांव की गलियों में घुसना मुश्किल हो जाता है। (विधन)

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, माननीय मांगे राम जी एक गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं (विधन एवं भाोर) चौधरी भजन लाल जी अगर आपके टाईम में ऐसी बात न हुई हो तो आप बताएं। मैं तो आपके टाईम का भी भुक्तभोगी हूँ। (विधन एवं भाोर)

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चौधरी भजन लाल जी को याद दिलाना चाहूँगा कि इनके समय में भी हम लोगों के खिलाफ 3-3 प्रिविलेज मोशनज थे। मेरे खिलाफ

तीन-तीन प्रिविलैज कमेटी मे मामले टोक रखे थे। इनको याद होगा कि जब मै बोलता था तो चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री होते हुए खुद 100 से ज्यादा बार इन्टरवीन किया करते थे। इनको भी याद होगा, प्रैस के लोग भी यहां पर बैठे हुए है और दूसरे लोग भी यहां पर बैठे हुए है, मिनिस्टर की बात तो छोडिए ये खुद मुझे इन्टरवीन किया करते थे। (विघ्न एवं भाोर)

श्री धीरपाल सिंह: चौधरी भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे और उस वक्त प्रो० सम्पत सिंह जी किसी बहस पर चर्चा करते हुए बोल रहे थे। उस दिन चौधरी टेक चन्द की 13वीं थी, मै मुंडाल से आया था। यहां पर आया तो मैने देखा कि सम्पत सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया तो मैने कहा कि इनको किस बात के लिए सस्पेंड किया गया है तो मुझे यह कहा गया कि आपको भी नेम किया जाता है। यह रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने बोलने हुए कहा कि हुडडा के द्वारा रजिस्ट्री मे हमारी वर्तमान सरकार को दो सौ करोड रुपए का इजाफा होगा। प्लॉट होल्डर को चार ट्रांसफर फी है। सर, सरकारी दस्तावेज मे दर्शाया गया है कि 1998-99 मे रहन के द्वारा, नगरपालिका के द्वारा और एग्रीकल्चर लैण्ड से 294 करोड रुपए की इन्कम प्राप्त हुई। 1999-2000 मे एस्टीमेट 408 का था और प्रति 360 करोड रुप की हुई थी। 2001 के लिए 405 करोड का एस्टीमेट है। इन्होने 200 करोड इसलिए कहा है क्योकि यह फर्जी

बात है। मैंने यह बात सरकारी दस्तोज से हाउस के सामने रखी है।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, धीरपाल जी बहुत ही सीनियर मैम्बर है। आप स्पीकर के पद पर नए आए हैं जैसे आपको सदन का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपके माध्यम से इनको यह कहना चाहता हूँ कि जब कोई मैम्बर बोल रहा हो तो मंत्री महोदय, को प्वायंट नोट कर लेने चाहिए और जब जवाब दे तो उसके बारे में बोल लें।

श्री धीरपाल सिंह: चौधरी साहब इन्होंने एक बात कही थी मैंने उसका सरकारी दस्तावेज से जवाब दिया है बाकी के प्वायंट हम नोट कर रहे हैं।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्लाट के बारे में ट्रांसफर की बात कही है। बाद में आपने कह दिया कि ट्रांसफर नहीं होगी। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि इमीजिएट इफैक्ट से तो आप कर सकते हो लेकिन रिट्रासपैक्टिव इफैक्ट से नहीं कर सकते। आप इस बारे में विचार कर लें। लोगो में बहुत रोश है। उन्होंने मुझे लिखकर दिया है।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यहां पर जो गवर्नर एड्रेस पढा गया है वह सरकार की अर्थैटिक स्पीच होती है। उसको मददेनजर रखते हुए बजट बनाना चाहिए। कृषि में आपने गन्ने की बिजाई

पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि यह लाभदायक फसल है। यह भी कहा है कि फलो और सब्जियों की खेती ज्यादा करे उससे किसान को ज्यादा लाभ मिलेगा। यह नीति आपने द टाई है। आप गवर्नर एंड्रेस पेज नम्बर 14 पर देखें। उचानी गांव करनाल के पास है। उसमें एक बागवानी प्र शिक्षण संस्थान बनाया जाएगा जो बेमौसमी सब्जियों और फलों की पैदावार के लिए ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह संस्थान 12.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है लेकिन बजट में इस बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अमाउंट सरकार उसके लिए खर्च करने जा रही है इसलिए इसका किसी न किसी हैड में वित्त मंत्री जी को अपनी बजट स्पीच में भाग देना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यह 12.50 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है जब इसका ही बजट में जिक्र नहीं होगी तो फिर इस बजट को बनाने का क्या लाभ है? इसी तरह से मछली उत्पादन के बारे में गवर्नर एंड्रेस में तो चर्चा की गयी है कि उसका रिकार्ड उत्पादन हुआ है लेकिन बजट में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। बजट में वित्त मंत्री जी ने इस चीज को कहीं पर भी टच ही नहीं किया है। इस बारे में कोई फंड अलोट ही नहीं हुए हैं। इसी तरह से ऐनीमल हसबैंड्री की बात है। हरियाणा के किसानों के लिए पशुपालन आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसको बढ़ा देने के लिए गवर्नर एंड्रेस में तो कहा गया लेकिन बजट में इस बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। अध्यक्ष महोदय, मै टाईम का ध्यान रखते हुए ज्यादा

नही कहना चाहूंगा। साथ ही मुझे अपनी बीमारी के हिसाब से कम ही बोलना पड़ता है। जब सरकार ने अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट बहाल की थी तो मैंने मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद किया था। वित्त मंत्री जी का या भायद मुख्य मंत्री जी का कही पर भाषण था कि हमने इस कालेज की ग्रांट जो चौधरी बंसी लाल जी से सम में बंद रही थी, को खोला है। चौधरी बंसी लाल जी ने तो लोगों की कचहरी में खड़े होकर देख लिया लेकिन इनको केवल दो ही सीट मिली है। खुद तो ये पता नहीं कैसे लोगों की खुद मद करके एम0 एल0 ए0 बन गये हैं। (विधन) जब हम 60 एम0 एल0 ए0 हैं। इनका दूसरा एम0 एल0 ए0 तो ***** ही बनकर आया है।

श्री अध्यक्ष: यह भाव कार्यवाही से निकाल दिया जाए।
(विधन)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, वह फौजी अफसर है और अपनी मेहनत से चुनाव जीतकर आया है।

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, जो ने नल पार्टी है उसके तो केवल 21 ही एम0 एल0 ए0 हैं जबकि हमारी रीजनल पार्टी होते हुए भी दो एम0 एल0 ए0 हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता: जो उस कालेज को 7 करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई थी वह तो चौधरी बंसी लाल जी के समय के ड्यू बनते थे क्योंकि हमने तो उस कालेज की कोई ग्रांट बंद नहीं

की थी। मुख्यमंत्री जी ने कल इस बारे में एक चिट्ठी भी यहां पर पढ़कर सुनाई थी। वह रिकार्ड है जो कि आज मौजूद है। उस समय युनानीमसली बोर्ड की तवज्जो पर एक रास्ता निकाला गया था, सरकार के खर्च घटाने का और उस मैडीकल कालेज को लाभ पहुंचाने का, परंतु ग्रांट हमारे समय में बंद नहीं हुई है। हम तो 2 करोड़ रुपये चौधरी बंसी लाल जी के समय के लिए अपने बजट में रखकर गये थे। आपने जिस ग्रांट की घोषणा की वह तो चौधरी बंसी लाल जी के समय की बनती थी। (विघ्न) चौधरी बंसी लाल जी के इन कारनामों की वजह से ही लोगों ने वह सरकार बना दी नहीं तो इनकी सरकार कौन बनाता था।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांगे राम जी से जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकार किसके कारनामों से बनी थी?

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, हमारे कारनामों से नहीं बनी थी बल्कि आपने जनता के साथ धोखा करके झूठे वायदे करके वह सरकार बनायी थी।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, 24 जुलाई 1999 को जो चौटाला साहब के नेतृत्व में सरकार बनी थी वह कांग्रेस और हरियाणा विकास पार्टी दोनों के कारनामों से बनी थी और जो हमारी सरकार बनी है वह हमने जो अपने पिछले सात महीनों में काम किए हैं, उनके पोजिटिव अचिवमेंट से बनी है।

श्री भुपेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि इनकी सरकार क्यों बनी? अंग्रेजों के समय की बात सुना रहा हूँ ध्यान से सुनो। सांपला में एक जिलेदार था उसकी जिम्मेदारी तुड़वा दी। सांपला के सेठ का उसके साथ झगडा हो गया तो सेठों ने मुकदमा कर दिया और जिलेदार ने भी कोर्ट केस कर दिया। जिलेदार कोर्ट में जीत गया और जीतने के बाद सेठ के घर डांग खडका दी कि मैं कोर्ट से जीतकर आया हूँ तो सेठ ने कहा कि तू अपने कर्मों से जीतकर नहीं आया बल्कि हमारे कुछ कर्म माडे थे जिनकी वजह से जीतकर आया है सो आपका वही हाल है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के कुछ माडे कर्म बाकी थे जिनकी वजह से आप जीतकर आ गए।

श्री मांगे राम गुपता: अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को मेरा सुझाव है। इनकी पार्टी की तरफ से जितने माननीय सदस्य बोले सभी ने अग्रोहा मैडीकल कालेज के बारे में खुब दबदबा मचाया। मैं भी इनका धन्यवाद करता यदि इन्होंने जो सात करोड रुपये जारी करने की घोशणा की थी, उस राशि को रिलीज कर देते। सात करोड में से आपने एक करोड रुपया रिलीज किया है यह उनके साथ बहुत बडा धोखा है आप इस 31 मार्च तक उनका बकाया 6 करोड रुपया रिलीज करें। अगर आप समाज की वाहवाही लेना चाहते हैं तो यह राशि भी रिलीज कर दें।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मांगे राम जी तो वित्त मंत्री थे इनके अलावा इनकी पार्टी के सारे सदस्यगण जो उधर बैठे हैं, सारे जानते हैं कि जो सात करोड़ रुपये आप ड्यू बता रहे हैं इसमें रैकरिंग और नाने रैकरिंग दोनों चीजें मिलकर शामिल होती हैं जहां तक तनखाहो का सवाल है तो उसका तो 50 लाख रुपया बकाय था और वह 50 का 50 लाख तुरंत रिलीज कर दिया था ताकि तनखाहें बकाया न रह जाए। दूसरे जो निर्माण कार्यों पर पैसा खर्च होता है उसके लिए कोई एक मु त रकम जमा नहीं कराई जाती। आज जैसे बजट में प्रोजेक्ट रखे हैं हर मद में रखे हैं क्या यह सारा का सारा पैसा एक साथ रिलीज कर दिया जाएगा? वह तो जैसे जैसे निर्माण का कार्य गति पर आएगा। पी0 डबल्यू0 डी0 (बी0 एण्ड0 आर0) और सोसायटी मिलकर काम कर रही है। किसी वर्क को हम पैडिंग नहीं रहने देंगे और काम होने का साथ साथ पैसा मिलेगा। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश भार्गवा जी, मोबाइल फोन हाउस में लाने की अनुमति नहीं है आप मोबाइल फोन यहां लेकर न आया करें।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो पैसा है ग्रांट जो मिलनी थी उसके न मिलने के कारण सोसायटी जिसके अंदर मैं पैट्रन हूं, जिंदल साहब भी हैं चीफ मिनिस्टर साहब और चौधरी देवी लाल जी भी पैट्रन हैं। स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले बताया कि सोसायटी तो पैसा इकट्ठा

करके खर्च करती रही। गवर्नमेंट ने खर्च किया नहीं, हम भी भागमिल थे। बकायदा मिटिंग करते रहे और यहां तक की विरोध करते रहे। विरोध के लिए सोसायटी ने चौटाला सहब को बुलाया था उसके लिए एक महीना पहले ही टाइम निश्चित किया था और 25 जुलाई का टाइम निश्चित किया हुआ था। यह बात अलग है कि पहले उनको विपक्ष के नेता के रूप में बुलाया था लेकिन परमात्मा की करनी थी कि वे वहां विपक्ष के नेता के रूप में नहीं बल्कि मुख्य मंत्री के रूप में गए और मुख्य मंत्री जी ने जाते ही कह दिया कि पिछले दो साल से जो काम बंद पड़े हैं उसे चालू करवाइए। उस जमीन पर जाने से पहले ही चौटाला साहब को मुख्य मंत्री का पद दिला दिया और 25 तारीख को जाते ही उन्होंने अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट को बहाल करने के आदेश दे दिए और जितना पैसा बनता था रिलीज हो गया है और ज्यों ज्यों एल0 ओ0 सी0 की डिमाण्ड आती जाएगी पैसा रिलीज होता रहेगा।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी को बहुत इंटेलिजेंट समझता था। ये कह रहे हैं कि सरकार अग्रोहा मैडिकल का एक पैसा भी बाकी नहीं रखेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार ने पहले यह कहा था कि हम अग्रोहा मैडिकल कालेज को सात करोड़ रुपया देंगे। मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बजट पे किया है क्या उस

बजट मे इन सात करोड रुपयो को रिलीज करने का कोई प्रावधान है?

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, श्री मांगे राम गुप्ता जी ने बजट को अच्छी तरह से पढा नहीं है वरना ये इस बात को नहीं कहते ।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, कहने को तो हर कोई कह सकता है कि हम यह देंगे और वह देगे । लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री महोदय यह जानते है कि महाराजा अग्रसेन के आर्िवाद से यह सरकार बनी है और चौधरी औम प्रका । चौटाला जी का इलाका भी वहां पर पडता है, चौधरी संपत सिंह का इलाका भी वहां पर पडता है और चौधरी देवी लाल जी ने ही उस कालेज के लिए जमीन दी थी । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अग्रोहा मैडिकल कालेज की 6 करोड रुपये की ग्रांट को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाये । अध्यक्ष महोदय, जहां तक सडको का सवाल है सडके तो यह सरकार बना ही देगी क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लोन जो ले रखा है । बिजली की सुविधा देने के लिए भी यह सरकार जरूर कुछ करेगी क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है । बजट मे ऐसा कहा गया कि स्कूलो को ज्यादा खोला जायेगा जिससे िाक्षा मे सुधार हो, अस्पताल ज्यादा बनवाएं जाएंगे । अध्यक्ष महोदय, आमदनी के लिए सबसे ज्यादा जरुरी है कि आदमी अपनी सुरक्षा, अपनी इज्जत को ठीक ढंग से बचा

सके। जब आदमी का घर से बाहर निकलना ही दुभर हो जाये, सडक पर जाते हुए यह लगे कि कही कोई किडनैप न कर ले तो इस हालात मे आदमी अपने आपको सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है? ऐसी हालत मे सरकार की नाकामी समझी जाती है और सरकार की बदनामी भी होती है। अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी ने भाराब बंदी के समय एक बडे माफिया गिरोह का जिक्र किया जिसने इस प्रदे 1 मे बडेबडे काइम किए है। इस बात के लिए सभी सदस्य सहमत है। अध्यक्ष महोदय, जब काइम प्रदे 1 मे बढ जाता है तो कही पर लूट-खसोट हो रही है, कही पर चोरी हो रही है, कहीं पर किडनैपिंग हो रही है कही पर मर्डर हो रहा है तो कही पर सरकार का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगो को उनकी सजा से सबक मिल जाये और फिर उस काइम को करने की किसी दूसरे आदमी मे हिम्मत न रहे। क्योंकि हर वक्त तो सरकार किसी भी आदमी की पैरवी नहीं कर सकती कि 24 घण्टे उसके घर पर पुलिस का पहरा दिया जाये। ऐसे पता भी नहीं चलता कि अपराधी किस आदमी को किस समय अपना नि गाना बनायेंगे। इस बात के लिए मैं सदन के सामने एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे हलके के गांव बडा खुर्द जो कि जीन्द से 6 किलोमीटर दूर है दिसम्बर, 1999 को उस गांव के ही किसी अपराधी आदमी ने एक छः साल के बच्चे का किडनैप कर लिया। उस बच्चे के घर वाले सारी रात इधर-उधर ढूंढते रहे लेकिन दूसरे दिन उस गांव के स्कूल के पास उस बच्चे की ला 1 मिली और जिस हालत मे उस बच्चे का मारा गया था उससे ऐसा

अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई अपराधी जगत का ही आदमी ऐसी मौत मार सकता है। उस छोटे से बच्चे की किस के साथ दु मनी हो सकती है। क्या उस बच्चे का मर्डर जाति दु मनी के कारण हुआ। जो मर्डर जाति दु मनी की वजह से होते हैं उनकी डिक्लेयरेशन हो जाती है कि फलां आदमी को मैंने मार दिया। उस गांव के लोग दे 1 के प्रधानमंत्री से मिले और यहां के मुख्य मंत्री से मिले। लेकिन तीन महीने होने जा रहे हैं आज तक यह सरकार उस 6 महीने के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जब तक ऐसी हालत रहेगी तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, लड़कियां कालेज कैसे जाएंगी, व्यापारियों का काम कैसे चलेगा? दुकानों के कब्जे होना, किडनैपिंग जैसे इन्सिडेंट हो जाते हैं लेकिन ऐसे काम करने वालों को सजा देना इस सरकार की ड्यूटी बनती है। यह सरकार जनता की बनाई हुई है, आपकी सरकार पंजातंत्र की सरकार है मैं आपका विरोधी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपकी सरकार पूरे 5 साल चले। दल बदल बदल कर सरकार तोड़ना ठीक बात नहीं है। हमारे लिए आपस में एक दूसरी सरकार की बुराई करना ठीक बात नहीं है। पंजातंत्र की जो सरकार बनी है हमें उससे खुशी है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों के हित की बात करती है। मैं वित्त मंत्री महोदय को एक बात कहूंगा कि वे मुख्य मंत्री महोदय से एक काम करवाएं कि किसानों की तरफ जो बिजली के बिल बकाया है उनको माफ कराएं क्योंकि उनमें हरियाणा के किसानों का कोई कसूर नहीं है। इनकी पार्टी के नेताओं ने किसानों को

कहा था कि आप लोग बिजली के बिल मत भरओ और बिल न भरने की वजह से उन किसानों पर कई केस बन गए थे, कुछ को जेल में डाल दिया गया था। ये बातें आज किसानों के गले की हड्डी बन गई है। वे बकाया बिल आज हजारों और लाखों में हो गए हैं इसलिए इन बिलों को माफ किया जाए।

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सम्मानित साथी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने नारा दिया था कि बिजली के बिल न भरओ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये एक बार न्यूज पेपर उठाकर देखें कि सबसे पहले किस की पार्टी के नेता ने यह नारा दिया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की यह स्टेटमेंट आई थी कि हम फ्री बिजली-पानी देंगे। (गोर)

श्री मांगे राम गुप्ता: वह अलग चीज है मैं तो बिलों की बात कर रहा हूँ।

श्री संपत सिंह: हम इस बात को मानते हैं कि वह अलग चीज है।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी का यह ऐलान नहीं था कि बिजली के बिल न भरओ। यह गलत बात है। जिस समय किसान इसके लिए आन्दोलित थे, यह भाई मंत्री बनकर उनकी लाठी के उपर से निकलते थे। उस समय किसकी सरकार थी कौन वजीर थे, यह

इस बारे में बताएं? जब निसिंग में, कादमा में, टोहाना, नारनोंद में और मण्डियाली में दर्जनो किसान मारे गए थे ये कांग्रेस के भाई झंडी वाली गाडियो में घुमते थे और अब ये किसानो के हमदर्द बनते हैं।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये बार बार बीच में जवाब देने खड़े हो जाते हैं, यह ठीक बात नहीं है। इन्होंने किसानो को गुमराह करके बिजली के बिल नहीं भरने दिए और कहा कि जब हमारी सरकार आएगी हम इन बिलो को माफ कर देंगे।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अब ये इन्टरवीन कर रहे हैं।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि लीडर आफ अपोजी इन और मुख्य मंत्री महोदय कही भी इन्टरवीन कर सकते हैं। माननीय साथी गलत बात कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। उस वक्त इन्होंने वोट लेने के लिए हर तरह से किसानो को गुमराह करने का काम किया। अब इनकी सरकार बन गई है इसलिए इनका यह धर्म और फर्ज बनता है कि ये किसानो के बिजली के बिल माफ करें।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वे बकाया बिल जो लाखों में हो गए हैं उनको किसान देने की स्थिति में नहीं है। अध्यक्ष

महोदय, चाहे मौजूदा सरकार उन किसानों के बिजली के कनेक्शन काट दे, चाहे उन्हें उठाकर जेलों में बंद कर दे। लेकिन वे किसान अब बिजली का बिल भरने की हालत में नहीं हैं। अब वे बिजली के पुराने बिल नहीं भर सकते। अध्यक्ष महोदय, जनता ने बड़े विवास के साथ चौटाला साहब की सरकार बनाई है और ये अपने आपको किसान हितैशी बताते हैं। जब ये दूसरे हैड में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो क्या ये किसानों के पुराने बिजली के बिल नहीं माफ कर सकते? अध्यक्ष महोदय, ये मुफ्त बिजली पानी किसानों को दें, मैं इसके हम में नहीं हूँ क्योंकि जब पैसे देने से ही बिजली नहीं मिलती तो मुफ्त में कहां से मिल जाएगी? पंजाब ने अपने किसानों को मुफ्त में बिजली दी है, वहां पर लेने के देने पड़ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों को मुफ्त की बिजली देने से न तो किसानों की भलाई होगी और न ही स्टेट की भलाई होगी। किसी वजह से किसान यूनियन द्वारा गुमराह किये जाने पर किसान बहक गये और उन्होंने उस समय अपने बिजली के बिल नहीं भरे। अब किसान वह बिल भर नहीं सकता और सरकार उसे माफ नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में तो किसानों के गले में हड्डी अटक गई है। अध्यक्ष महोदय, इसका तो एक ही हल है कि मुख्य मंत्री महोदय को किसानों के वे बिल माफ कर देने चाहिए।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मांगे राम गुप्ता जी बहुत ही समझदार हैं। ये जानते हैं कि किसान यूनियन अब भी है

और चौधरी बंसी लाल जी के समय मे भी थी और कांग्रेस की सरकार के समय मे जब चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे, तब भी थी। अब भी किसान युनियन ने यह नारा दे दिया है कि वे बिल नही भरेंगे। हमारी सरकार को बने 8 महीने हो गये है और सभी माननीय सदस्य भी देख रहे है कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। उन किसानो को कैसे नैगोि एट कर रही है। उनसे बात चीत कर रही है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसी लाल जी की सरकार ऐसे समय मे किसानो को लाठियो और गोलियो से जवाब देती थी। स्पीकर साहब, लाठियो और गोलियां चलाने से किसी समस्या का समाधान नही होता। समस्या का समाधान बातचीत करने से होता है और हमारी सरकार भी किसानो के साथ बातचीत कर रही है। पहले की सरकारो की तरह उन पर लाठियां या गोलियां नही चलवा रही। स्पीकर साहब, डिक्टेटरि एप से काम नही चलता। चौधरी बंसी लाल जी तो इस मामले मे भजन लाल जी से भी आगे निकल गये थे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनिता जी, प्लीज आप बैठिये।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, ये लोग किसानो पर गोलिया चलाते रहे, और हम जो किसाना से संबंधित है हम अपने घर मे बैठे रहे, यह कैसे हो सकता था। स्पीकर साहब, उस समय हमने किसानो की लडाई लडी, इनका विरोध किया ताकि और लाठियो व गोलिया न चले। स्पीकर साहब, यह कैसे हो सकता था

कि हम घर बैठे रहते और किसानों का खून सड़को पर बहता रहता और हम दोनों भाई अपने घर में बैठकर मौज करते रहते। हमने उस समय किसानों का पूरा पूरा साथ दिया।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने किसानों की मदद की लेकिन अब तो इनकी सरकार आ गई है। जैसे चौधरी देवी लाल जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ। आज उसी तरह होना चाहिए कि चौटाला साहब कहे कि किसानों के वे बिल माफ। इसमें नैगोशिएशन की क्या बात है? (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मांगे राम जी, आज बजट पर बोलिए।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्री जी हाउस में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कह रहे थे कि प्रदेश के लोगों की जीरी के अच्छे भाव दिये गये। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि किसानों को जीरी का अच्छा भाव नहीं मिला। उनकी दुर्गति हुई। जैसा कि हुड्डा साहब ने भी चर्चा की थी कि वे मंडियों में गये थे। व्यापारी होने के नाते मेरी भी जीरी की दुकान है और जीरी बेचने का अनुभवी है। मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी कल जवाब में कहा कि सरकार ने किसानों से पहली सरकार के मुकाबले छः गुणा ज्यादा जीरी खरीदी और

राजस्थान से भी जीरी आकर हरियाणा की मंडियों में बिकी है। मुख्य मंत्री का यह जवाब था जबकि यहां पर जींद की एक मण्डी का जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश की जींद में भी बहुत बड़ी मंडी है जिसमें किसान मुख्य रूप से पैड़ी की पैदावार लाता है और हमारे टाइम में पूरे सीजन में ढाई लाख रुपये बोरी पैड़ी की खरीद होती थी लेकिन इस बार पूरा सीजन चला गया और पूरे सीजन में सरकार ने सिर्फ एक हजार पैड़ी की बोरी खरीदी। सरकार तो छः गुणा पैड़ी खरीदने की बात करती है यह तो छठा हिस्सा भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी बताएं तो सही कि किसानों को वह भाव कहां मिले है? अध्यक्ष महोदय, बजट में अलॉटमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्या साधन जुटाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों की इन्होंने बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। अब मैं ला एण्ड आर्डर के उपर आता हूँ। ला एण्ड आर्डर की बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बजट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के लिये कोई अलॉटमेंट नहीं की। जिस तरह से गवर्नर साहब की स्पीच में भी जिक्र किया गया है कि पुलिस के लिए और अच्छे हथियार खरीदेंगे, पुलिस की तादात बढ़ायेंगे? यह काम तो सरकार का था। बजट में इन्होंने इस बात को टच ही नहीं किया कि किस हैंड के तहत यह कितने हथियार खरीदेंगे, कितने मकान पुलिस के लिए बनाएंगे, कितनी और रिक्यूटमेंट करेंगे अथवा और क्या सुविधाएं देंगे। काइम रोकने के लिए क्या पैट्रोलिंग होगी? इस डिपार्टमेंट को तो टच भी नहीं किया गया है।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मांगे राम जी भी वित्त मंत्री रहे हैं। इनको सब चीजों का पता है कि सारी बातें विस्तार से बजट स्टेटमेंट में नहीं आती हैं। इनके पास कितने बड़े पोथे हैं जो कि सरकार ने इनको दे रखे हैं, उनको ये पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, अब ये सी० डी० की बात करते हैं वह तो इनकी आसानी के लिए बनाई गई ताकि ये जिस डिपार्टमेंट के जिस हैड को निकालना चाहे, निकाल कर देख सकते हैं। प्लान में निकालना चाहे तो प्लान में देख लें। सरकार ने इसके लिये इतनी सुविधा दे दी है लेकिन ये तो मात्र बजट स्टेटमेंट पढ़कर आ गये हैं, उससे तो बात नहीं बनती। अगर इन्होंने मेहनत की होती, पोथे पड़े होते तो इनको सारी बातों का पता लगता। बजट स्टेटमेंट में तो मोटी मोटी बातें कही जाती हैं। पूरा बजट अगर आज में पढ़ना भुरु करे तो पढ़ते पढ़ते अगला हफ्ता आ जाएगा। पूरी रामायण की तरह यह पोथा है।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यह रैलेवेनट जवाब दें। मैं यह तो नहीं कहता कि सारा पोथा ये पढ़ सकते हैं या फिर सारा पोथा पढ़ें लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे सरकारें चलती हैं उनकी बजट अलाटमेंट का जिक्र तो बजट में आना चाहिए। ऐसे कह देने से तो काम नहीं चलता कि बहुत सारी किताबें भरी पड़ी हैं। भरी पड़ी हैं तो कोई मतलब नहीं होता। रामायण की किताब में भी एक आदमी सारांश में सारी जरूरी बातों को लेता है। इनको मेन

डिपार्टमेंट की बजट अलाटमेंट तो दिखनी चाहिए थी जैसे लॉ एण्ड आर्डर डिपार्टमेंट है, फुड एण्ड सप्लाय डिपार्टमेंट है, फिरीज डिपार्टमेंट है, कृषि या बागवानी डिपार्टमेंट है। सरकार ने इस तरह से कोई भी डिपार्टमेंट टच नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस सरकार के बनने के बाद अपना पहला बजट पेश किया है। यह महकमा कांटो के ताज से भरा हुआ महकमा है। इस विभाग में रहते हुए आप कोई सैर-सपाटा नहीं कर पाएंगे। इस महकमे में बहुत मेहनत के साथ काम करना पड़ता है। जब मैं वित्त मंत्री था तो उस वक्त तकरीबन सारे मंत्री दूसरे देशों की यात्रा कर आये थे लेकिन मैं तो किसी दूसरे देशों में कभी भी नहीं जा पाया था। मैं 5 साल तक वित्त मंत्री रहा और कभी भी एक पैसे का नया टैक्स नहीं लगाया। टैक्स न लगा कर भी हम खजाने में काफी पैसा छोड़कर गए थे। लहमने अपने समय में कभी भी घाटे का बजट पेश नहीं किया। सम्पत सिंह जी आप मेहनत के साथ इस विभाग में काम करें या फिर यह महकमा किसी काबिल व्यक्ति को सौंप दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, आप वाईन्ड अप करें।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खुद माना है कि इस बजट में कुछ कमी रह गई है। मैं आशा करता हूँ कि जो कमियाँ रह गई हैं उनको ये दूर करने की

कोर्णित करेगें। अधुयकुष महोदुय, हमारे मुखुय मंत्री जी अब जीनुद डलसुडुकुट के मुखुय मंत्री हो गये है। ठीक है सलरसा डलसुडुकुट के साथ इनके अपने पुराने पैतृक संबंघ है। वहां पर चीनी मलल और चावल की मलल लगाई जा रही है। हमें इस बात की खुशी है कल उस इलाके के ललए अच्छे काम हो रहे है। आपके माध्यम से मैं मुखुय मंत्री जी के नोटलस मे लाना चाहूंगा कल हमारा जीनुद जीला एक पलछडा हुआ जलला है। (वलघन) मैं इस बात को मानता हूं कल पीछे जींद जलले को जो नुमाइनुदगी रही वह ढीली रही। जींद का जो एक मंत्री रहा उसको बंसी लाल जी भी अपने पास रखने मे लगे रहे लेकलन वह डटा नहीं। बाद मे चौटाला साहब ने उसको डाटने की कोर्णित की लेकलन इनके साथ भी वे नहीं डटे। बाद मे ये कांग्रेस मे आये और वह कांग्रेस में भी नहीं डटा। उसके न डटने से चुनावो मे जींद जलले में कांग्रेस को नुकसान हुआ। मैं सरकार के नोटलस मे लाना चाहता हूं कल जींद जलले मे सीवरेज की हालत बहुत बुरी है। (वलघन) कुछ भाई बैठे बैठे कह रहे है कल जब मैं मंत्री रहा तो मैंने क्या कलया। मैं इन भाईयो की जानकारी के ललए बताना चाहूंगा जब मैं मंत्री था तो उस वक्त मैंने यहां की सीवरेज के ललए एक प्रोजैकुट भुरु करवाया था। उस पर काम करवाने के ललए 4 करोड रुपये भी दलये थे। बाद मे बंसी लाल जी की और चौटाला साहब की सरकार आ गई जलस कारण वह काम बीच में रुक गया। (वलघन)

श्री धीरपाल सिंह: जब इस सरकार ने पीछे सत्ता संभाली तो उस वक्त यह महकमा मेरे पास था। मैंने उस वक्त जींद जिले की कमेटी को 30 लाख रुपये की एड दी थी।

श्री राम कुमार कटवाल: जब मांगे राम जी मंत्री थे तो उस वक्त इन्होंने अग्रोहा मैडिकल कालेज आग्रोहा में खुलने दिया। उसे इन्होंने जींद में क्यों नहीं खुलवाया। ये गलत बात कह रहे हैं कि जब ये लोग सरकार छोड़कर आये थे तो उस वक्त 500 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में था। ऐसी गलत बात कह कर ये सदन को गुमराह न करे। जीन्द जिले का इनके वक्त में ही बुरा हाल हुआ है।

11:00 बजे

श्री अध्यक्ष: मांगे राम जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है आपकी पार्टी के दूसरे लोगों को भी बोलना है। इसलिए आप अपनी बात को समाप्त करें। वैसे तो जितना टाइम आपकी पार्टी का अलॉट हुआ है उतना ही आपको मिलेगा जितना ज्यादा समय आप बोलेंगे यह टाइम आपकी पार्टी के टाइम में से कट जाएगा।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हाउस में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी जनता के लाभ की चीज है वह की जाए,

चाहे वह सीवरेज है, चाहे वह सडक है, चाहे वह होस्पिटल या दूसरी जरूरत की चीजे है वह सब होनी चाहिए। सरकार बनने के बाद जनता को सुविधा देने के लिए सरकार में यह नहीं होना चाहिए कि पिछली सरकार ने यह काम भुरु किया था इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम जींद में राजपुरा गांव में पोलिटैक्नीक कालेज मंजूर करके गए थे वह वर्ल्ड प्रोजैक्ट की स्कीम है और इसके लिए पैसा भी अलाट हुआ पडा है, गांव की 25 एकड जमीन भी सरकार को ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन आज तक वह पोलिटैक्नीक कालेज नहीं बन पाया है। इसका कारण सिर्फ यह है कि यह चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में मंजूर हुआ था। कल मुख्य मंत्री जी जिक्र कर रहे थे कि पत्थर लगे रह गए तो अगर सरकार उन पर काम नहीं करवाएगी तो वे बनेंगे कैसे? अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो चीजे सरकार से सैंकान हो चुकी है चाहे चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में हुई हों, वे सारी चीजे हरियाणा के लोगों के लिये हैं और उन सब को सरकार द्वारा बनवाया जाना चाहिए तथा सारा काम नेक नीयती से करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विवास करता हूं तथा मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्तमान सरकार ठीक चल रही है और यह सरकार सभी को एक नजर से देख कर काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, इन्ही भावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा आपने बोलने के लिए मुझे जो समय

दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बलवन्त सिंह (सढौरा, अनुसूचित जाति): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट इस सदन में पेश किया है उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस सदन में पहली बार मੈम्बर चुन कर आया हूँ इसलिए अगर कोई असंगत बात जाने-अनजाने में मुझ से निकल जाए तो मैं उसके लिए माफी चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस संयत ढंग से तथा सुनियोजित तरीके से बजट तैयार किया है अगर उस पर नजर डाल कद देखा जाए तो यह पता चलता है कि राज्य ने बहुमुखी विकास किया है। उसके वार्षिक प्लान में 2530 करोड रुपये का प्रावधान है जो कि वर्ष 1999-2000 की संशोधित व्यवस्था से 39.50% अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पावर, सिंचाई, सडको और परिवहन के लिए अधिकाधिक प्राथमिकता दी गई है तथा उसके लिए 1632.15 करोड रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जो कुल प्लान व्यवस्था का 64.05 है अर्थात् बिजली के लिए 626.75 इरीगेशन के लिए 506.22 करोड और बाढ नियन्त्रण के लिए 20 करोड रुपये शामिल है जिससे

हरियाणा प्रदेश का बहुमुखी विकास होगा। स्पीकर सर, इसी बजट में सामाजिक सेवाओं के लिए 657.45 की राशि का प्रावधान किया गया है खासकर बुढ़ापा पेंशन, विकलांग और विधवाओं के लिए भी 320.23 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है। हर व्यक्ति के लिए चाहे वह गरीब है अथवा अमीर है इस बजट में प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए 160 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वाटर सप्लाई और सैनित्त्व के लिए 58 करोड़ रुपये का, विकास के लिए 18.81 करोड़ रखे हैं। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हरियाणा की सारी इकोनॉमी कृषि पर निर्भर करती है। इसके लिए 111.80 करोड़ रुपये रखे गये हैं। जो सहायता प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं उसके लिए इस बजट में पिछले वर्ष के 624.47 करोड़ रुपये के मुकाबले में 1127.96 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है यानि कि दुगुना पैसा रखा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सढौरा की तीनों तरफ िवालिक की पहाडियां पडती हैं। जब बरसात होती है तो उनमें से निकलने वाली नदियों से हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है। वहां पर जो सोम नदी है उसके पास 20-25 गांव जैसे धनौरा, माजरी, भगवानपुर, भटुवाला, सतावडी, हपालगढ, भोरगढ, सुन्दर, बहुदरपुर आदि-आदि हैं। इसमें पानी ज्यादा आने की वजह से वे दूसरे इलाकों से कट जाते हैं। इसी तरह से वेभना छोटी नदी है उसमें भी पानी आने की वजह से डैहर,

अम्बली, गनौली, गहौली, बेरखेडी, ओखल, अडबोन, लखनौरा, अन्धेरी, सादिकपुर आदि गांव है जो कट जाते है। इन दोना नदियो पर पुल बनवाने की कृपा करें। सर, जब इन नदियो मे पानी आ जाता है तो वहां के किसान को अपनी फसल 20 किलोमीटर दूर से नारायणगढ होकर ले जानी पडती है। मै आपसे एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि वहां पर दो पुल बनवाने की कृपा करें और नदियो मे तेज बहाव से गांव न कटें इसका कोई प्रावधान करें। अध्यक्ष महोदय, राज्य मे 45 सौ किलोमीटर सडको की रिपेयर, सडको का पुननिर्माण, और कच्ची सडको को पक्का करने का विचार है यह बहुत ही सराहनीय काम है। स्पीकर सर, मेरे कहने का भाव है कि 2000-2001 का जो बजट पे 1 किया गया है यह बडी ही समझदारी और बडी सुझबुझ से तैयार किया गया है। इसमें हर वर्ग की भलाई का ध्यान रखा गया हैं। मै वित्त मंत्री जी का और मुख्य मंत्री चौधरी औम प्रका 1 चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बढिया बजट पे 1 किया है। धन्यवाद।

श्री देवराज दीवान (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सबसे पहले मै आपके माध्यम से इस महान सदन के सभी सदस्यों को दसवीं विधान सभा मे चुनकर आने के लिए बधाई देता हू।

दसवीं विधान सभा में जो नयी सरकार व नये साथी आए हैं मैं उन सभी को अपनी बधाई देता हूँ। वित्त मंत्री जी ने कल जो बजट पेश किया है अब मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बजट सरकार का एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार की नीति, नीयत और उसकी कारगुजारी को भी पेश की तरह दर्शाता है। वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट पेश किया है इसमें कोई भाकत नहीं है कि ये पूर्ण रूप से राज्य का चारों तरफ से विकास करेगा। इसलिए इस बजट की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को देखते हुए कोई भी सरकार अपनी नीतियों तैयार करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि मुकम एवं संतुलित बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ। इस बजट को देखने से यह आभास होता है कि चुनावों में इस सरकार ने जनता से जो वायदे किये उन वायदों को मूर्त रूप देने का काम सरकार ने इस बजट में किया है। इस बजट में प्रान्त के चहुमुखी विकास तथा लोगों के जीवन स्तर को उंचा उठाने के लिए सरकार ने अपना संकल्प व्यक्त किया है। आज समय की मांग है कि सरकार कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय ले जिनसे भविष्य में अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। सरकार को आर्थिक एवं बुनियादी क्षेत्रों के विकास की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। सरकार ने अंतर राज्य स्तरों में समानता लाकर तथा औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा

देने के लिए जो नयी औद्योगिक नीति घोषित की है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। गन्ने का भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करके जहां गन्ना उत्पादको को लाभ दिया गया है वहीं यूरिया एवं डी0 ए0 पी0 खाद के मुल्य मे छूट देकर अन्या किसानो को भी कृशि उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम इस सरकार ने किया है और अपनी किसान समर्थित छवि को सरकार ने निखारा है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सरकार द्वारा किये गये वि. शेष प्रयासो के कारण ही केन्द्रीय पूल से बिजली का उत्पादन 19% से बढकर 27% हो गया है।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सर, दीवान साहब अपनी लिखी हुई स्पीच यहां पर पढ रहे है। ये इसको सदन के पटल पर रखे और इसको पढा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। वह ठीक स्पीच दे रहे है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, यह नियमो मे भी लिखा हुआ है कि यहां पर कोई सदस्य अपनी लिखी हुई स्पीच नही पढ सकता। ये अपनी स्पीच पढ रहे है इसलिए क्यों न इस सपीच को पढा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: वे केवल हैडिंग देख रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें और उन्हें बोलने दें।

श्री देवराज दीवान: अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि आज के युग में बिजली की कितनी आवश्यकता है? इसमें संदेह नहीं कि बिजली का उत्पादन हमारे प्रदेश में आवश्यकता से काफी कम है। इस कारण काफी दिक्कत का सामान करना पड़ता है। इस अवस्था को सुधारने के लिए जो कदम सरकार ने अभी तक उठाए हैं वह सराहनीय हैं। सप्लाई में सुधार करके काफी हद तक बिजली की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। खेत में पानी के बिना किसान अपनी पैदावार को बढ़ा नहीं सकता। सिंचाई की सुविधा के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। सिंचाई के महत्व को मद्देनजर रखते हुए नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों की सफाई का कार्य करवाने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है जिसके लिए इस बजट की प्रतीक्षा किए बिना नहीं रहा जा सकता। प्रदेश के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2000-2001 में सड़कों को मजबूत करने तथा सड़कों की मरम्मत के लिए करीब 582 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। सोनीपत राठधना सड़क को मेरठ सोनीपत सड़क से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने प्रासकीय मंजूरी दे दी है इसके

लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह सड़क जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सोनीपत राठधना रोड काफी हद तक बन चुकी है थोड़ी सी बाकी रहती है और इसमें कई जगहों पर दो-दो ढाई-ढाई फुट के गड्डे हैं यह थोड़ा सा काम भी पूरा कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर पुलिस कर्मियों के परिवार को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का जो निर्णय लिया है, वह प्रशंसनीय है और इसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। चंडीगढ़ के सैक्टर 39 में 504 नये सरकारी मकान बनाने का प्रस्ताव किया गया है जो कि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की कठिनाई के प्रति जागरूकता को जाहिर करता है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में साफ पीने के पानी की व्यवस्था करना बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार ने 350 गावों में 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पीने का पानी उपलब्ध करवाने का प्रयास इस बार इस बजट में किया है जो कि बहुत ही जरूरी व सराहनीय कदम है। वर्ष 199 में सुखे के हालात होने के बावजूद खाद, बीज और पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कारण 116 लाख टन तथा 719 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। नये निवेशों को आकर्षित करने से व उद्योगों को विकसित करने से 20 प्रतिशत रोजगार के मौके बढ़ेंगे। नई औद्योगिक नीति नवम्बर

99 में घोषित की गई है, वह एक आदर्श नीति है जिससे राज्य का आर्थिक विकास होगा तथा लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि नयी औद्योगिक नीति प्रदेशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने नए-नए अस्पताल, डिस्पेंसरियों और सब-सेंटर खोलने के अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। इसके साथ ही महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय की मैचिंग ग्रांट को बहान करके चिकित्सा सेवा के लिए सोने पर सुहागे का एक और सराहनीय कार्य किया है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से 30 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को स्व-रोजगार के साधन जुटाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस संबंध में सरकार के प्रयासों की मैं दिल से सराहना करता हूँ। आपरेटन विजय के दौरान कारगिल में भागीदारी जवानों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की राशि प्रदान करना तथा भूरवीर घायल सैनिकों को 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक की धनराशि का दिया जाना उन भूरवीरों की वीरता का सम्मान है जिसके लिए यह सरकार अत्यन्त सराहना की हकदार है क्योंकि ऐसा करके इस सरकार ने देश की एकता और अखण्डता के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों और उनके परिवारों को एक सम्मान दिया है। हरिजन कन्यादान स्कीम के तहत 5100/ रुपये की राशि हर

गरीब हरिजन कन्या की भाादी हेतु उसके माता-पिता को प्रदान कर सरकार ने दलितो को वि ेश सम्मान प्रदान किया है जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। वृद्धावस्था, पै ान, विकलांगो तथा विधवाओ और बेसहारा लोगो को दी जाने वाली पै ान की रािा दुगनी करके सरकार ने महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। जिसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्त होने के फलस्वरुप नगरपालिकाओ को आर्थिक मदद देने के लिए 23.84 करोड रुपये की सहायता का प्रावधान किया है तथा फालतू घोशित किए गए तीन हजार से अधिक कर्मचारियो को अन्य विभागो में नौकरियो पर रख कर सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट एक संतुलित बजट है जिसमे राज्य के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए किसी भी वर्ग पर करो का कोई अतिरिक्त भार नही डाला है और गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की जरूरतो को मद्देनजर रखते हुए एक सराहनीय बजट प्रस्तुत किया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र है। यह बजट समाज के हर वर्ग को एक नई दिा देने मे सक्षम होगा तथा राज्य के विकास मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक भाानदार तथा विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी की कु ालता तथा बुद्धिमता की

प्र संसा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हलके के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: दीवान साहब, वाईड अप कीजिए।

श्री देवराज दीवान: अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके के कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें जो भाम गान घाट है वे ऐसे स्थानों पर हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो वहां पर जाने के लिए कच्चे रास्ते तो होते हैं पर उनमें दो-दो फुट पानी खड़ा हो जाता है। आप जानते हैं कि हर इंसान को इस संसार से एक न एक दिन तो अवश्य जाना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन रास्तों को पक्का करवाया जाए। मेरे हलके में गांव हैं चिटाला, पिनाना, जुआं, माहरा, नैनातितारपुर, खिरजपुर, जाट माजरा, सादनखुर्द, सांवलकलां, बोहला, बैयांपुर तथा चटियो औलिया। इन गावों के भाम गान घाट को जाने का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्षा के दिनों में भाम गान घाट को जाने वाले रास्ते में पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे मृतक को भाम गान घाट तक ले जाने में बहुत कठिनाई का सामान करना पड़ता है और कई बार तो अर्धी उठाए लोगों के फिसल जाने से काफी दिक्कत हो जाती है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हलका सोनीपत में सभी गावों के भाम गान भूमि को जाने के रास्ते भी पक्के करवाए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री

महोदय जी का ध्यान गांव की चौपालो की मुरम्मत और नवीनीकरण की ओर दिलाना चाहूंगा। गावो मे चौपालो की हालत बहुत ही खस्ता है और पिछले कई वर्षा `स इनकी मुरम्मत के लिए आव यकता के अनुसार रािा का आवंटन नही किया गया। मेरे हलके सोनीपत के गांव महाना मे वाल्मीकि, धानकान चौपाल, सांदलकलां मे हरिजन, धानकान चौपाल, गांव चटाना मे वाल्मीकि चौपाल, हरिजन चौपाल, बी सी चौपाल, गांव जाहरी में वाल्मीकि चौपाल, गांव पिलाना मे धानकान चौपाल, बी सी चौपाल, गांव थरिया में बी सी चौपाल, गांव बोहला मे हरिजन चौपाल, वाल्मीकी चौपाल, गांव कालूपुर मे धानकान चौपाल और हुल्लाखेडी मे बी सी चौपाल का मुरम्मत का कार्य तथा निर्माण कार्य होना बहुत ही अव यह है। मै एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि इन चौपालो की मुरम्मत वर्षा ऋतु के आरम्भ होने से पहले करने के निर्देा जारी करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुराध है है कि सोनीपत हलके के एप्रोच रोड गांव किलादड के लिए, गांव जाहरी से गांव थरिया तक एप्रोच रोड गांव हुल्लाहेडी के लिए, गांव सांदलकलां से गांव थरिया तक, गांव सांदल कलां से सांदलकलां रेलवे स्टेान तक, गांव जाहरी से कामी रोड तक, गांव सलारपुर माजरा से पिनाना तक, गांव जुआं से पांची तक वाया माहरा, गांव भाहजादपुर से गांव किलोडछ तक, पुरखास अडडा सोनीपत से लेकर चटिया

गांव तक, चटियां गांव से माहरा गांव तक लिंक रोड, जाहरी-थरिया लिंक रोड की मुरम्मत करवाने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हमारे सोनीपत भाहर मे एक बाई पास है उसका थोडा सा काम बाकी है जिसके बारे मे मैंने कल भी मुख्य मंत्री महोदय को बताया था। उस बाई पास को भीघ्र ही पुरा करवाया जाए जिससे सोनीपत का ट्रैफिक बाहर का बाहर हो जाएगा और इससे एक्सीडेंटस कम होंगे तथा रोजना लगने वाले जामो से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे हलके में 220 के0 वी0 सब-स्टे इन चालू हो गया है लेकिन उसके चालू हो जाने के बाद भी उसमें थोडा सुधार की आव यकता है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें थोडा सुधार किया जाए। अंत मे मैं। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि काकरोई और लहराडा गांव के खेतों की सिंचाई के लिए बुर्जी नं0 13800 पर एक मोगे की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके निर्माण के कार्या को भीघ्र अति भीघ्र करवाया जाए।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उनके जो भी सुझाव अपने हलके के है वे हमें लिखित मे दे दें, जो बोलने पर रह गये हो। दीवान साहब, आप भी अपने सुझाव मुझे दे दें। हम सभी सदस्यों के

सुझाव पर गौर कर लेंगे। चाहे वह सुझाव किसी भी मैनबर के हों।

श्री औम प्रकाश जिंदल (हिसार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जिनके बारे में बजट में चर्चा नहीं की गई है या की भी है तो नाम मात्र की। बजट में बहुत सी कमियां रह गई हैं। जैसे सेल्जटैक्स बारे में सुझाव है कि नई रेट लिस्ट 4 मार्च, 2000 से लागू की गई है। इस एक अप्रैल 2000 से लागू किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों को असैसमेंट करने में परेशानी न हो क्योंकि सरकारी वित्त वर्ष भी एक अप्रैल से ही शुरू होता है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हरियाणा में कारों की रोडी पर और बजरी पर सेल्ज टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है जबकि मार्बल पर सिर्फ यह 10% है और इसका उपयोग अमीर लोगों और व्यापारियों द्वारा किया जाता है। जबकि बजरी और रोडी का उपयोग गरीब आदमी ही करता है। इसलिए इस पर बढ़ाया गया टैक्स वापिस लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में दालों व अनाज पर 4% टैक्स लगाया गया है जबकि दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में इन पर कोई टैक्स नहीं है। क्योंकि यह आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन वस्तुओं पर टैक्स समाप्त किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी

औम प्रका 1 चौटाला जी की सरकार बनी थी उस समय हलवाईयो ने खु ि से मिठाईयां बांटी थी। लेकिन अब उनके उपर भी टैक्स लगा दिया गया और अब वे चौटाला साहब को गालियां दे रहे है। इस बात पर भी मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी ध्यान दें क्योंकि ये छोटे व्यापरी है, टैक्नीकल आदमी है और सरकार ने दुध से बनी वस्तुओ पर टैक्स लगा दिया है। इससे उनके रोजगार पर असर पड सकता है। इससे वे लोग बहुत परे ान हैं और इस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। (इस समय सभापतियो की सूची मे से माननीय सदस्य श्री रामपाल माजरा पदासीन हुए) सभापति महोदय, हरियाणा सरकार ने इस समय ट्रिब्यूनल कोर्टस में आई ए एस अफसरों को नियुक्त कर रखा है। जबकि वहां पर जुडी ि ायल मैजिस्ट्रेट होने चाहिए ताकि लोगो को सही न्याय मिल सके। क्योंकि जुडी ि ायल मैजिस्ट्रेट ठीक ढंग से न्याय करते है। आई0 ए0 एस0 अफसर सरकार से संबंधित होते है और सरकार के कहने के मुताबिक ही कार्य करते है। सरकार के कहने पर वे जिसको चाहे उसको सजा दे देते है और जिसको चाहे छोड देते है। इसलिए वहां पर ज्युडिसियल मैजिस्ट्रेट की ही नियुक्ति होनी चाहिए। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जो अधिकारी ट्रिब्यूनल कोर्टस में बैठते वे वहां पर स्थाई तौर पर नही बैठते बल्कि सप्ताह में 2-3 घंटे ही वहां बैठते है और व्यापारियो को चण्डीगढ आना पडता है। इस ओर भी सरकार

को ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, यदि अधिकारियों की कमी है तो और भर्ती करने चाहिए। लेकिन जो व्यापारी टैक्स देते हैं उन्हें पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर उनको कोई सजा देनी है तो वह जल्दी ही मिलनी चाहिए। उनके बार बार कोर्ट में चक्कर नहीं लगने चाहिए। बहस होने के बाद भी व्यापारियों का फैसला काफी समय तक रिलीज नहीं किया जाता। जबकि फैसले की कापी व्यापारियों को एक हफ्ते के अंदर मिल जानी चाहिए। सेल्ज टैक्स कमि नर चण्डीगढ़ के दफ्तर से व्यापारियों को कोई स्पष्टीकरण संबंधी सूचना नहीं मिलती है। सेल्ज टैक्स से संबंधित सारी सूचनाएं व्यापारियों को उपलब्ध कराने की प्रबंध सरकार को करना चाहिए। सभापति जी, एक तरफ तो सरकार आर्थिक विकास की गति को तेज करना चाहती है और दूसरी ओर सरकार नये उद्योगों पर दी जाने वाली सेल्ज टैक्स की छूट को वापिस लेना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे उद्योगों को बढ़ावा देगी। इसलिए किस तरह से व्यापार बढ़े और उद्योगों को बढ़ावा मिले इसके लिये सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। सभापति जी, मुख्य मंत्री जी ने जुलाई, 1999 में भापथ लेते ही अग्रोहा धाम में जाकर अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट बहाल करने की एक पब्लिक जनसभा में घोषणा की थी और प्रो० सम्पत सिंह के हलके के लोगो ने तथा अग्रोहा समाज ने खुशियां मनाई थी। प्रो० सम्पत सिंह का वहां हलका लगता

है। वहां के लोगो ने चौटाला साहब को वोट देकर कामयाब भी किया है। अग्रोहा मैडिकल कालेज की 12 करोड रुपये की ग्रांट बनती है। मुख्य मंत्री जी की घोशणा से अग्रवाल समाज और वित्तमंत्री जी के हलके के लोग बहुत खुश हुए क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी ने यह ग्रांट बन्द कर रखी थी। उन्होने ह ग्रांट इसलिए बंद कर रखी थी क्योंकि वह महाराजा अग्रसेन के नाम से चिढते थे। वे चाहते थे कि अग्रोहा मैडिकल कालेज को एक पैसा भी न दिया जाए। चौधरी औम प्रकाश चौटाला ने इस कालेज की ग्रांट तो बहाल कर दी लेकिन 9महीने बीत जाने के बाद भी इस कालेज के विकास के लिये केवाल मात्र 50 लाख रुपये की राशि दी गई है। (गोर) जब भी इसबारे में बात करते तो यही बात मिलती हैकि हम ग्रांट देने को तैयार है। काम पीओ डबल्यूओ डीओ ने करवाना है और वहां पर सामान रखा है और काम अधुरा पडा है। जब तक विकास का काम पूरा न हो जाए तब तक इस मैडिकल कालेज की बात करने को कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैकिल की वहां पर कोई क्लासिज नहीं लग सकती। सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन है क्योंकि वे वरिष्ठ सदस्य भी है और अग्रोहा इनका हलका भी रह चुका है और इन्होने ही इस अग्रोहा मैडिकल कालेज के लिये जमीन दिलाई थी तथा चौधरी देवी लाल जी ने ही इसकी फाउंडेशन रखी थी, हमारे अग्रवाल समाज ने करीब 15करोड रुपया इस कालेज मे लगा दिया है

और अब गवर्नमेंट की तरफ से ही कमी है। ये अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। इसलिए ये जल्दी से जल्दी इस कालेज की ग्रान्ट रिलीज कराये क्योंकि तकरीबन 100 किलोमीटर के एरिया में मैडिकल कालेज की कोई सहूलियत नहीं है। हरियाणा के अंदर चार मैडिकल कालेज होने चाहिए। रोहतक, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगए और अग्रोहा मैडिकल कालेज, हिसार में यह सुविधा होनी चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को मैडिकल कालेज की सुविधा मिल सके। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बकाया राशि जल्दी से जल्दी रिलीज की जाये ताकि मैडिकल कालेज का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके जिससे आम जनता को फायदा हो सके।

सभापति महोदय, अब मैं हिसार हलके की समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हिसार बाहर की सड़कों की बहुत बुरी हालत है और उनमें जगह जगह पर खड्डे पड़े हैं। मार्केट कमेटी के पास सड़के हैं उनकी मरम्मत इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कमेटी के पास पैसा नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार वहाँ पर पैसे देना का प्रबंध करे ताकि बाहर की सड़के ठीक हो सकें।

सभापति महोदय, अब मैं हिसार बाहर में पीने के पानी की कमी के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वहाँ पर पीने के पानी के लिए जो टैंक बनाया गया

था वह आज से 20साल पहले बनाया गया था। उसकी कैपेसिटी उस समय की आबादी को देखते हुए बनाई गई थीं उस के बाद भाहर की आबादी कई गुणा बढ़ चुकी है जिस कारण अब वहां पर पीने के पानी की बहुत किल्लत हो गई है (विघ्न) भ्जागी राम जी आप मुझे अपनी बात कहने दें। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हिसार भाहर मे पीने के पानी की बहुत कमी है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए तुरन्त कदम उठाये ताकि आम जनता को पीने का पानी मिल सके और उन्हे परे ानी का सामान न करना पडे।

सभापति महोदय, हिसार भाहर बहुत पुराना होने की वजह से वहां की सीवरेज की लाईन की भी बहुत बुरी हालत बनी हुई है क्योंकि यह बहुत सारी जगहो से टूटी हुई है। सीवरेज लाईन टूटने के कारण वह पीने के पानी की लाईन के साथ मिल गई है जिस कारण लोगो को गन्दा पानी पीने को मिल रहा है। सीवरेज की व्यवस्था जो आज से 20-25 साल पहले हिसार भाहर मे भुरु की गई थी वह तकरीबन एक तरहसे ठप्प हो गई है। इस सीवरेज की गन्दगी सडक के उपर तक आ गई है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हिसार के सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए वहां की मार्केट कमेटी को फण्ड मुहैया करवाए ताकि

जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामान न करना पड़े। हिसार की जनता वहां पर खुले दरबार में भी इस मांग को कई बार उठा चुकी है। अतः मेरा सरकार से इस बारे में पुनः अनुरोध है कि वहां के सीवरेज सिस्टम को तुरन्त ठीक कराने के लिए विशेष कदम उठाये। सभापति महोदय, हिसार भाहर एक बहुत ही भीड़ वाला भाहर है। वहां पर लोगो का तंग गलियां होने की वजह से निकलना भी दूभर हो गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ भी सरकार ध्यान देते हुए इस का कोई हल निकालने की कोशिश करे। चेयरमैन साहब, आपने यहां पर मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री बंसी लाल (भिवानी): चेयरमैन साहब, मैं दो तीन प्वायंट्स पर ही अपनी बात कहूंगा क्योंकि यह नई सरकार का पहला बजट है। सभापति जी, मैं आपके जरिये श्री सम्पत सिंह जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि इन्होंने इस बजट में बिजली के मद के अंदर 1070.13 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें से तकरीबन 506 करोड़ रुपया तो प्लान साइट में और तकरीबन 562 करोड़ रुपया नान प्लान साइट में रखा गया है। नान प्लान साइट्स में अब से पहले सबसिडी तकरीबन 800-850 करोड़ रुपये की थी जो कृषि क्षेत्र को दी जा रही थी। फरीदाबाद के गैस बेस्ड पावर प्लांट की 146 मैगावाट की तीसरी यूनिट और

पानीपत थर्मल पावर प्लांट की 210 मैगावाट की छठी युनिट भी चालू हो जाएगी। इससे कम से कम 10 परसेंट बिजली फारमिंग सैक्टर को ज्यादा मिल सकेगी। इसके बाद यह सबसिडी बढ़कर 1100-1200 करोड़ रुपये हो जायेगी। सरकार इस सबसिडी को कहां से पूरा करेगी इस बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री जी ने बजट में डब्लू0 आर. सी0 पी0 और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की क्या गारंटी है कि वर्ल्ड बैंक और हरियाणा सरकार में लोन के बारे में समझौता हो भी पायेगा या नहीं हो पायेगा? इसके अलावा ओटू वीयर जहां पहले भी वहां से अब बन रही है वह 800 मीटर नीचे है। उसकी जो कैपेसिटी कम हुई है वहां सिल्ट आ गई। जो पानी ठहरता था वहां पर सिल्ट कास्ट होती थी। मैं समझता हूँ कि उस पूरी सिल्ट को निकलावाया जाए और उसके 2-4 किलोमीटर पीछे तक भी अगर जमीन ऐक्वायर करके पानी से भर लिया जाये तो उसमें खासा का हो सकता है और अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। हमने एक बार स्कीम बनाई थी कि रेलवे लाईन तक ओटू वीयर को ले जाए, अगर आप ऐसा कर सके या जितना भी उसको बढ़ा सके, बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा होगा और प्रदेश को उससे फायदा है।

चेयरमैन साहब, एक प्वायंट के बारे में मैं और जिक्र करना

चाहूंगा। चौधरी सम्पत सिंह जी ने फलड प्रोटैक इन मैम्बर्ज को हाई प्रायोरिटी पर रखा है लेकिन उसके लिए केवल 20 करोड रुपये का प्रावधान इस बजट में रखा है। 20 करोड रुपये से फलड प्रोटैक इन का काम नहीं हो सकता है। जहां पर 2700-2800 करोड रुपये का काम है वहां पर 20 करोड रुपये से कुछ नहीं हो सकता। अभी तो उन्होंने बजट में जो प्रावधान रखा है वह बहुत ही कम है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। चेयरमैन साहब, इस बजट में हिसार-घग्गर ड्रेन का जिक्र भी किया गया है और यह ड्रेन बनाने के लिए काफी पैसे की जरूरत होगी।

श्री सम्पत सिंह: चेयरमैन साहब, यह तो इस टाइम से भी पहले से चली आ रही है इसको वर्ल्ड बैंक के साथ टाई-अप करके तथा उनसे लोन सैंक इन करवाना है। 2700-2800 करोड रुपये का अभी जो उन्होंने जिक्र किया इसमें और दूसरे प्रोजैक्ट्स भी हैं जो वर्ल्ड बैंक से जब पैसा आएगा तभी पूरे हो पाएंगे। अभी इन प्रोजैक्ट्स के लिए पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ है अभी तो केवल स्कीमें ही बनी हैं।

श्री बंसी लाल: चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से मैं एक बात सरकार को कहना चाहूंगा। चार करोड रुपये से ज्यादा की जो भी स्कीम होती है वह सी0 डबल्यू0 सी0 से मंजूर करवानी पडती है। उसकी क्लियरेंस अगल ले ली गई है

तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर क्लियरेंस नहीं ली तो ले लीनी चाहिए। इस बारे हमने लिखा भी था। अब क्लियरेंस नहीं ली गई तो बाद में उनके भी चक्कर लगाने पड़ेंगे इसलिए वक्त से क्लियरेंस ले ले तो अच्छी बात है। सी० डबल्यू० सी० जब मंजूरी करने लगेगा तो वह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की सरकार से भी पूछेगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को भायद कोई आब्जैक्शन नहीं होगा लेकिन मैं समझता हूँ कि भायद राजस्थान को आब्जैक्शन हो क्योंकि वह आगे जा कर हनुमानगढ़ को डुबोती है। इसमें जो पानी जाता है वह पोल्यूटिड वाटर है। परवाणु बनूड और आगे जा कर राजपुरा डेरावसी की सब फैक्टरियों का गन्दा पानी घग्गर में जाता है और फिर यह आगे जा कर सब से ज्यादा सिरसा के आखिरी हिस्से में नुकसान करता है। साल डेढ़ साल पहले हनुमानगढ़ में इस गन्दे पानी की वजह से कई मवेशी मर गये थे और लोगों में पीलिये की बीमारी भी फैल गई थी। इस बारे में सी० डबल्यू० सी० और राजस्थान गवर्नमेंट से बात करें। राजस्थान गवर्नमेंट की भी इस पानी में भागीदारी है इसलिए वैसे तो उनको भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 2530 करोड़ रुपये का जो प्लान चौधरी सम्पत सिंह जी ने बनाया है यह मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता इस लिए इसको घटाना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता कि

2530 करोड रुपये ये जुटा पाएंगे। चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री चन्द्र मोहन (कालका): माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वित्त मंत्री जी ने सदन में जो बजट पेश किया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बजट को पढ़कर मैं ऐसा लगता हूँ कि इसमें कहीं पर भी किसान भाईयों को, कर्मचारियों को, व्यापारियों को और मजदूर भाईयों को कोई राहत देने का प्रयास नहीं किया गया है। बजट का घाटा 196.77 करोड रुपये से आरम्भ होकर 294.56 करोड रुपये का अनुमान है। 97 करोड रुपये का घाटा खाली छोड़ा गया है। इस घाटे को पूरा करने के लिए खाली पदों की समाप्ति, नए पदों की भर्ती पर रोक, सरकारी खर्च में कमी और टैक्सों की वसूली करके अतिरिक्त टैक्स जुटा कर पूरी की जाएगी। ऐसा उसमें लिखा गया है। जब ये सरकार बनने से पहले लोगों के बीच में गए थे तो इन्होंने कहा था कि हम भर्ती करेंगे अब ये भर्ती पर रोक लगा रहे हैं। इन्होंने जो वायदे जनता से किए थे उनका क्या होगा? इसी प्रकार से ये यह बताएं कि सरकारी खर्चों में किस प्रकार से कटौती की जाएगी। कौन से खर्च कम होंगे। बजट अनुमानों पर चर्चा की गई लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि चुनावों से पहले जो

किसानों के साथ वायदा किया था कि 5वीं स्लैब प्रणाली लागू करेंगे। उसकी भी इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। इसी प्रकार से ट्यूबवैल के कनेक्शन देने की बात है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो कनेक्शन काट दिए गए हैं उनके बारे में क्या करेंगे। सभापति महोदय, अग्रोहा मैडिकल कालेज के बारे में हमारे कई साथियों ने चर्चा करते हुए कहा है कि मैं इस बारे में ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि गुरु जम्भेवर यूनिवर्सिटी में आदरणीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने वायदा किया था कि जो चौधरी बंसी लाल जी ने राजनीतिक दुर्भावना करके उसका दर्जा घटाया है उसके बहाल करेंगे। इसके बारे में सरकार की आज क्या योजना है। मैं यह जानाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भाराब बंदी की आड में चौधरी बंसी लाल जी ने 3000 करोड़ रुपये के टैक्स लगाए थे उस बारे में चुनावों से पहले यह सरकार कहती थी कि हम उनको वापिस ले लेंगे। इस बारे में क्लियर करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताना चाहूंगा। कालका क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वह पैरीफरी एक्ट की वजह से है। इस ऐक्ट की स्थापना जब चण्डीगढ़ बना था, तब हुई थी। उसके बाद तो सारा इलाका डिवैल्प हो गया है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि यह सैन्टर गवर्नमेंट से लिंकड है। सभापति महोदय, जैसे पंजाब में डेरावासी इन्डस्ट्रीयल

एरिया को बैकवर्ड एरिया घोशित करके वहां के रहने वालों को सुविधा प्रदान की जाए। अगर ऐसा करेंगे तो वहां पर जो रहने वाले हैं उनके ऊपर जो पैरीफरी की तलवार लटक रही है उससे उनको निजात मिलेगी। सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारे यहां पर जितने भी गांव हैं सब में आबादी बढ़ गई है। लाल डोरे की समस्या हर गांव में आती है। कनेक्ट इन लेने की समस्या आती है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि लाल डोरे को बढ़ाया जाए ताकि यहां के रहने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। इसी प्रकार हमारा मोरनी क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी समस्या नोटोड को लेकर है। श्री भजन लाल जी के भासन काल में कंसौलिडे इन का काम शुरू हुआ था लेकिन श्री बंसी लाल जी ने अपने समय में उसको बंद करवा दिया था। मेरा आपकी सरकार से नम्र निवेदन है कि उस काम को वारफुटिंग पर किया जाए, वहां के लोगों को राहत दी जाए। इसी तरह से दून और रायपुर क्षेत्र के एम0 पी0 ग्रन्ट से सिंचाई के लिए ट्यूबवैल्वेज लगाए गए थे उनका आज तक कनेक्ट इन नहीं लगा है। यह बैकवर्ड इलाका है, पहाड़ी इलाका है सरकार को चाहिए कि इस इलाके में टॉप पर कनेक्ट इन दें। इसी तरह से इन्होंने गवर्नर एड्रेस में कहा है कि बाहरी को सुन्दर बनाने का प्रयास करेंगे। यह बात सही है कि घरों के बाहर जो एन्कोचमेंट है, वह कोर्ट के आर्डर से तोड़ी गई है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन जगहों को ये वहां से रहने वाले लोगों को

सस्तेदाम पर दे सकते हैं ताकि वह जो जगह है उसको वे लोग अच्छी तरह से मैनटेन कर सकें। इससे सरकार का भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। एक और बात गवर्नर एड्रेस में थी कि गावों में जो मैचिंग ग्रंट देते हैं उसको बनाया गया है यह तो बढ़िया बात है लेकिन भाहरो में जो कॉलोनियां हैं जहां पर पंचायत नहीं है या जहां पर म्यूनिसिपल कमिटी नहीं है जैसे पंचकुला है तो अगर वहां के लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके सरकार को दें तो क्या सरकार उसके बदले में ऐसे भाहरो को मैचिंग ग्रंट देगी? यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। इसी तरह से जहां तक शिक्षा की बात है आपने भी अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पढ़ा होगा कि अब टीचर्स की भर्ती के लिए हरियाणा का डोमीसाइल होने की जरूरत नहीं है। सर, यह तो हरियाणा के लोगों के साथ धोखा है। अगर यहां पर बाहर के लोग आकर रहने लगेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इसी प्रकार से मेरे हलके में एक बिटना गांव है हां पर एक आई० टी० आई० का निर्माण चौधरी भजन लाल जी के समय में हुआ था लेकिन बंसी लाल जी की सरकार ने उसको चालू करवाने की कोशिश नहीं की। मेहरबानी करके सरकार उसको चालू करवाने की कोशिश करे। इसी तरह से जहां तक पीले कार्ड का संबंध है इनको बनाने में बहुत धांधली हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस बारे में दोबारा सर्वे करवाया जाना

चाहिए और ये पीले कार्ड, सही हकदारों के ही बनाये जाने चाहिए। इसी तरह से बुढ़ापा पेंशन की जहां तक बात है सरकार ने इसको सौ से दोसौ रुपये किया है। अच्छी बात है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको 500 रुपये तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने चाली साल के लोगों को भी इसका लाभ देने के लिए बुढ़ा बना दिया है इसलिए मेहरबानी करके सरकार को इसका भी दोबारा से सर्वे करवाना चाहिए और उचित लोगों को ही इसका लाभ देना चाहिए। मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री अमर सिंह (गुहला, अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। आदरणीय वित्त मंत्री श्री सम्पत सिंह जी ने कल जो बजट यहां पर पेश किया है मैं उसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वित्त मंत्री जी ने हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए हर मद के लिए जो पैसे का प्रोविजन किया है उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। चाहे वह बिजली की बात थी, चाहे वह सड़कों की बात थी, चाहे वह परिवहन की बात या चाहे वह सामाजिक कल्याण की सेवाओं की बात थी, उन्होंने पूरी तरह से सोच समझ कर हर मद के लिए पूरा पैसा दिया है। चेयरमैन साहब, जहां तक बिजली की

बात है हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए यहां पर बिजली का होना बहुत ही आवश्यक है। अब हरियाणा के लोग एक ही बात करते हैं कि जब जब भी चौधरी देवी लाल जी का या चौटाला साहब का राज आया तब तक हरियाणा के लोगों को पूरी बिजली मिली और इसी कारण आज भी हरियाणा के लोगों को हमारी सरकार पर पूरा विश्वास है। पिछले 6 महीनों में जो सरकार ने लोगों को बिजली दी है उसके लिए हरियाणा के लोग बहुत आभारी हैं। हमारा कैथल एरिया एक कृषि प्रधान एरिया है। वहां पर लोग जीरी और कनक की खेती करते हैं। अभी पिछले दिनों जब लोग कनक की फसल को पानी दिया करते थे तो वे एक ही बात कहते थे कि इस या बारह साल के बाद पहली बार उनको अपनी इस फसल को दिन में पानी देने का मौका मिला है जबकि पहले वे लोग रात को ही पानी दिया करते थे क्योंकि पहले उनको दिन में बिजली ही नहीं मिलती थी। चेयरमैन साहब, बिजली के विकास के लिए बजट में जो पैसा रखा गया है, चाहे वह नये पावर हाउस बनाने की बात हो, चाहे नयी लाईने बिछाने की बात हो, सबके लिए पैसा रखा गया है इसके लिए मैं भी सरकार का, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि बिजली की जरूरत को देखते हुए उन्होंने इस बारे में पूरा पैसा रखने की कोशिश की। सर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरा जो गुहला हलका है वह कृषि के लिहाज से पूरी तरह से जीरी और कनक की खेती पर निर्भर है

इसलिए वहां पर बिजली किसान के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमारे गुहला हलके में 232 के 0 वी का पावर हाउस मंजूर है उसके लिए जमीन भी ऐक्वायर हो चुकी है इसलिए कृपया उस पर काम भुरु करवाया जाए ताकि आने वाले दिनों में किसानों को पूरी बिजली मिल सके और खेती के लिए पूरी बिजली उपलब्ध हो सके। सर मेरे हलके में तीन सब डिवीजन हैं। ये हैं—गुहला, चीका और सीवन सब डिवीजन। 12:00 बजे जब कांग्रेस का राज था उस समय उन तीनों सब डिवीजनों को एक डिवीजन बनाने के लिए ऐस्टीमेट बनाया गया था और वह पास भी हो गया था लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। हमारा सिविल सब डिवीजन कैथल में पडता है और उप मंडल गुहला और चीका व सीवन में पडते हैं। हमें अपने कामों के लिए गुहला, कैथल और पेहवा, चीका व सीवन के चक्कर काटने पडते हैं मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन तीनों सब डिवीजनों को मिलाकर गुहला में एक डिवीजन बनाया जाए। वहां पर लोगों को बिजली की जरूरत है और उसके लिए कभी कैथल के व कभी पेहवा के चक्कर काटने पडते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेरे हलके के गांव काटड में 33 के 0 वी 0 सब स्टे इन का काम चालू है। जीरी का सीजन आने वाला है उससे पहले पहले इस सब स्टे इन का काम पूरा हो जाए ताकि लोगों को पूरी बिजली मिल सके। जहां तक सिंचाई की बात है मैं धन्यवाद

करुंगा कि सिंचाई की तरफ भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है और पूरा पैसा इसकी मद में रखा गया है। मेरे हलके में मारकण्डा डिस्ट्रीब्यूट्री है जो हमारे यहां के सभी गावों को पानी देती है जब कांग्रेस के राज में इस डिस्ट्रीब्यूट्री को पक्का किया गया तो पेहवा हलके के पास इसके बेड को उपर उठा दिया गया। इसकी क्षमता 444.9 क्यूसिक की है लेकिन इसमें 360 क्यूसिक पानी छोड़ा जाता है जिसकी वजह से इस नहर में सिर्फ चीका तक ही पानी पहुंचता है। चीका से आगे के 20-25 गावों में पानी नहीं पहुंचता। चैयरमैन सर, जब मैं 1991 में विधान सभा में सदस्य के रूप में चुनकर आया था तब मैंने कांग्रेस सरकार को फोटो लाकर दी थी। गावों में लोग बटोड़े वहां रखते हैं जहां पानी न पहुंच सके। हमारे वहां लोगों ने इस डिस्ट्रीब्यूट्री में बटोड़े रखे हुए हैं और वे इसे सेफ जगह मानते हैं क्योंकि वहां पर पानी कभी पहुंचा ही नहीं। वह फोटो लाकर दिखाने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और यह सोचकर नहीं दिया क्योंकि गुहला हलके से हमें 11 इनकी विरोधी उम्मीदवार जीता रहा है। पीछे श्री बंसी लाल जी की सरकार ने भी मेरे हलके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि स लेवल को दोबारा से चैक करके पानी पूरा का पूरा टेल एंड तक पहुंचाया जाए। बिजली और पानी हमारे यहां के किसानों के लिए बहुत जरूरी है। मैं वित्त मंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद

करता हूं कि उन्होंने सडको और पुलों की रिपेयर के लिए भी पैसा रखा है। चेयरमैन सर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पिछली सरकार ने मेरे हलके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा हलका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पिछली सरकार ने एक नया पैसा भी मेरे हलके की सडको के लिए नहीं दिया। मैं चौटाला साहब का धन्यवाद करता हूं कि उनके मुख्य मंत्री बनने के बाद मेरे हलके की कुछ सडको की मरम्मत हुई। जहां तक कृषि का सवाल है मैं पहले भी कह चुका हूं कि पूरा जिला कैथल या गुहला हल्का कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे है और पूरा उत्पादन देता है। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बिजली और पानी की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए ताकि मेरे हलके के किसानों को कृषि की तरफ ध्यान देने में कोई कठिनाई न आये। चेयरमैन सर, चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव से पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत खुले दरबार में कैथल भाहर में सीवन अनाज मण्डी को मंजूरी दी थी। अगर उस मण्डी को बनाने का काम सरकार भुरु कर दे तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। इसके अलावा मेरे हलके में चीका मण्डी की मंजूरी सरकार की तरफ से हो चुकी है और उसकी जमीन भी ऐक्वायर हो चुकी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस साल में ही चीका मण्डी बनाने का काम भुरु किया जाये। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं सरकार को एक बात और कहना चाहता हूं। गेहूं का सीजन

भुरु होने वाला है परंतु पिछले सीजन में जो गेहूं की परचेज की गई थी चाहे वह कैथल में हो या पुण्डरी में हो, चाहे गुहला में हो वह सारा गेहूं वहां के भण्डारों में ही पड़ा है केन्द्र सरकार ने उस गेहूं को वहां से अभी तक नहीं उठवाया है। नई कनक आयेगी तो उसका भण्डारण कहां किया जाएगा? इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार से अनुरोध करके पुरानी गेहूं को भण्डारों में से उठवाया जाये ताकि नई गेहूं के भण्डारण में कोई दिक्कत न हो। चेयरमैन सर, मेरे हलके गुहला में गुहला सब डिवीजन है और वहां पर मार्केट कमेटी है। परंतु उस मार्केट कमेटी में फायर ब्रिगेड स्टे न नहीं है। इसलिए जब भी कभी कनक के सीजन में आग लग जाती है तो हमें कैथल या पेहवा से फायर ब्रिगेड मंगानी पड़ती है। परमात्मा न करे ऐसा हो परंतु कनक के सीजन में अकसर ऐसा हो जाता है। फायर ब्रिगेड के लिए हमने पैसे भी जमा करवा रखे हैं सिर्फ सरकार ने मंजूरी देनी है। अगर सरकार वहां पर फायर ब्रिगेड स्टे न खोलने की मंजूरी दे देती है तो किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। इस बजट में काफी सभी चीजों के लिए काफी पैसा रखा है इसमें चाहे समाज-कल्याण हो, चाहे दूसरी चीज हो। हरियाणा प्रदेश के लिए वर्तमान सरकार ने एक अच्छा बजट पेश किया है। चेयरमैन सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जोकि खासकर हमारे हरिजन भाईयों के लिए है। आज हरियाणा के पूरी हरिजन समाज ने सरकार को

17 में से 14 सीटें दी है। कांग्रेस पार्टी जो आज तक ढिंढोरा पिटती रहती थी कि हम हरिजनो का विकास करेंगे आज तक कांग्रेस पार्टी ने हरिजन समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। आज सारे हरियाणा का हरिजन समाज इस सरकार से जुड़ा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह हरिजना के कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करे। चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भादी लाल बतरा जी बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: चेयरमैन सर, विधान सभा सचिवालय की तरफ से एक पत्र हर सदस्य को मिला है जोकि regarding 'Survey on the Review of the Indian Constitution] है। सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह मुद्दा भारत के संविधान को बदलने का है। इस पर बराबर चर्चा होनी चाहिये। यह देश के दलितो और गरीब लोगो की भावनाओ पर कुठाराघात करने की साजिा है। मेरा आपे अनुरोध है कि हाउस की कार्यवाही स्थगित करके संविधान के विशय पर चर्चा होनी चाहिए और मै सभी माननीय सदस्यो से अनुरोध करुंगा कि वे एक प्रस्ताव पारित करें कि हिन्दुस्तान के संविधान को जिसे डा० बी० आर० अम्बेडकर ने बनाया था उसे बदलना नहीं चाहिये। इस पर चर्चा होनी चाहिए और सभी सदस्यो को इस विशय पर बोलने का समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति: देखिये दलाल साहब, इस पत्र के द्वारा सिर्फ व्यक्तिगत राय ही पूछी है। हाउस से इस बारे में नहीं पूछा गया है। केवल व्यक्तिगत राय जानने के लिए ही यह पत्र सदन में बंटवाया गया है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि यह जो संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है।

श्री धीरपाल सिंह: सभापति महोदय, इस सरकुलर को अभिप्राय व्यक्तिगत रूप से सबकी राय जानना है इसमें डिस्कशन का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सभापति: जिस इंस्टीच्यूसन ने आपको यह लैटर भेजा है, आप उसको अपनी राय भेज दें। इसमें डिस्कशन का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, सरकुलर का मतलब प्रत्येक मैम्बर से राय जानना नहीं होता इसलिए इस मुद्दे पर ओपन डिस्कशन करवाई जाए।

श्री सभापति: किसी इंस्टीच्यूशन ने आपकी इंडीविजुअल राय जाननी चाही है, इस बारे में हम कोई प्रस्ताव नहीं पास करना चाहते हैं।

श्री धीरपाल सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि ये पहले इस लैटर को अच्छी तरह से पढ़े, इसमें लिखा हुआ है कि बीफोर 15-3-2000 और यह 15-3-2000 आज ही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि इसमें राय जानने की बात है। (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: *****

श्री सभापति: कर्ण सिंह दलाल जी जो कुछ भी कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी राय दें इसलिए आप इसमें अपनी राय लिखकर भेज दें। (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: सभापति महोदय, आज आदरणीय सम्पत सिंह जी की तरफ से लैटर आया है कि आज आप सबका डिनर है तो आप इसके बारे में भी हमारे ओपीनियन जानना चाहेंगे कि हम जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। (गोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, इसको कोई दो राय नहीं कि यह क्वै चनेयर है कोई हाउस का एजेन्डा नहीं है। कर्ण सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है वह काफी महत्वपूर्ण है और हम इससे अनकंसर्ड नहीं रह सकते। इनका सुझाव है कि इस पर डिस्कान होनी चाहिए। आज संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है।

श्री धीरपाल सिंह: सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ययह कोई एजेन्डा नहीं है तो इस पर डिस्कशन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भूपेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, मैं इस कागज की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कर्ण सिंह दलाल ने जो मुददा उठाया है वह पूरे हरियाणा और पूरे भारत का मुददा है। (गोर) हमारा काम संविधान की रक्षा करना है, संविधान के हिसाब से हम सब यहां पर बैठे हैं।

श्री सभापति: हुड्डा साहब आप बैठिये। (गोर) एक इंस्टीच्यूशन आपकी राय जानना चाहती है आप लिखकर बाई पोस्ट भेज दें, इसमें इतनी सी यह बात है। (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: * * * * *

श्री सभापति जी: जो कुछ भी कर्ण सिंह दलाल जी कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सभापति महोदय, पहले आप मेरी बात तो सुनें। उसके बाद आप जो भी फैसला करें, वह ठीक है।

श्री सभापति: दलाल साहब आपकी बात सुन ली। आपकी जो भी ओपीनियन है वह आप बाई पोस्ट भेज देना। इंस्टीच्यूशन आफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है

दलाल साहब वह आपको दे दी गई है और आपने इस बारे में जो भी ओपीनियन देनी है वह बाई-पोस्ट भेज देना। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह: सभापति महोदय, अब बजट पर बहस चल रही है। इसलिए अब किसी दूसरे मुद्दे पर बहस नहीं हो सकती। अगर मेरे विपक्ष के भाइयों को कोई और बात करनी है तो वह किसी और समय कर लेंगे। लेकिन अब नहीं हो सकती। आज सुबह जीरो आवर हो चुका है अब कोई दूसरी बात नहीं हो सकती और कालिंग अटैंशन के लिए भी आज समय रखा गया था। (विघ्न) उस कालिंग अटैंशन का जवाब भी दिया गया था सभापति महोदय, अगर मेरे विपक्ष के भाई कुछ और लिखकर देंगे तो हम उसका जवाब भी देंगे। लेकिन इस समय बजट पर चर्चा चल रही है। इसलिए वे बजट पर ही बोलें। कोई दूसरी बात न करे। अगर ये दूसरा मुद्दा उठाएंगे तो वह वाजिब नहीं होगा। सभापति महोदय, भजन लाल जी विपक्ष के नेता हैं। ये ही बता दें कि बजट पर चर्चा चल रही हो और बीच में कोई दूसरा मुद्दा उठाया जाये। क्या यह वाजिब है?

श्री भजन लाल: सभापति महोदय,, यह ठीक है कि बजट स्पीच पर बजट के बारे में ही बोलना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो यह कागज सबको दिया है यह भी बजट ` बीच में नहीं देना चाहिए था। यह भी कल ही देना चाहिए था। अगर ये इस तरह से बीच में कागज देंगे तो उस पर बोलना भी पड़ेगा।

श्री सम्पत सिंह: सभापति महोदय, यह जो सर्कुलर है यह हरियाणा सरकार का सर्कुलर नहीं है। यह तो इंस्टीच्यूट आफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गांधी भवन, कुमार पार्क, ईस्ट बंगलौर का सर्कुलर है। सभापति महोदय, इसी तरह से पार्लियामेंट की भी जो कमेटियां बनी हुई है, उनसे भी सर्कुलर आते रहते है। कामन वेलफेयर आदि की जो कमेटियां बनी हुई है, उनसे भी सर्कुलर आते रहते है। सभापति महोदय, इन कमेटियो की तरफ से सैक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन आती है कि सभी सदस्यों को यह सर्कुलर दिया जाये और सैक्रेटरी ने यह सर्कुलर आज सभी सदस्यों को दे दिया। उस इंस्टीच्यूट को सभी सदस्यों ने अपनी अपनी ओपीनियर देनी है। यह बाई पोस्ट भेज देना। यह कोई सरकारी कागज होता तो आपको इस पर ऐतराज होना चाहिए था और हम इसका जवाब भी देते। सभापति महोदय, मैं भजन लाल जी को बताना चाहता हूं कि इस तरह से सर्कुलर पहले भी आते रहे है। अधिवेशन नहीं होता था तब भी आते रहे है। सभापति महोदय, अधिवेशन नहीं होता तब भी सैक्रेटरी इस तरह के सर्कुलर सभी मैम्बरजके पास पहुंचाता है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगो को इन्वोल्वमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमे पार्टीसिपेट कर सके तथा अच्छी राय दें सके। यह कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है और न ही सरकार से कंसर्न है। इसलिए इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है।
(विघ्न)

श्री सभापति: इस सर्कुलर के बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टीकरण दे दिया है। इसलिए इसके उपर कोई भी डिस्कान नहीं हो सकती। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: सभापति जी, चौधरी सम्पत सिंह कह रहे हैं कि यह सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। सचिव, विधान सभा ने भी यह डॉक्यूमेंट नहीं भेजा तो फिर विधान सभा में यह डॉक्यूमेंट कहां से आ गया। (गोर)

श्री सम्पत सिंह: सभापति जी, विधान सभा सचिवालय ने ही यह डॉक्यूमेंट भेजा है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: सभापति जी, विधान सभा का डॉक्यूमेंट कैसे हो गया। ये तो विधान सभा कहे कि यह डॉक्यूमेंट विधान सभा का है।

श्री सभापति: यह डॉक्यूमेंट विधान सभा का ही है और विधान सभा ने यह डॉक्यूमेंट सरकुलेट किया है।

श्री भजन लाल: मैं सदन में एक बात कहना चाहूंगा। सभापति जी, संविधान से छेड़छाड़ करने के हक में देना के बहुत थोड़े लोग हैं। कम से कम 2/3 लोग संविधान से छेड़छाड़ करने के हक में नहीं हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह: सभापति जी, अभी तक संविधान को रिव्यू करने की कोई बात नहीं हुई है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: सभापति जी, * * * * *

Mr. Speaker: Whatever has been spoken by Sh. Bhajan Lal is not to be recorded.

श्री कर्ण सिंह दलाल: सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: कर्ण सिंह जी, जब आपको बोलने का समय दिया गया तब तो आप बोले नहीं। (गोर)

Shri Sampat Singh: Haryana Vidhan Sabha cannot review the Constitution. We have no power to review the Constitution. It is only for suggestion and not for discussion.

श्रीमती अनिता: सभापति जी, मुझे एक बात कहनी है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: अनिता यादव जी, आप बैठिये। (गोर)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: सभापति महोदय, (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: डा० कादियान, आप बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सभापति जी, मेरी बात तो सुनिये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: भादी लाल जी, आप बोलें। अगर आप नहीं बोलेंगे तो दूसरे सदसस को संबोधित करना पड़ेगा। (गोर)

एवं व्यवधान) डा० कादियान, आप बैठिए। चौधरी कर्ण सिंह दलाल आप भी बैठिए। आप तो एक अच्छे पार्लियामैन्टेरियन हैं। (गोर) भादी लाल जी नये मैम्बर हैं, इनको बोलने में सहयोग दें। (गोर एवं व्यवधान)संसदीय कार्य मंत्री का ब्यान आ चुका है और उन्होंने अपने आप एक्सप्लेन कर दिया है। अब तो आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है।(गोर)

श्री सम्पत सिंह: सभापति जी, विपक्ष में सदन के जो नेता हैं वे बोल चुके हैं तो अब इनके बाकी मैम्बरों के बोलने की तो कोई जरूरत नहीं है। (गोर) You cannot discuss the Constitution here. Everything has been cleared now.

श्री जय प्रकाश: सभापति जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: जय प्रकाश जी बैठिए। (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: सभापति जी, (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: दलाल साहब, आप बैठिए। भादी लाल जी को बोलने में सहयोग दें क्योंकि नये मैम्बर हैं। आप बीच में बाधा न डालें। अब सब बातें क्लीयर हां चुकी हैं और आप लोगों की समझ में भी आ गई है। इसलिये इस इशु पर अब बोलने की जरूरत नहीं है। (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: सभापति जी, आप मेरी बात तो सुन लें। (गोर)

श्री सभापति: दलाल साहब जब आपको बोलने का समय मिलेगा तो उस वक्त आप बोल लेना। अभी बैठिए। (गोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूँ। (गोर)

श्री सभापति: कर्ण सिंह दलाल जो बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए।

वाक-आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल: सभापति जी, अगर आप मुझे इस बारे में बोलने का मौका नहीं देते तो मैं सदन से वाक-आउट करता हूँ।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक-आउट कर गए)

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

श्री भादी लाल (रोहतक): सभापति महोदय, जो लैटर आज सर्कुलेट हुआ है उसको मैं सदन के सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। (गोर एवं विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह: सभापति महोदय, इनको कहें कि यह लैटर पढकर सदन में गलत परम्परा न डालें। ये बजट पर जो कुछ कहना चाहते हैं, वह कह लें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: भादी लाल जी, आप केवल बजट पर ही अपनी बातें कहें।

श्री भादी लाल: ठीक है जी। सभापति महोदय, मैं इस महान सदन में पहली बार चुनकर आया हूँ। मेरा कहना यह है कि चाहे हम किसी भी पार्टी से या किसी भी क्षेत्र से चुनकर आये हैं लेकिन हम सदन के अंदर सारे एक हैं और हमें सभी ने मिलकर हरियाणा के हितों की बात करनी है। ऐसी सोच हमारे सभी सम्मानित सदस्यों की होनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने भी यहां पर कहा कि हमें यहां पर दलगत राजनीति से उपर उठकर बात करनी चाहिए। वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें पूरे प्रदेश में काम करने के लिए कुछ न कुछ पैसा दिया है। मेरा कहना यह है कि सरकार को अपनी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रखना चाहिए। जब कोई सरकार अपनी कथनी और करनी में फर्क करती है तो फिर उस सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाता है। सरकार को हर जगह विकास के कार्य करवाने चाहिए। (इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पूर्व रोहतक के एक पूर्व मंत्री पर, उसके लडके पर और उस वक्त के आफिसरज जो वहां पर कार्यरत थे, मुकदमा दर्ज हुआ कि उस मंत्री ने रोहतक में काम करवाने के लिए 11 करोड़ रुपये वहां के

विकास के नाम पर खर्च किए हैं। रोहतक जिले के साथ भुरु से ही पक्षपात होता रहा है। वे मुकदमे राजनीति के तहत दर्ज हुए हैं या नहीं इस बात में मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे थे उन्हें बीच में रोकना नहीं जाना चाहिए था। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सम्मानित सदस्य से अनुरोध है कि जो मामला कोर्ट में लम्बित हो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं इनको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर विकास के नाम पर ठगी ठोरा हुआ है। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिली। आप अपने हलके के विकास कराने की बात करें या और जो सुझाव आप देना चाहते हैं, वह दें। एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम कर रही है और दूसरी तरफ आप उनका पक्ष ले रहे हैं। अच्छा यही होगा कि आप अपने हलके के विकास की बात करें।

श्री भादी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा। न ही मैं इस चक्कर में पड़ रहा हूँ कि वह किस पार्टी से है? मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि रोहतक में जो विकास के कार्य हो रहे थे उनको रोकना नहीं जाना चाहिए था। अब वे कार्य रोक दिए गए हैं इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहाँ पर विकास के कार्य तेज किए जाएं ताकि वहाँ की जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार के नोटिस में मैं लाना चाहूँगा

कि रोहतक मे गवर्नमेंट स्कूल मे एक बूस्टर लगाना था। वह बूस्टर भी लगाना बंद कर दिया गया है। यदि वह बूस्टर वहां पर लग जाता तो पीने के पानी की सप्लाई ठीक तरह से हो सकती थी। रोहतक जिला 1966 से चल रहा है। वहां पर पीने के पानी की बहुत कमी है। वहां पर अब भी बहुत सारी कालोनीज ऐसी है जहां पर पीने के पानी नहीं है। ये कालोनीज है, जवाहर कालोनी, सैनी कालोनी, इंदिरा कालोनी व नेहरु कालोनी आदि। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रोहतक मे जो गवर्नमेंट स्कूल मे बूस्टर लगना था उसे लगाया जाना चाहिए ताकि वहां पर लोगो को पीने का पानी अच्छी मात्रा मे मिल सके। अब वहां पर घंटे आधे घंटे के लिए पीने के पानी की सप्लाई हो रही है जिससे उन लोगो की आव यकता पूरी नहीं हो पा रही है। मेरा इस बारे मे केवल इतना ही कहना है कि वहां पर जो विकास के कार्य हो रहे थे उनकी स्पीड बराबर जारी रहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा कहना है कि वहां पर 1962 मे मैडिकल कालेज बना था। उस वक्त की अपेक्षा अब जनसंख्या मे भी काफी बढ़ौतरी हो चुकी है। वहां पर अब मरीजो की बहुत अधिक भीड रहने लग गयी है क्योंकि उस वक्त जो ओ० पी० डी० बनाई गई थी वह उस वक्त की जनसंख्या के हिसाब से बनाई गई थी। इसी तरह से रोहतक मैडिकल कालेज में इन्डोर पै ंट भी पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा मे ऐडमिट हो रहे है। भीड का अधिक रहने का कारण यह है कि पहले की अपेक्षा अब जनसंख्या

कई गुना अधिक बढ़ चुकी है और जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां पर खड़े होने की जगह नहीं है लेकिन उसकी एक्सपेंसों के लिए आज बजट में कुछ प्रोविजन नहीं आया है और न ही कुछ सुपर स्पेशलिटी है। इससे दो नुकसान हो रहे हैं एक तो सारे हरियाणा प्रदेश में केवल एक ही गवर्नमेंट मैडिकल कालेज है जो सिर्फ उन आदमियों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या उनके लिए जो बहुत उंचे लोग हैं जो यहां से रैफर हो कर अपोलो या एस्कोर्ट में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। अगर अपोलो और एस्कोर्ट की सुविधाएं हम मैडिकल कालेज रोहतक में ही दें और उसको एक्सपेंसों में दें, ओपीडी बढ़ जाए, इनडोर बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे प्रदेश में वासियों को काफी फायदा होगा और गवर्नमेंट को भी काफी फायदा होगा क्योंकि गवर्नमेंट को जो राशि रि-इम्बर्स करनी पड़ती है, वह नहीं करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैडिकल कालेज को स्ट्रेंगथन कर ले के लिए, उसकी ओपीडी के लिए कुछ प्रावधान जरूर किया जाए और बजट में उसके लिए और पैसा आना चाहिए। जहां तक स्वास्थ्य की बात थी तो सीवरेज और पानी के हैड में भी जो पैसा रखा गया है वह काफी कम है तथा मैंने जो समस्याएं आपके सामने रखी हैं उनके समाधान के लिए यह पैसा काफी नहीं रहेगा इसलिए मैं चाहूंगा कि रोहतक के लिए कोई स्पेशल ग्रांट दी जाए ताकि वहां पर सीवरेज और पानी की समस्याओं को हल किया जा सके और लोगों को बुनियादी सहूलियतें मिल सकें। तीसरी बात मैं

और कहना चाहूंगा। आदरणीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं वकील हूँ। यह बात मैं भी समझता हूँ लेकिन मैं विपक्ष में आ गया और विपक्ष के विधायक के साथ आज राज्य में कैसा बर्ताव हो रहा है वह मैं मुख्य मंत्री के सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले मैं होटल कलिंग में था। रात को पौने ग्याहर बजे का टाईम था और होटल में दो आदमी आए। उस वक्त होटल बंद हो चुका था उन आदमियों ने कहा कि खाना खाना है। होटल बंद हो चुका था और सारे एम्पलायज जा चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने गोलियां चलाईं। क्यों चलाईं? भायद मैं विपक्ष का विधायक था इसलिए चलाईं या उसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी, उसका मुझे कुछ पता नहीं है और आज मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसकी इनकवायरी होना चाहिए क्योंकि उस वक्त टैलीफोन कर दिया गया था और पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने वह ऐस्टीम तो पकड़ ली लेकिन वे मुलजिम आज तक पकड़े नहीं गए हैं। कारण क्या है, वे कौन हैं, किस कांसीप्रसी के तहत वे आए थे और क्या करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसकी इनकवायरी होना चाहिए और जो दोषी है उनको पकड़ा जाना चाहिए ताकि एक भय का वातावरण जो बन गया है वह दूर हो जाए और हम सब ठीक तरीके से रह सकें (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी स्कीम अच्छी है लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं इनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट इम्पलायज

का भुगतान ट्रेजरी के थ्रू होता है उससे पैँ इन की राशि काजो मिसयूज होता है वह बन्द हो जाएगा और हर महीने की पहली तारीख को बूढो, विकलांगो, विधवाओ आदि को बैंक के थ्रू पैँ इन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद मै कुछ और बातें भी आपके सामने रखना चाहूंगा। इस बजट मे कोई ऐसा टैक्स नही लगाया गया है लेकिन पहले हरियाणा मे 100/- रुपये तक के जुते पर टैक्स फ्री था आज इस पर 5% टैक्स लगाया गया है लेकिन हमारे साथ लगते प्रदे ा दिल्ली में 200/- रुपये तक के जुते टैक्स फ्री है। हम भी अगर 100/- या 200/- रुपये तक के जुते को टैक्स से ऐक्सम्पट कर दे तो गरीब आदमियो के लिए बहुत बडी सुविधा होगी और इससे वे भाई फायदा उठा सकेंगे। जिनके पास ज्यादा पैसा नही है। दूसरी बात मै किसान की कहना चाहूंगा। किसार गेहूं, चना, जौ या दूसरी फसल ले कर मण्डी मे आता है तो उस पर साढे ग्यारह परसेंट टैक्स पडता है। इसमे 4% टैक्स, 4% मार्किट फीस, अढाई फिसदी डामी और 1% लेबर लगती है। व्यापारी वर्ग बडा हो ियार है और वह साढे ग्यारह परसेंट की कीमत किसान को कम देता है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम यह खर्चा काट दें तो जो पैसा व्यापारी किसान को कम देता है तो किसान जब माल लेकर मण्डी मे आए तो उसको ज्यादा पैसा मिल सकता हैं यह बात किसान के हित में है और किसान जब मण्डी मे माल लेकर आएगा तो उसकी जो ऐक्सप्लायटे इन हो रही है, वह नही होगी इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह काम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मै यह कहना चाहूंगा कि दालो पर 8:

टैक्स लगा दिया लेकिन दिल्ली में दालों पर टैक्स नहीं है। जो टैक्स दिल्ली में नहीं है अगर वह याह पर लगाया जाएगा तो उससे व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा और हम सब भाईयों को नुकसान होगा। इसी तरह से खल, तुड़ी और पतुआ आहार पर भी 4% टैक्स लगा हुआ है लेकिन यह टैक्स दूसरी जगहों पर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री चन्द्र भाटिया (फरीदाबाद): आदरणीय स्पीकर साहब, वित्त मंत्री सम्पत सिंह जी ने वर्ष 2000-2001 का जो बजट सदन में रखा है मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बजट में जनहित के बहुत से आंकड़े हैं जो जनता को आकर्षित करते हैं। मेरे से पहले बजट पर बोलते हुए विपक्ष के साथियों ने काफी कुछ कहा और कुछ इसके विरोध में बोलने के लिए खड़े हुए थे। सही मायने में उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले भादी लाल जी ने कहा कि सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। मांगे राम जी ने भी अपने समय में बोलते टैक्स न बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया। हरियाणा की जनता ने इस बजट को बहुत ही सराहनीय बताया है। विपक्ष के साथी बार बार यह कह रहे हैं कि यह बजट सही नहीं है। सर, मन तो उनका भी मान रहा है कि यह बजट बहुत अच्छा है लेकिन

वे इस सदन में विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं इसलिए उन्होंने इसका विरोध में बोलना ही है। अध्यक्ष महोदय, हमसे पहले जिनका राज यहां पर होता था आज वे विरोधी पक्ष में बैठे हैं। उन्होंने अपने समय में अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट बन्द कर दी थी और चौधरी और प्रकाश चौटाला जी ने उस समय इसका बहुत विरोध किया था लेकिन बंसी लाल जी ने माना नहीं। आज हरियाणा की जनता ने उन सभी साथियों को विपक्ष में बैठा रखा है। अध्यक्ष महोदय, बुजुर्गों के लिए जो पैसों को दोगुना किया है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। पहले 100 रुपये पैसों मिलती थी और उसको देने का काम चौधरी देवी लाल जी ने किया था। अब बुजुर्गों को इस पैसों से बहुत राहत मिलती है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर उसमें कोई कमी है तो वह ये बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता इसको बहुत ही सराहनीय कदम बता रही है। हमारे विपक्ष के भाई भी उसका बार बार विरोध करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारे विपक्ष के साथी खड़े होकर बजट का विरोध भी करते हैं वहीं बाद में अपने हलके की बातें भी कहते हैं। ये लोग पहले सरकारों में रहे हैं अध्यक्ष, इससे पहले जब कांग्रेस की हकूमत थी और वे लोग जब हरियाणा के हितों, हरियाणा के लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रहे थे तो लोगों ने उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी को सत्ता सौंपी। चौधरी बंसी लाल जी का भी तीन साढ़े तीन साल तक राज रहा और हम भी उस सरकार में होते थे। उस समय हम अपनी बात को अपनी पार्टी के अंदर और

सरकार मे मुख्य मंत्री के सामने बार बार रखते थे। हमारे कांग्रेस के लोग भी उसी चीज का विरोध यहां पर करते थे और चौधरी बंसी लाल जी को गालियां निकाला करते थे लेकिन अध्यक्ष महोदय, अचानक ही कांग्रेस पार्टी ने बंसी लाल जी को समर्थन भी दे दिया। जब चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी बंसी लाल जी के गलत कामों का विरोध किया करते थे और जब हम भी उस सरकार में रहकर मुख्य मंत्री के सामने अपनी बातों को कहते थे तो उस समय चौटाला साहब और कांग्रेस के साथी भी कहते कि हमारी बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, हम तो सरकार में रहकर भी बोलते थे उस समय हमारे विपक्ष के साथी थपथपाकर कहते थे कि हम सही बातें कह रहे हैं लेकिन अचानक ही चौधरी बंसी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने उस समय समर्थन दे दिया, जब हमने वापस लिया था। हमें तो उस समय कहा जाता था कि हम गलत हैं लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लोग उनको साढ़े तीन साल तक गालियां निकाला करते थे उन लोगों ने सरकार को समर्थन दे दिया था। अध्यक्ष महोदय, जो लोग हरियाणा की जनता के साथ इस तरह खिलवाड़ करते हैं वह उनको दोबारा नहीं आने देती। एक मौका चौटाला साहब को मिला और उन्होंने 6 महीने के अंदर ही बहुत विकास के काम किए। जब उनका 6 महीने का समय चल रहा था तो कांग्रेस के लोग यह कहते थे कि इस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि यह सरकार उनहोंने जोड़ तोड़ करके बनायी है। इसलिए दोबारा से चुनाव करवाएं जाने चाहिए। अगर जनता इनको अच्छा समझेगी तो इनको

दोबारा मुख्य मंत्री बना देगी उस समय ये कहते थे कि मुख्य मंत्री जनता की मर्जी से नहीं बल्कि जोड़तोड़ करके बने हैं लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए तो पिछले 6-7 महीनों में चौटाला साहब ने जो काम किए थे उनको देखकर हरियाणा की जनता ने उनको फिर से चुनकर मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पहले सदन के कुछ सदस्यों ने कहा था कि चुनाव के अंदर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया क्योंकि उस दौरान जगह जगह पर काम किए गए, गांव गांव में खंजड़े बनाये गये, नालियां बनाई गईं और स्कूलों को बनाने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने तो चुनावों के दौरान किसी भी बात का जिक्र नहीं किया था। कांग्रेस की भी हकूमत रही थी इनका भी राज था लेकिन उस समय तो केवल पत्थर ही लगे हुए थे जिन पर आज तक भी काम नहीं हुआ है। इसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने भी बताया था। लेकिन चौटाला साहब ने जिन बातों की घोषणा की वह पूरी हुई। पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने 90 विधान सभा क्षेत्रों में घूम घूम कर खुले दरबार लगे और आम आदमी की बात सुनी। लोगों को लगता था कि मुख्य मंत्री जी हमारी सीधी बात सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछली चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में हम भी विधायक थे। हम तो पहली बार चुनकर आए थे इस बार फरीदाबाद की जनता ने दोबारा से मौका दिया और हमें विधान सभा के अंदर चुनकर भेजा। हमने तो वह समय देखा जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे तो आम जनता को उनसे मिलने की बात तो दूर की

थी, विधायको और मंत्रियों की बात भी नहीं सुनी जाती थी। आज जब हरियाणा की जनता के बीच में चौधरी और प्रकाश चौटाला जी जाते हैं तो आम आदमी यही सोचता है कि यह मुख्य मंत्री हमारा अपना है आम आदमी भी खुलेपन से अपनी बात कह सकता है। इन बातों को लेकर हमारे कांग्रेस के साथी बेचैन हैं। हमने फरीदाबाद हलके के बारे में अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा था। चौधरी बंसीलाल जी बैठे नहीं हैं। इन्होंने भी हमारे साथ बड़ी ज्यादातियां की हैं। जब हमारे हलके के गरीब लोगों पर उनकी बस्तियों पर बुलडोजर चलते थे और हमारे यहां विकास के काम नहीं होते थे तब हम अपने हलके के लोगों की बात को यहां पर कहा करते थे हमारी बातें सरकार को रास नहीं आती थी तो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमें बनाए जाते थे लेकिन क्योंकि हमारे पीछे फरीदाबाद की जनता थी इसलिए हमने उन ज्यादातियों की परवाह नहीं की और अपने हलके के लोगों की मांगों को मजबूती से यहां रखा। मेरे हलके में स्लम बस्तियां भी हैं और वहां सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है थोड़े समय जब हमारा चौधरी बंसी लाल से झगडा चल रहा था वह हलके के विकास की बात को लेकर था। अभी भी हमारे हलके में काफी कमियां हैं चुनावों में जब हम जनता से वोट मांगने जाते हैं तो उनसे तरह तरह के वायदे करके आते हैं कि हम जीत गए तो तुम्हारे ये काम करवाएंगे वह काम करवाएंगे। स्लम बस्तियों के लिए केन्द्र सरकार से पैसा आता है और वह पैसा स्लम बस्तियों पर खर्च किया जाता है लेकिन हमारे हलके में वह उसके आसपास बल्लभगढ़, एन0 आई0 टी0 और

पुराने फरीदाबाद इन तीनों में जो स्लम बस्तियाँ हैं उनमें काम नहीं होता है पिछली बंसी लाल की सरकार में भी हमने इन बातों को बहुत जोरदार तरीके से उठाया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया मुझ से पूर्व मेरे हलके से कांग्रेस के नुमाइन्दे हुआ करते थे उन्होंने भी फरीदाबाद की जनता के साथ बहुत ज्यादा ज्यादाियाँ की थी। हम तो विधायक रहे थे लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार में तो वहाँ से मंत्री रहे लेकिन उनके मुन्त्री होते हुए उस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ। कांग्रेस की हकूमत में हमारे फरीदाबाद की जनता पर हाउस टैक्स लगाया था और कांग्रेस सर्वे होता तो यह हाउस टैक्स 10 गुणा हो जाएगा। फरीदाबाद की जनता 10 गुणा हाउस टैक्स नहीं दे सकती थी। मैंने पिछले सदन में यह बात उठाई थी। तब मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमने इस हाउस टैक्स को ठीक करवाएंगे। अब उस पर रोक लगी हुई है। सिर्फ फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हाउस टैक्स को ठीक कराने की बात मुख्य मंत्री जी ने कही थी। हमारे विपक्ष के साथी अपने हलके की बात को कहते हैं कि हम यह कहना चाहेंगे कि उस समय तो राज होता था। तब भी काम नहीं होता था आज अच्छे काम हो रहे हैं उन अच्छे कामों पर भी विपक्षी भाईयो द्वारा विरोध किया जा रहा है जहाँ तक सड़के और नाली और पानी की बात कही। जब कांग्रेस की सरकार थी और उनका राज था उस समय मेरे हलके में सड़को का काम हुआ, न नालो का काम हुआ और न ही पानी के बारे में कोई काम हुआ। उस समय वे काम करा सकते थे। मैं विपक्ष के भाईयो को कहना

चाहता हूँ कि वे चौधरी औम प्रकाश चौटाला से अपने हलको का काम कराएंगे क्योंकि चौधरी औम प्रकाश चौटाला कभी किसी सदस्य में फर्क नहीं रखते। इस बात का प्रमाण उन्होंने 90 हलको में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करके दिया है। मैं अपने विपक्ष के भाईयो को कहूँगा कि अगर यह सरकार अच्छे काम करती है तो उस काम की सराहना करें। इसके साथी ही अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। साथ ही मैं वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अच्चा बजट पेश किया।

श्री लछमन दास अरोडा: स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, हमें भी बजट पर बोलने का समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि जिस सदस्य को अब तक बोलने का समय नहीं मिला है उसको पहले मौका दिया जाये।

श्री लछमन दास अरोडा: स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं इस सदन में विराजमान दसवीं विधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ माननीय वित्त मंत्री महोदय भाई सम्पत सिंह जी ने जो बजट पेश किया है मैं उस बजट को टैक्स फ्री बजट कहूँगा। क्योंकि इस बजट के

रिजल्ट्स तो हमें आगे आने वाले सै 1990 तक ही मिल पाएंगे। इसलिए उस वक़्त ही मैं इस बजट पर कोई बात कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने हलके सिरसा के बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी को भायद याद होगा कि 1990 में जब ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सी0 एम0 के0 कालेज सिरसा में एक समारोह में उन्होंने एक बात का ऐलान किया था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, का रिजनल सेंटर सिरसा में खोल दिया जाएगा। उस समय 14 महीने तक ये मुख्य मंत्री रह 'लेकिन किन्हीं कारणों से किसी वजह से उस रिजनल सेंटर को नहीं खोल पाए। उसके बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और कांग्रेस की सरकार ने गांव फुल्का में 100 एकड़ जमीन ऐक्वाययर की और एक करोड़ रुपये की लागत से इस रिजनल सेंटर के लिए बिल्डिंग बनाई। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं रही। उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी का राज इस प्रदेश में आया और चौधरी बंसी लाल जी ने उस कार्य को वहीं का वहीं ठप्प करवा दिया। भवन बनाया गया था उस पर ताला लगवाया गया। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस रिजनल सेंटर को जल्दी से जल्दी चालू किया जाये क्योंकि सरकार का पैसा लगा हुआ है अगर रिजनल सेंटर नहीं खुलता है तो सरकार का सारा पैसा बर्बाद हो जायेगा। जहां तक सिरसा भाहर के बाई पास की बात है। सिरसा भाहर में जो फाटक है उस पर इतनी भीड़ लगी रहती है और वह फाटक ज्यादातर बन्द रहता है। अगर किसी आदमी को मैडिकल हैल्प की जरूरत पड जाये तो उस आदमी को

उस फाटक की वजह से समय पर मैडिकल हैलप नहीं मिल सकती। मुझे याद है कि पिछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिरसा बाई पास के लिए एक करोड रुपय मंजूर किया था लेकिन उसके बाद वह सरकार चली गई। वह एक करोड रुपया पता नहीं लैप्स हो गया या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। मेरी खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह विनती है कि उस बाई पास को जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक फोर लेनिंग की बात है, पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी जिले हैं वहां नै नाल हाइवे है तथा सडके बनी हुई है लेकिन सिरसा जो कि मुख्यमंत्री महोदय का होम डिस्ट्रिक्ट भी है वहां पर फोर लेनिंग सडके नहीं बनी हुई है इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि वे सिरसा के अंदर जल्दी ही सडको को फोर लेनिंग करवाने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सिरसा मे रेलवे कोसिंग पर ओवर ब्रिज की चर्चा काफी लम्बे समय से चली आ रही है परंतु पता नहीं क्यों यह चर्चा कामयाब नहीं हो पाती और वह ब्रिज नहीं बन पाता इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस मे यह बात लाना चाहता हूं कि वे रेलवे कोसिंग पर भीघ्र ही ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीवरेज मास्टर प्लान की बात है, बहुत लम्बे समय से यह कोि । । हो रही है कि यह मसला हल हो जाए। ज्यों ज्यों हम इस मसले को हल करते है त्यों त्यों यह मामला और बिगडता जा रहा है। इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाया जाए और इसको लागू किया जाए ताकि इस मसले का हल

हो सके। सिरसा में जब बारिश होती है तो बारिश के पानी की निकासी का कोई रास्ता ही नहीं होता है और हालत यह बन जाती है कि सिरसा भाहर एक तालाब बन जाता है, इसके कारण लोगों को बहुत मुसीबतों का सामान करना पड़ता है। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे वाटर वर्क्स का पानी उन कालोनियों में सप्लाई करवाने का काम करवाएं। इसके अलावा सिरसा में 25-26 एकड़ जमीन पर भाखड़ा नाम का तालाब है जो आज गन्दगी का अड्डा बन गया है और यह तालाब सिरसा भाहर के सैंटर में पड़ता है।

1983-85 में हमने भारत सरकार से कोर्षा बनाने के लिए 50 लाख रुपये सैंकटन करवाए परंतु सरकार बदलने के बाद वह रुपया लैप्स हो गया और वह पैसा वहां लग नहीं पाया इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि टूरिज्म विभाग की तरफ से उस तालाब को साफ करवा के वहां एक टूरिस्ट कम्प्लैक्स बनवाया जाए ताकि लोगों को सैर करने की जगह मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिरसा भाहर गुरुओं की नगरी है, सच्चा सौदा वहां पर है, राधा स्वामी वहां पर है, नामधारी वहां पर है, लाखों की संख्या में वहां लोग इकट्ठे होते हैं। जहां तक सिरसा के नक्शे की बात है सारे हरियाणा में सिरसा के नक्शे के मुकाबले किसी भाहर का नक्शा इतना सुन्दर बना हुआ नहीं है। अगर सिरसा के सभी विकास के कार्य ठीक ढंग से हों तो सिरसा भाहर राजधानी बनाने के काबिल है। वहां पर

बार बार नई राजधानी बनाने की बात होती है इसलिए सिरसा को राजधानी बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय जी ने गवर्नर ऐड्रेस पर बोलते हुए पण्डित को बढाने का भी जिक्र किया था। हिसार मे लाइव स्टाक फार्म मे रिसर्च सेंटर है उसके माध्यम से सिरसा मे भी एक ब्रांच खोली जाए क्योंकि सिरसा मे भी अच्छी नसल की भैंसे है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिरसा भाहर की मार्किट के अंदर एक मीट मार्किट है यदि उसको मार्किट से बाहर निकाल दिया जाए तो वह मार्किट एवन मार्किट बन सकती है। अध्यक्ष महोदय, इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हू।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे गुजारि है कि आप समय निर्धारित करके दे कि बजट पर कितना समय अभी सभी साथियो ने बोलना है और हम किस समय जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी दो घंटे मे विपक्ष के तकरीबन सभी सदस्य बोल लेंगे। उसके बाद 13:00 बजे 3 बजे आप बोल लेना।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नही बोल पाये। पहले उन्हे बोलने का अवसर दिया जाये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, तीन पार्टियों के जो एक एक सदस्य हैं, उन्हें भी तो बजट पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, आपकी पार्टी की सदस्य संख्या सदन के 90वें हिस्से के बराबर है। उससे ज्यादा समय आप ले चुके हैं। प्लीज आप बैठ जायें। (गोर एवं व्यवधान) दलाल साहब आपकी कालिंग अटैं इन मो इन कल लगी हुई है आप उस पर कल बोल लेना। प्लीज आप बैठ जाएं। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, हम तो बजट पर बोलने के लिए समय मांग रहे हैं। हमें बजट पर बोलने के लिए समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप हमें बजट पर बोलने के लिए चाहे थोड़ा मय दें। लेकिन समय जरूर दें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि आप सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ जायें। 5 मिनट तो आप लोगो ने भाोर— ाराबे मे ही नश्ट कर दिये। प्लीज आप सभी बैठें।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अच्छे सदभावनापूर्ण वातावरण में यह सदन चल रहा है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने सबको खुले दिन से बोलने के

लिए समय दिया, इसके लिए हम पहले भी आपका आभार व्यक्त कर चुके हैं और पुनः भी करते हैं। विपक्ष के नेता की इस बात से भी हम सहमत हैं कि जो सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल चुके हैं, उनके अलावा जो नहीं बोले, सर्वप्रथम उन सबको समय दिया जाये। ताकि हरियाणा विधान सभा के 90 के 90 सदस्य बोल सकें। फिर भी अगर समय होगा तो दूसरों को भी बोलने का अवसर दिया जायेगा। लेकिन कुछ लोग यहां पर अपनी ठेकेदारी क्यों समझते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ठेकेदारी की बात कैसे कर सकते हैं। मैं तो जनता द्वारा चुनकर यहां आया हूं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप सब बैठिये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, मेरे हलके के लोगो ने मुझे चुनकर भेजा है और चौटाला साहब ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। आप मुझे इस बारे में रुलिंग दें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप सब बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, मैं किसी की मेहरबानी से यहां नहीं आया। बल्कि जनता द्वारा यहां पर चुनकर आया हूं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सभी मैम्बर बराबर है और सब को बराबर समय मिलेगा। (तोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, हम भी बराबर का समय मांग रहे है। (तोर)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप दूसरो को बोलने देंगे या नही। अगर समय होगा तो आपको जरूर दूंगा। अभी आप बैठिये। आपका नब्बेवां हिस्सा है और आपको नब्बेवें हिस्से से ज्यादा समय दूंगा। अभी जो सदस्य नही बोले है उनको बोलने दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारे हिस्से का हमें समय देंगे तो ठीक है।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा ये कह रहे है कि मै चुनकर आया हूँ और किसी के रहमो कर्म पर नही है तो मै इनको बताना चाहूंगा कि यहां पर हम मैम्बर चुनकर आया है। केवल चौटाला साहब दो जगह से चुनकर आये और एक जगह उन्होने खाली कर दी है। हर मैम्बर को आपने पूरा समय बोलने के लिए दिया है। सदन के नेता और विपक्ष के नेता दोनो ने यह कमिटमेंट भी की है कि जिनको बोलने का मौका नही मिला उनको समय मिलना चाहिए। आप उनको समय दे भी रहे है चाहे किसी पार्टी का सिंगल मैम्बर हो उसको भी पूरा समय आपने दिया। अध्यक्ष महोदय, जितना एकोमोडेट हर मैम्बर को आप कर

रहे है उतना तो भायद आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इसलिए किसी का यहां एस्प नि कास्ट की बात करना ठीक नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, मैंने एस्प नि वाली कोई बात नहीं की है। (गोर) कोई इस तरह से हमें दबाना चाहे तो हम नहीं दबेंगे। (गोर)

श्री बलबीर पाल भाह (पानीपत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पुनः बोलने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें कोई नये कर नहीं लगाये। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि छः महीने के बाद इसके जो रिस्क न होंगे उसके उपर दोबारा हम यहां चर्चा करेंगे। अभी तो मुझे एक ही बात कहनी है जो हरियाणा की ज्वलंत समस्या है। इसके उपर बोलकर मैं बैठ जाऊंगा। पानीपत की मैं कोई बात नहीं कर रहा। यह समस्या मेवात से जुड़ी हुई है। मेवात में गौक मी हो रही है जबकि हरियाणा में गौक मी बन्द है जबकि मुख्य मंत्री जी ने भापथ कुरुक्षेत्र में जी जहां गौपालक श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि हमारे मेवात के भाई किस कारणवश गौक मी करते हैं। ये सभी भाई पहले हिन्दु थे, बाद में समाज की किसी व्यवस्था के कारण इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया और हमसे अलग हो गये। इसके अलावा जो

इनके अंदर बहने वाला खून है वह भी हिन्दु का है, हिन्दुस्तानी का है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अकबर के काल में भी गौक गी नहीं होती थी लेकिन आज मेवात में गौक गी हो रही हैं। क्यों हो रही है, इसका कारण हमें जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मेवात पिछड़ा हुआ इलाका है और हजरत मोहम्मद साहब ने भी एक बात कही थी कि केवल आपाकाल में ही गौक गी की जाए। जब तक कोई और साधन है तब तक गौ को मारा न जाए लेकिन आज गौ को मारा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्टडी किया है उसमें पाया है कि मेवात के लोग अपनी स्वेच्छा से गौक गी नहीं कर रहे हैं। गौक गी करना उनकी मजबूरी है क्योंकि आने वाली जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने मेवात के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। सैल्फ एम्प्लायमेंट के कोई साधन नहीं जुटाये और न ही वहां पर कोई हैवी इंडस्ट्री लगाई। इस तरह के कोई कार्य नहीं किए जिससे कि मेवात के लोग गौक गी को छोड़ दें। वे लोग मजबूरी में गौक गी कर रहे हैं। वे जो गौक गी कर रहे हैं वे अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। वहां पर सारा मांस दिल्ली जाता है और वहां से जो लोग मांस के निर्यात का काम करते हैं उनके द्वारा उसे विदेशों में भेजा जाता है। इस बारे में मेरा कहना है कि मेवात के लोगों के लिए इस बजट में कुछ न कुछ प्रावधान अवश्य किया जाये ताकि वहां के जो नौजवान साथी हैं वे इस गौक गी के काम को छोड़ सकें और वे पहले की तरह होली व दिवाली का त्यौहार सभी के साथ मिलकर मना सकें ताकि वे फिर से हरियाणा की

मुख्यधारा मे भामिल हो सके। यह तभी हो सकता है जब वहां से गौक ि की लानत को खत्म किया जा सकेगा। वहां पर जितनी अधिक मात्रा मे गौक ि होती है उसका मांस वहां पर खाया नहीं जाता बल्कि बाहर भेजा जाता है। वहां की गरीबी ही इस जड की मूल ज्वलंत समस्या है। यदि हम इसको रोक पायेंगे तो यह अपने आप मे एक बहुत बडा उद्धार वहां के लिए हो सकेगा और उन लोगो का भी उद्धार हो केगा जो इस काम मे लगे हुए है। गौक ि को रोकना एक धार्मिक कार्य है। गौक ि होने से लोगो की धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचती है। जो लोग इस काम मे लगे हुए है उनको सैल्फ एम्पलायमेंट के तहत नौकरी दी जाये और फिर उनसे लिखवा कर ले लिया जाये कि वे भविश्य मे गौक ि नहीं करेंगे। यदि हम ऐा कर पायेंगे तो यह हिन्दू समाज के लिए और मेवात के लोगो के लिए एक महान कार्य होगा। धन्यवाद।

प ँ पालन राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद इलियास): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे आदरणीय भाह साहब ने कहा कि मेवात मे गौक ि हो रही है उसे रोका जाना चाहिए। मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मेवात एरिया का जितना ि ाक्षित वर्ग है, योग्य वर्ग है या यों कहिए कि जो सम्मानित वर्ग है वह नहीं चाहता कि गौक ि हो। वहां पर पढे लिखे, समझदार लोगो का व वहां की 36 बिरादरियो

का विचार है कि गौक ी नहीं होनी चाहिए। मेवात मे केवल मेव ही नहीं रहते बल्कि 36 बिरादरी के लोग रहते है। वहां का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि गौक ी हो। मेव जाति के लोग गौक ी का काम नहीं करते। इसमें कोई दो राय नहीं कि वह एरिया बहुत ही बैकवर्ड एरिया है और वहां पर बहुत ही गरीबी है। भाह साहब ने मेव जाति पर जो आरोप लगाया है कि मेव लोग गौक ी कर रहे है यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद व निराधार है क्योंकि मेव जाति के लोग गौक ी नहीं कर रहे। पहले तो मैं खुद कहता हूं वहां पर 36 बिरादरी के आदमी है वहां पर न कोई गौक ी करता है न ऐसी कोई बात है। (विघ्न) जब से चौधरी औम प्रका । चौटाला जी ने हरियाणा मे वजीरेआला की हैसियत से कार्यभार सम्भाला है, मैं अपनी नॉलेज के आधार पर कहता हूं कि पिछले छः महीने के अंदर कही पर गौ का कोई जिक्र नहीं आया है। इसके लिए मैं चौधरी साहब की सराहना करता हूं और मैं खुद इस बात की ताईद भी करता हूं तथा अपनी तरफ से खुद छुट भी देता हूं कि हम चौधरी साहब के सिपाही है और सरकार की हैसियत से हम मेवात मे गौक ी नहीं होने देंगे। मैं हाउस को भी वि वास दिलाना हूं क्योंकि चौधरी साहब की खुद की नीति और पालिसी भी यही रही है इसलिए मेवात मे गौक ी नहीं होगी। न तो हम गौक ी कर सराहना करेंगे और न गौक ी होने देंगे (विघ्न एवं भाोर) जहां तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेवात वाकई मे ही गरीबी से मुत्सिर है और हमें मालूम है कि चौधरी साहब जी मेवात की किसी चीज से

अनभिज्ञ नहीं है और पूरी तरह से परिचित है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह सन् 1987 में जब चौधरी देवी लाल जी हरियाणा के रहनुमा थे उनही के नक्शे केकदम पर चलकर माननीय और प्रकाश चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं तो किसी प्रकार से मेवात को पीछे नहीं रहेने देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है कि जैसे पहले चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में मेवात ने तरक्की की है चाहे वह रोजगार की बात थी किसी दूसरी चीज की बात थी मुख्तलिफ विभागों की बात थी वैसी ही तरक्की अब भी होगी। थैंक्यू वैरीमच।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी में मेवात के अनदर गौहत्या होती रही है, यह ठीक है। (विधन) इन्होंने माना है (विधन) चाहे इनके पहले राज से होती आ रही है (विधन) मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि गरु जिसे हम अपनी मां कहते हैं और मानते हैं उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार गौ हत्या के उपर कोई आयोग बनाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है, अब आप बैठें। (विधन)

श्री मुहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कर्ण सिंह दलाल जी से एक बात जानना चाहता हूँ।

चौधरी बंसी लाल जी जब मुख्यमंत्री थे और उनका एक प्रोग्राम पुन्हाना के अंदर था तब गौक जी का बात उनके सामने आई तो आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी ने उस वक्त कहा था कि गौक जी तो पहले से होती आई है यह कोई बात नहीं है। भाई दलाल साहब को मैं यह बताना चाहता हूँ जब इनकी सरकार थी तो ये खुद मंत्री थे तो उस वक्त इन्होंने यह बात क्यों नहीं की। भाह साहब ने एक बात और कही है कि पहले हम हिन्दु थे और अब मुसलमान हो गए हैं। मैं भाई से यह गुजारि ा करता हूँ कि माफ कीजिएगा हिन्दुस्तान के अंदर खाने का अधिकार, रहने का अधिकार और धर्म को मानने का अधिकार बहुत पुराने वक्त से है। यह सही बात है कि हम हिन्दु थे लेकिन इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है कि हम कल्मागोयम हुए हैं उसमें हम मुस्तहिक हैं। जब से हमने कलमा पढ लिया तो बात खत्म हो गई उसके बाद के हालात की बात कोई मायने नहीं रखती। उस वक्त कहां था, क्या था, क्यों कन्वर्ट हुए, कैसे कन्वर्ट हुए। माफी चाहूंगा कि यह मामला हाउस के अंदर नहीं कहना चाहिए था। बलबीर भाह जी को ऐसी बात यहां पर नहीं उठानी चाहिए थी, यह सब को बराबर का अधिकार है और अपनी प्रवृत्ति की बात है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बलबीर पाल भाह द्वारा

श्री बलबीर पाल भाह: अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैंने बहुत स्पष्ट भावों में कहा है कि उस समय ऐसे हालात हुए जिससे इन्होंने कन्वर्सन की। मैं इनकी किसी बात के खिलाफ नहीं हूँ। हम और आप भाई हैं मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता था हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि मेवात के अंदर गौक भी होती रही है वह बन्द होनी चाहिए, मैं सरकार से यह मांग करता हूँ। ये किसी धर्म को माने, हम किसी धर्म को माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री मोहम्मद इलियास: हम इसके लिए पहले से ही वचनबद्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री बलबीर पाल भाह: हम आपका इसके लिए धन्यवाद करते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस विषय में अपनी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष: अब इस टॉपिक पर और डिस्कशन नहीं होगी, आप सब बैठ जायें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर बात कही गई है। आप चाहे तो कार्यवाही देख सकते हैं।

श्री गोपी चन्द: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आडर है। अध्यक्ष महोदय, कभी कोई मैम्बर कही से खड़ा हो जाता है तो

कभी कोई। अध्यक्ष महोदय जी अपनी सीट पर खड़े होते हैं फिर भी ये बोलते रहते हैं। मैं इनको यह बताना चाहूँ कि बाकी मैम्बर्ज भी बोल सकते हैं उनको भी बोलने का अधिकार है। ये बिना इजाजत के नहीं बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। अभी मंत्री जी ने जैसा कहा कि हमारे सामने यह बात आई कि वहाँ पर गौ हत्याए हुई है

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल जी जो कह रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री धर्मपाल (सोहना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कल दिनांक 14-3-2000 को वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह कर रहित है। यह बहुत ही सूझ बूझ का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 3-4 सालों में अराजकता का माहौल बन गया था चाहे वह किसी भी वर्ग की तरफ से हो। विकास नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कोई सुरक्षित ही नहीं था। किसी भी तरफ विकास कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। इसके लिए मैं पिछली सरकारों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को दोषी नहीं ठहराऊँगा क्योंकि यह ठीक नहीं है। इस बजट से उम्मीद होती है कि भाग्यद

पिछली कमियां ठीक हो जाएंगी। जब इस बजट का परिणाम आएगा यह तो उससे ही पता चलेगा। मैं अपनी कांस्टीच्युएंसी सोहना की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। वहां पर सड़को की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पूछो नहीं। वहां पर 3-4 सालों में कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ था। यह मैं मानता हूँ कि अब थोड़ा सा काम हुआ है। किसी काम को न करना अच्छी बात नहीं है। इसके साथ साथ मैं खासतौर पर बताना चाहूंगा जितनी अप्रोच रोडज है। चाहे वल्लभगढ़ रोड है, दिल्ली से अलवर रोड है और चाहे नै नल हाई वे रोड से कहीं को है। ऐसे कई रोडज हैं मैं कितने नाम यहां पर गिनवाऊ। इस बारे में मैं सबसे पहले बाद ग्राहपुर गौलवास सड़क जिसका 8 कि० मी० का टुकड़ा खराब है, का जिक्र करना चाहूंगा। इसकी हालत यह है कि इस पर बस का जाना भी बंद हो गया है। रोडवेज ने अपनी बस वहां पर इसलिए भेजनी बंद कर दी क्योंकि उस सड़क में बहुत गड्ढे थे बस आ जा नहीं सकती थी सब का बहुत नुकसान होता था। इसी तरह से दूसरी सड़क दिल्ली से अलवर रोड पर धामरोड लिंक रोड है इसकी भी बहुत बुरी हालत है इसी तरह से दिल्ली अलवर रोड पर अलीपुर गांव की जो सड़क है उसका भी यही हाल है उसी के साथ साथ एक गढ़ी बाजीपुर को रोड जाती है उसकी भी हालत खराब है। इसी तरह से पिचरसा से वाया वल्लभगढ़ रोड है यह 18-20 कि० मी० तक खराब है। अध्यक्ष महोदय, ये सारी ऐप्रोच रोडज हैं जोकि सारी ही टूटी हुई हैं। इसी तरह से बाद ग्राहपुर से दरबारपुर हसनपुर रोड है उस पर भी बस का आना जाना बंद

है क्योंकि वह टूटी हुई है। इसी तरह से मानेसर से कासन तक की सड़क भी बहुत खराब है। नै नल हाई वे नं० ८ से गांव ग्वालियर की सड़क और खेडकी की सड़क की भी हालत बहुत खराब है। मैं इन सभी सड़कों के बारे में सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनको बनाने की तरफ जल्दी ध्यान दिया जाए और जनता को सुविधा दिलायी जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक जन-स्वास्थ्य की बात है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया था और बजट में भी इसका उल्लेख है। सन् १९९४-९५ में एक स्कीम आई थी जिसमें आधा पैसा भारत सरकार और आधा पैसे हरियाणा सरकार का था। इस स्कीम के तहत पटोदी, सोहना, नारनौंद और कनीना आदि कस्बों को पेयजल की व्यवस्था की गयी थी। सरकार बताए कि इस स्कीम के तहत कितने बोरिंग और ट्यूबवैल्ज लगे? मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि सोहना में कुछ कालोनी में जैसे कि कालोनी, पहाड कालोनी, वार्ड नं० ८ व १० में पीने के पानी नहीं पहुंचा है जबकि सरकार ने दावा किया है कि उसने ७० लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया है लेकिन जिन जगहों का मैंने नाम लिया है वहां पर दस लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस स्कीम को पूरा करवाया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, कृषि तथा उससे संबंधित कार्य ही किसानों की आय के साधन हैं। पं. राज्यपाल का जहां तक सवाल है। आज गया और भैंसे बहुत महंगी हो गयी है। वैसे तो हरियाणा में दूध की मात्र

काफी अच्छी है यह मा मेरे ख्याल मे पूरे दे 1 मे पंजाब के बाद दूसरे नम्बर पर है। यहां पर 621 ग्राम यानि लगभग आधा किलो दूध एक आदमी के लिए उपलब्ध है। यह मात्रा बहुत अच्छी है लेकिन प जुओ के रख-रखाव के लिए और खासकर उनके उपचार के लिएमै सरकार से और सदन के नेता से अनुरोध करुंगा कि पहले इस बारे मे एक स्कीम थी हर जिले मे एक पौली-क्लीनिक बनाने की। इस स्कीम के तहत ही हमारे गुडगांव जिले मे भी एक पौली-क्लीनिक का िालान्यास चौधरी भजन लाल जी ने किया था उस पर सात या आठ लाख रुपये भी खर्च हो चुके थे लेकिन उसके बाद से वह बिल्कुल बंद पडी है। मेरा अनुरोध है कि इस पौली-क्लीनिक को पूरा करवाया जाए। इस क्लीनिक के लिए गांव खनौला वालो ने अपनी बहुत ही महंगी जमीद दी थी। अगर इसको पूरा करवा दिया जातहै तो इसका बहुत ज्यादा फायदा हमारे गुडगांव जिले को मिलेगा। कई बार प जु चारे में सुई या कोई लोहे कीचीज खा जाते है या उनको कोई और बीमारी हो जाती है अगर यह क्लीनिक पूरी हो जाएगी तो इसके द्वारा उनका उपचार अच्छी तरह से हो सकेगी और आपरे ान करके उस बीमारी को भी दूर किया जा सकेगा वे किसान को होता हुआ नुकसान बच जाएगा साथी ही किसान की प जुपालन मे रुचि भी बढेगी। अब मै िाक्षा के बारे मे कहना चाहूंगा। वैसे तो िाक्षा के बारे मे बहुत कुछ किया गया है लेकिन जो तकनीकी िाक्षा है उसे भी महत्व दिया जाना चाहिए। हमारे गांव मानेसर मे जिला गुडगांव की एक पोलिटैक्निक मानेसर

के नाम से कार्यरत है मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि इस पॉलिटैकिनक मे चार ट्रेड सैंकान किए गए थे। 1. मैकेनिकल, 2. इलैक्ट्रोनिक 3. प्लास्टिक इंजीनियरिंग और 4. इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इन चारो मे से एक ही ट्रेड चल रही है इसका कारण यह है कि कुछ तो भवन का अभाव था, लैबोरेट्री भी नहीं बन सकी थी। इसके अलावा यह भी पता चला है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेड है वह नीलोखेडी मे चल रही है मेरा अनुरोध है कि हमारे वहां चारो ट्रेड चालू की जाए। ताकि देहात के बच्चो को आगे बढ़ने का मौका मिल सके और इस इलाके का सुधार हो सके। इसके साथ साथ और कई ऐसी बातें है जो कहने की है जैसे कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र मे मात्र सात दस जमा दो के स्कूल है और भी ऐसे कई इलाके बाकी है जहां 10-10 गावो मे दस जमा दो स्कूल नहीं है। मेरा अनुरोध है कि दस जमा दो स्कूलो को बढ़ावा दिया जाए ताकि हर आदमी को और विशेषकर लडकियो को मौका मिल सके। इन भाब्दो के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मै अपना स्थान लेता हूं।

श्री नफे सिंह राठी (बहादुरगढ): आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद, जैसे कि सभी को ज्ञात है कि पिछले महीने की 22 तारीख को हरियाणा प्रदेश मे असैंबली के चुनाव हुए और किस तरह से चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी नेतृत्व मे हरियाणा की जनता ने समर्थन व्यक्त किया और समर्थन व्यक्त करते हुए सरकार बनाने का पुनः अवसर प्रदान किया।

चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने समर्थन लेते ही जो काम किए उन कामों की लोगों ने सराहना की और हरियाणा में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के स्तर पर उसकी सराहना हुई और इसी कारण चौटाला साहब की सरकार दोबारा सत्ता में आई। आज बजट पर जो चर्चा चल रही है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। प्रोफ़ेसर सम्पत सिंह जी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना भानदार बजट प्रस्तुत किया है जो हरियाणा की जनता के लिए विकास के नये मार्ग खोलेगा और हरियाणा में अमन, चैन, और भांति कायम करेगा। लोगों की भावनाओं की कद्र होगी, आदर होगा। स्पीकर साहब, पिछली सरकार के समय में जिस तरह से हरियाणा में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया वह आपके सामने है। पूरे हरियाणा की जनता जानती है कि चौधरी बंसी लाल के समय में किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई थी। विकास के कार्य नहीं हुए। लोगों से जो वायदे किए गए उनके बरखिलाफ काम करने का काम किया गया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी जिस तरह से कानून व्यवस्था के मामले में और विकास के मामले में बहुत भेदभाव हुआ है। बहादुरगढ़ हलके की बात मैं कहना चाहूँगा। स्पीकर साहब, कांग्रेस सरकार के भासनकाल में बहादुरगढ़ में एक नहीं दो नहीं बल्कि एक दर्जन छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हुए। आठ साल की छोटी छोटी बच्चियों को मार कर फँक दिया जाता था। बेबी किलर कांड होते रहे लेकिन कांग्रेस सरकार आंख मिंच कर बैठी रही और कोई कार्यवाही नहीं की गई। झुठे मुकद्दमे एक

या दो आदमियों के खिलाफ जरूर बनाये गए। लेकिन अब बहादुरगढ़ में कानून व्यवस्था की हालत में काफी सुधार है। मेरे हलके बहादुरगढ़ का 70 किलोमीटर एरिया दिल्ली की सीमा से लगता है दिल्ली के कस्बों नजफगढ़, नांगलोई, चण्डी आदि में जो छोटी छोटी कालोनिया होती है वहां दूसरे स्टेट्स से आकर लोग रहते हैं जिनमें काईम पे के लोग भी होते हैं। वे लोग हरियाणा में दाखिल होकर अपराध करते हैं फिर दिल्ली में चले जाते हैं। बहादुरगढ़ बाहर को हरियाणा प्रदेश का गेट वे आफ हरियाणा कहा जाता है। वे लोग बहादुरगढ़ में काईम करके दिल्ली में भाग जाते हैं। लेकिन जब से चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी की सरकार इस प्रदेश में आई है तब से उन दरिन्दों का हरियाणा प्रदेश में आने पर अंकुश लगा है और बहादुरगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। स्पीकर साहब, इस बजट में दिल्ली की समस्या को हल करने के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है और पिछले बजट के हिसाब से लगभग 142 करोड़ रुपया ज्यादा रखा गया है इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। स्पीकर साहब, जहां तक पानी का सवाल है। मेरे एरिया में 22 टेलें नहरी पानी की है उन 22 टेलों में से 17 टेलें ऐसी थीं जिन पर लगभग आठ साल से पानी नहीं पहुंचता था। लेकिन आपको सुनकर खुशी होगी कि जब से चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी की सरकार इस प्रदेश में आई है तो उसने तमाम रजवाहों की सफाई करवाकर और सभी नहरों की सफाई करवाकर आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। नहरों के मामले में जा 775.

17 करोड रुपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है वह बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। स्पीकर सर, जहाँ तक सड़को का सवाल है। 1995 में प्रदेश में बाढ़ आई थी उस समय चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी लेकिन पूरे प्रदेश में बाढ़ के बाद किसी भी सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई। वे कहते थे कि सड़को को मैंने ही बनवाया है और मैं ही सड़को की मरम्मत और थोकली लगवाने का काम करूँगा। उन्होंने भी सड़को की मरम्मत का काम नहीं करवाया। लेकिन जब से चौधरी अमर प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई है आप देख रहे हैं कि प्रदेश की सड़को की मरम्मत का काम चल रहा है कहीं पर गड्डे भरने का काम चल रहा है तो कहीं पर सड़को की रिपेयर का काम चल रहा है। स्पीकर सर, अब मैं खेलों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली सरकार ने खेलों के मामले में खिलाड़ियों की अनदेखी की है और उसका परिणाम आज यह है कि हरियाणा के खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरियाँ करने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने खिलाड़ियों का नौकरियों से कोटा खत्म करने का काम किया था। 1992 में पुलिस विभाग के खिलाड़ियों को रिवर्ट कर दिया गया था जिसके कारण उन खिलाड़ियों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। जबकि माननीय चौधरी देवी लाल जी ने खिलाड़ियों को नौकरी में कोटा देना भुरु किया था और जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर या अन्तरराष्ट्रीय स्तर का होता उसे नौकरी में प्रमोशन दिया जाता था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने प्रमोशन देने की बजाए रिवर्नि

करने का काम किया। स्पीकर सर, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ इसलिए मैं खिलाड़ी की भावना को जानता हूँ। इन खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जितने भी खिलाड़ियों की रिक्ति की गई है उनकी रिक्ति वापिस लेकर उनको पदोन्नति प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछली बंसी लाल जी की सरकार के समय में जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय हम भी इस सदन के सदस्य थे और आदरणीय औम प्रकाश चौटाला जी भी विपक्ष के लीडर थे किस तरह से बंसी लाल जी ने भाहीदों को दी जाने वाली राशि को दो-दो कर पचास हजार से पांच लाख रुपये करने का काम किया था लेकिन औम प्रकाश चौटाला जी ने आते ही उस राशि को 10 लाख रुपये करने का काम किया इसलिए हरियाणा के लोगों ने पूरी तरह से एकजुट होकर औम प्रकाश चौटाला जी को, चाहे वे किसानों के लिए, चाहे व्यापारियों के लिए, चाहे कर्मचारियों के लिए, चाहे भाहीदों के लिए काम कर रहे थे, जनादेव दी दिए। इसी प्रकार औम प्रकाश चौटाला जी ने चुंगी प्रणाली को खत्म करने का काम किया। यह चुंगी प्रणाली अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही थी। पिछली सरकार ने न केवल व्यापारियों को बल्कि बाहर के रहने वालों को छोटा मोटा सामान बाहर से लाने पर चुंगी लगाकर परेशान करने का काम किया था। औम प्रकाश चौटाला जी ने गन्ने का भाव 110 रुपये और आज ये वही कांग्रेस के लोग इस सरकार पर छिंटाकरी करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की

सरकार मे बिजली की क्या दुर्द गा थी और बंसी लाल जी के टाइम मे भी क्या थी, इस बात को आप सभी जानते है। औम प्रका 1 चौटाला जी ने आते ही बिजली के क्षेत्र में जो काम करके दिखाए है उनसे लोग लाभान्वित और खु 1 हुए है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत चौधरी औम प्रका 1 चौटाला जी मेरे हलके मे गए और वहां जाकर लोगो की समस्याएं सुनी और उनकी तकलीफें दूर करने का काम किया। एक वे मुख्यमंत्री थे जिनसे एम एल ए और मंत्री नही मिल पाया करते थे और एक ये मुख्य मंत्री है जो लोगो के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनकर उनका निराकण करने का प्रयास करते है। 1995 में कांग्रेस की सरकार थी उस समय बहादुरगढ मे आटो मार्किट बनने के लिए 21 एकड जमीन पर दफा 4 और 6 के तहत नोटिफिके 1न हो गई थी और नोटिफिके 1न होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार के मंत्रियो ने मिलकर प्रोपर्टी डिलर्ज और जमींदारो को कहा कि तुम्हे सरकार कुछ नही देगी और उन पर दबाव डालकर उनको 3-3, 4-4 लाख रुपये देकर उनकी जमीने खरीद ली, उन जमीनो मे हरिजनो की भी जमीनें थी। 21 एकड जमीन मे एक कालोनी बनाकर 1200-1200, 1500-1500 रुपये गज के हिसाब से प्लाट काटने का काम किया गया उसके बाद बंसी लाल की सरकार आई जैसा कि अभी भाादी लाल जी ने जिक किया था कि एक पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उस मंत्री का लडका भी उस कालोनी मे हिस्सेदार था और उन्होने करोडो रुपये के वारे-न्यारे किए। इस तरह से लोगो को लूटा गया। पिछली

सरकार मे और उससे भी पहले की कांग्रेस की सरकार मे लोगू पर जुलम और ज्यादातियां हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहादुरगढ भाहर 1162 साल पुराना बसा था और उससमय काएक भाम तानघाट था उसको भी ऐक्वायर कर लिया गया है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पिछली सरकार मे लोगो पर हुए जुल्मो और ज्यादातियो को सुधारा जाए और बहादुरगढ मे कुछ ऐसे कार्य है जो पिछली सरकारो के समय मे नही हो सके और वे इसलिए नही हुए क्योंकि वहां से हमे गा ही अपोजी तान का विधायक रहा है। वहां पर कुछ ऐसे कार्य होने बहुत जरुरी है। जैसे सोहटी सब-माईनर का काम पिछले काफी समयसे नही हुआ है। इसी तरहस से टांडाहेडी नूनामाजरा माईनर है। इसका काम भी पिछले 20 सालो से नही हुआ है। वहां पर यह काम न होने से किसानो को बहुत ज्यादा परे तानी का सामान करना पड रहा है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय जी से नम्र निवेदन है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवायें। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त सांखोल और जसराणा माईनर है। उन पर भी विगत 20 साल से काम नही हुआ है। यह काम भी मुख्यमंत्री महोदय जल्दी से करवायें ताकि वहां किसानो की समस्या दूर हो। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे 29 नगरपालिकाएं तोड दी है। इस बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नगरपालिका तोडी गई है उसका स्टाफ उसके नजदीक लगती नगरपालिका मे ही भेजा जाये। खरखौदा नगरपालिका तोडी गई है उसका स्टाफ इसके लगते नगरपालिका

मे ही भेजा जायें। स्पीकर सर, बहादुरगढ मे सिवरेज सिस्टम में बडी भारी समस्या है और इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब वहां पर डिस्पोजल सिस्टम लगाया जाये। इस सिस्टम के लिए वहां पर 4 एकड जमीन के लिए दफा 4 और दफा 6 के तहत नोटिफिके ान हो चुकी है। इस बारे में मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर दफा 9 के तहत नोटिफिके ान करके जल्दी से जल्दी वहा ं पर काम भुरु किया जाये। स्पीकर सर, इसी के साथ जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है जिसमें कृशि, व्यापार, प णुपालन, उद्योग और पर्यावरण, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ि ाक्षा, कानून-व्यवस्था, नहरो, पीने के पानी आदि को ध्यान मे रखकर जो प्रावधान किया गया है उसके लिए वे बधाई के पात्र है। इस तरह से संपत सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ और सभी माननीय साथियो से निवेदन करता हूँ कि वे भी इसका समर्थन करें। धन्यवाद।

श्री राम कुमार (गोहाना): परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस गरिमामय सदन मे मेरे को इस भाताब्दी के प्रथम वार्षिक बजट का समर्थन करने के लिए आपने समय दिया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जो विकास का बजट पे ा किया है इसकी मैं प्र ांसा करता हूँ। वाकई मैं यह बजट हरियाणा प्रदे ा की प्रगति के लिये बनाया गया है। यह बजट आज तक का सबसे अधिक सार्थक और उपयोगी बजट है।

इस बजट से यह साफ झलकता है कि सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए सजग है और सही अर्थों में हरियाणा का विकास करना चाहती है। आज से पहले इतना बढ़िया, सार्थक और उपयोगी बजट कभी नहीं आया। इस बजट में बिक्री कर फार्म संख्या 15 को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। कर रहित बजट पेश किया गया है। इस बजट में सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष प्रावधान किया है तथा ग्रामीण व भाहरी क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार सभी उपभोक्ताओं को नियमित बिजली सप्लाई करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने यह भी एक सराहनीय कार्य किया है। सरकार ने इस बजट में गरीबी कम करने, आया तथा रोजगार के अवसर जुटाने, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा अन्य कृषि संबंधी विकास कार्यों का प्रावधान करके एक सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तम स्वास्थ्य मानव जीवन की सर्वोत्तम पूंजी है। सरकार ने इस सर्वोत्तम पूंजी के परिक्षण के लिए राज्य में 2299 उपकेन्द्रों, 401 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 44 अस्पतालों का प्रबंध करने का प्रावधान किया है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। इस बजट में गावों तथा भाहरों में बसने वाली 36 बिरादरियों के लोगों के लिए जो सराहनीय कार्य करने का प्रावधान किया गया है उसके लिए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। यह बजट प्रदेश की तरक्की का बजट है। स्पीकर सर, मेरे हलके गोहाना में बहुत सी समस्याएं हैं

जिनके बारे में मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 50 सालों से गोहाना में एक भुगर मिल की स्थापना किए जाने की मांग चली आ रही थी। चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आने से पहले भी बहुत सी सरकारें आईं लेकिन किसी ने भी गोहाना हलके के लोगों की सुनवाई नहीं की। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने सत्ता में आते ही एक ही कलम से गोहाना के लोगों की इस मांग को स्वीकार कर लिया। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह बिसला चेयर पर पदासीन हुए) सभापति महोदय, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए उनसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नवम्बर से पहले पहले इस भुगर मिल को चालू करा दें ताकि जिन किसानों ने अपना गन्ना बो रखा है उनका गन्ना नवम्बर में इस मिल में लाया जा सके। सभापति महोदय, मरे क्षेत्र गोहाना की दूसरी समस्या यह है कि हमारे बाहर में जमीन के नीचे का पानी खारा है और कड़वा पानी है और ट्यूबवैल लगाकर यही पानी घरों में दिया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां डिग्गी बनाकर नहर का पानी घरों में सप्लाई कराया जाए ताकि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके जिससे कि उनकी सेहत और स्वास्थ्य ठीक रहे। सभापति महोदय, तीसरी समस्या देहाती जमीनों में भी खारा और कड़वा पानी होने की है। खारा पानी होने की वजह से जमीनें खराब हो

जाती है इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमारी नहरों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाये ताकि पानी टेल तक पहुंच सके और सारे खेतों की सिंचाई हो सके। इसके अलावा लडकियों के लिए भी अलग से कालेज होना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे यहां मिनी सचिवालय भी नहीं है और अधिकारियों को इधर उधर किराये की बिल्डिंग कर दफ्तरों में बैठना पड़ता है जिससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गोहना में एक मिनी सेक्टर भी होना चाहिए। सभापति महोदय, हमारी पांचवी समस्या बाई पास की है क्योंकि गोहाना में बड़े बड़े वाहन बाहर के अंदर से होकर गुजरते हैं जिससे सड़क पर जाम लग जाता है और पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि गोहाना के अंदर एक बाई-पास बनाना चाहिए जिससे कि बड़े बड़े वाहन बिना किसी दिक्कत के अपने गन्तव्य स्थानों को जा सकें और लोगों को भी कोई परेशानी न हो। सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह गरिमामय बजट है। इस बजट की जितनी तारीफ की जाये कम है। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि यह बजट हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ले जायेगा। अन्त में सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री अजय सिंह: चेयरमैन साहब स्पीकर साहब ने मुझे बजट पर समय देने के लिए कहा था।

श्री सभापति: अभी आप बैठिये। बाद में आपको समय देंगे। अब श्री भागी राम जी बोलेंगे।

श्री भागी राम (ऐलनाबाद अनुसूचित जाति): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। बजट पर बोलते हुए सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पे किया है। इसके बाद में चौटाला साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने राज्य सभा की सीट के लिए होने वाले चुनाव में एक हरिजन जाति के व्यक्ति श्री फकीर चन्द जी को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। मैं इसके लिए चौटाला साहब का सभी हरिजन भाइयों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने अपने अपने विचार हाउस के सामने रखे। कई साथियों ने कहा कि सरकार की तरफ से हरिजन कन्याओं की भाादी के समय कन्यादान देने वाली स्कीम के तहत 5100 रुपये सरकार की तरफ से दिये जाते हैं नाकामयाब रही यानी इस स्कीम का फायदा हरिजन भाइयों को पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हरियाणा विधान सभा में हरिजन मैम्बरो की संख्या 17 है और इन 17 मैम्बरो में से 14 मैम्बर अकेले औम प्रका चौटाला जी की पार्टी के हैं। इसके

अलावा दो मैम्बर्ज भी हमारी ही पार्टी जैसी पार्टी के मैम्बर्ज है। इसके अलावा जो एक मैम्बर बचे है श्री रामफल फौजी वे भी अपनी ताकत से कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हाउस में जीतकर आये है। (विघ्न)

श्री रामकिान: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चेयरमैन साहब आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि हरिजन लडकियों की भादी की स्कीम के तहत जो 5100 रुपये दिये जाते है यदि सरकार इसके साथ उन्हे 40 किलो चावल और एक बोरी चीनी की और दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

14:00 बजे

श्री भागी राम: हरिजन भाइयो ने फैसला करके सारे के सारे विधायक चौटाला साहब की पार्टी के जिताए है तो आखिर कोई न कोई कारण तो है। चेयरमैन साहब जब से दे । आजाद हुआ है या जब से हरियाणा बना है तब से ले कर हर चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हरिजनो के वोट बटोरने के लिए तरह तरह के नारे दिए। कभी जमीन बांटने का नारा दिया, कभी प्लांट बांटने का नारा दिया, कभी गरीबी हटाने का नारा दिया और कभी कोई और नारा दिया। सभापति महोदय, इस चुनाव के अंदर कोई अलग ही नारा दिया और वोट बंटोरे। लास्ट में हरिजन भाइयो को हरिजन भाइयो से लडाने का काम भी इस कांग्रेस पार्टी ने किया। आखिर में जब हरिजन ने सोचा तो उसको समझ आई। जब से

दे । आजाद हुआ और हरियाणा बना हरिजन वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते रहे लेकिन इस चुनाव के अंदर सब हरिजन भाइयो ने सोच समझ से काम लिया और आज सारे के सारे विधायक चौटाला साहब की पार्टी के जिताए। (विघ्न) चेयरमैन साहब, चौटाला साहब ने आखिरकार हरिजनो के लिएकुछ काम किए होंगे। थोडे ही समय के लिए चौधरी देवी लाल जी को और चौटाला साहब को हरियाणा में राज करने का मौका मिला है। करीब 4-5 साल के भासनकाल मे हरिजनो के लिए जो काम किए उनसे पता चलता है कि वे हरिजनो के कितने हितै ि है चाहे गांव मे हरिजन चौपाल बनाने का काम किया, चाहे घुमन्तु परिवारो के बच्चे पढ लिख नही सकते थे उनके बच्चो को स्कूल मे दाखिला देने के बाद हर रोज एक रुपया हाजरी इनाम देने का काम किया। चेयरमैन साहब सम्पन्न परिवार के किसी आदमी को पैं ान मिल चाहे न मिले लेकिन हरिजन परिवार जो कि गरीब है उनके घर के अंदर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है जब उस परिवार के बूढे को 200 रुपये और बुढिया को भी 200 रुपये मिल जाते है तो उनको बहुत बडी मदद उससे मिलती है जिसके कारण वह बूढा या बुढिया जब तक जीयंगे चौधरी देवी लाल जी को हमे ा याद रखेंगे (विघ्न) आज वे लोग चौटाला साहब तथा चौधरी देवी लाल को याद कर रहे है। चेयरमैन साहब, इसी तरह से हरिजन कन्या के लिए 5100 / रुपये कन्यादान के रुप मे देने का फैसला किया गया है। जब कभी कोई हरिजन आदमी पहले किसी अमीर आदमी से कर्ज लेने के लिए जाता था तो उसको कितने

ऐफिडेविट पर दस्तखत करवा कर उससे दुगना तिगुना ब्याज लगा कर वसुल करता था और उसके लडके को घर में नौकर रखता था। 5100 रुपये कन्यादान की राशि के लिए चौधरी साहब बधाई के पात्र हैं। वह गरीब आदमी जिसके घर में बेटी जवाब है और भादी के समय 5100/ रुपये मिल जाता है तो हरिजन के लिए इससे बड़ा और कोई सहारा नहीं हो सकता है। चेयरमैन साहब इसी तरह से इन्टरव्यू के लिए जब कोई गरीब आदमी का बेटा जाता था तो उसे बड़ी दिक्कत होती थी और कई बार तो पैसे की कमी के कारण वह इन्टरव्यू पर जा नहीं पाता था। लेकिन चौधरी देवी लाल जी ने इन्टरव्यू पर जाने के लिए आने जाने का फ्री पास करके बहुत बड़ा फैसला किया था। अगर कोई बच्चा सिरसा से चलकर चण्डीगढ़ इन्टरव्यू देने के लिए आएगा तो उसको किराये के पैसे जुटाने में जो मुश्किल पेश आती थी उससे उसको राहत मिली है। नौकरी उको मिले या न मिले यह बाद की बात है लेकिन जब वह हर इन्टरव्यू अटैंड कर रहा है क्योंकि सिरसा से लेकर चण्डीगढ़ तक 200-300 रुपये किराये की राहत उसको मिल गई है। चेयरमैन साहब, इसी प्रकार से कई और महत्वपूर्ण फैसले हरिजनो के लिए किए हैं। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी तो उस सरकार ने पीले कार्ड का मामला टेकअप किया था। सारा हाउस चर्चा कर रहा है कि सभी हलको में पीले कार्ड बनने से लोग राशन कार्ड के लाभ से वंचित रह गए हैं इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह अपील करना चाहूंगा कि क्योंकि सम्पन्न परिवार वालों के तो पीले कार्ड बन गए

है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पूरी तरह से दोबारा से सर्वे होना चाहिए और जो वास्तव में गरीब लोग हैं और पीले कार्ड बनने से वंचित रह गए हैं उनके पीले कार्ड बनवाए जाएं। चैयरमैन साहब, मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने हलके की कुछ बातें कहना चाहूंगा। 1977 में मैं पहली बार चुनाव जीत कर आया था। एक चुनाव को छोड़कर मैं चुनाव जीता रहा हूँ। थोड़ा सा समय चौधरी देवी लाल जी को हरियाणा में राज करने का मिला था बाकी समय चौधरी भजन लाल जी और चौधरी बंसी लाल जी का राज रहा है। इन्होंने ऐलनाबाद और सिरसा जिले के साथ भेदभाव रखा और इनके भेदभाव की वजह से आज सदन में लक्ष्मण दास जी रो रहे थे वे भजन लाल जी को अपनी बात तो कह नहीं सकते थे लेकिन हमारी सरकार के सामने रो रहे थे। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। (विधन) 1979 में चौधरी देवी लाल की सरकार बनी उस समय इन्होंने ऐलनाबाद में हास्पिटल बनाने के लिए नींव पत्थर रखा था। बिजली का 132 के 0 वी 0 स्टे पान बनाने के लिए, सिवरेज सिस्टम का और वाटर वर्क बनाने का िलान्यास किया था। भजन लाल जी की सरकार आई लेकिन उन पर काम नहीं किया गया। बंसी लाल जी की सरकार आई फिर भी उन पर कुछ काम नहीं किया गया। वहाँ पर िलान्यास के पत्थर के पत्थर लगे रहे। उन िलान्यासे के बाद न जाने कितने 132 के 0 वी के सब-स्टे पान बने, सिवरेज, वाटर वर्क्स और हास्पिटल बन लेकिन ऐलनाबाद में आज तक कोई काम नहीं किया गया है। यह सब वहाँ पर बदले की भावना की वजह से किया

गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ पर जो अभी तक काम नहीं किये गये हैं वे करवाएँ। सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनकर हैरान होंगे कि आज तक वहाँ पर बदले की भावना से न तो चार दिवारी बनवाई गई है और न ही कोई बिल्डिंग बनवाई गई है। वहाँ पर आज भी बड़ा बड़ा घास खड़ा है। चौधरी भजन लाल जी ने और चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा में राज किया। चौधरी देवी लाल जी को तो राज करने का थोड़ा सा समय मिला था। अभी थोड़ी देर पहले सभी मैम्बर्ज यहाँ पर इस बारे में कह रहे थे, रो रहे थे तो वे सब इन दोनों को ही रो रहे थे। क्योंकि वे इनके राज से दुखी थे। आज इन दोनों के कारनामों की वजह से आदरणीय चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने हैं। चेयरमैन साहब, मैं चौटाला साहब का इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही नये ओटू बीयर को बनाने का िालान्यास किया। बरात के सीजन में पंजाब एवं हिमाचल का पानी हमारे सिरसा जिले से होकर गुजरता है जब ज्यादा पानी वहाँ पर हो जाता है तो उससे यहाँ की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पुराना ओटू बीयर अंग्रेजों के जमाने का था और अब उस पर रात और दिन काम चल रहा है। चेयरमैन साहब, मैं इसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय अभी बैठे नहीं हैं लेकिन वित्त मंत्री और िक्षा मंत्री यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऐलनाबाद और रानियां दो कस्बे हैं इन दोनों कस्बों में नगरपालिकाएँ हैं और दोनों कस्बों में ही प्लस टू स्कूल हैं। आज िक्षा की हर जगह जरूरत है हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है हर मां-बाप

अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहता है इसलिए मेरा इन दोनों मंत्रियों से अनुरोध है कि ऐलनाबाद और रानियां में एक एक कालेज जरूर बनाया जाना चाहिए। इस बारे में मेरा एक क्वेश्चन भी है। अंत में मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिना टैक्स का बजट पेश किया। धन्यवाद।

श्री भीमसैन (इंद्री): सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद। सर, चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में जो वित्त मंत्री जी ने कर मुक्त बजट पेश किया है उससे प्रदेश के सभी वर्गों को सभी लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई कर नहीं लगाया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से अपने हलके की समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। आज से कुछ महीने पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी हमारे इंद्री में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गए थे। उस समय उन्होंने वहां पर कुछ घोशणाएं की थी जिनमें काफी घोशणाएं तो उनकी कार्यकुशलता के कारण पूरी हो गयीं मगर कुछ घोशणाएं ऐसी रह गयीं जिनका उल्लेख मैं यहां पर करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है, आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी हलके की बकाया घोशणाओं को भी पूरा करेंगे। उस समय उन्होंने घोशणा की थी कि वहां पर हैफेड का भोलर लगाया जायेगा। इसके अलावा उन्होंने वहां पर जो भाहीद उद्यम

सिंह ने इनल कालेज है उको सरकारी कालेज बनाने का वायदा किया था। इसी तरह से उन्होंने वहां पर डबल्यू० जे० सी० के उपर एक पुल बनाने की भी बात कही थी। इसी तरह से मेरे हलके के गांव वीना मे एक पावर हाउस बनाया जाना है उस पर अभी तक काम भुरु नहीं हुआ है। मै अनुरोध करुंगा कि उस पर भी काम भुरु करवाया जाए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी घोशणाओ मे से अभी तक जो पूरी नहीं हुई है उनके लिए मै माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी घोशणाओ मे से जो भी तक पूरी नहीं है उनके लिए मै माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि वे पूरी की जाएं। इसके साथ ही हमारे हलके के अंदर जो सडके टूटी पडी है जिनकी काफी खस्ता हालत है उनकी भी मरम्मत की जाए। ऐसी ही एक सडक मुरादगढ गांव से लेकर बडे गांव एवं भाहपुर तक की है उको भी पूरा किया जाना चाहिए। मुझे पूरा वि वास है और एक बात कहते हुए मै फख महसूस करता हूं कि चौधरी औम प्रका । चौटाला जी जो बात कहते है वही करते है। ऐसा हमने पिछले भासन काल मे जब हम इनकी सरकार में मंत्री थे, तब देखा थे। जितने भी कार्यों की घोशणा की थी वह कार्य पूरे किए है और उसी वि वास के साथ आज फिर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं और याद दिलाता हूं कि जो घोशणाए उन्होंने मेरे हलके के लिए की थी उन्हे पूरा करें ताकि हलके के अंदर जो विकास कार्य बकाया पडे है वह पूरे हो सके। इन भाब्दो के साथ मै आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हू।

श्री सभापति: श्री जीतेन्द्र सिंह मलिक अभी तक इस हाउस में नहीं बोले हैं मैं चाहता हूँ कि यदि वे बोलना चाहे तो विपक्ष के नेता उन्हें बोलने के लिए बुला लें। तक तक श्री भगवान सहाय रावत बोल लें।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस सहस्त्राब्दी के प्रथम वार्षिक बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए इस बजट की वास्तविकता से परिचित होते हुए सदन के सम्मुख इसके सकारात्मक पहलू पर अपने कुछ विचार मैं रखना चाहूँगा। मुझे इस बात की खुशी है कि एक जनकल्याणकारी सरकार की स्थापना के बाद राज्यपाल का अभिभाषण जहाँ निर्दिष्ट करता है वहाँ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट भविष्य की योजनाओं पर दृष्टीपात करता है। हमारे सभी साथी विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आए हैं उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रवार समस्याओं व उनमें विकास के कार्य करवाने के प्रति रुचि है इसके साथ-साथ पूरे राज्य को दृष्टीगत रखकर बजट का प्रावधान किया गया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। सर्वप्रथम तो मैं हार्दिक शुभकामनाएँ बजट है उसकी प्रतीक्षा किए बगैर नहीं रह सकता इससे पहले बजट प्रस्तुत होते रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी बजट में टैक्स का न लगाना सकारात्मक पहलू में

आता है। केन्द्र स्तर पर सबसिडी में कटौती अभी भी विचाराधीन है हमारी प्रदे 1 सरकार बधाई की पात्र है कि ऐसी में उसने सबसिडी को मनेटेन किया है और कई ऐसी जगह भी है जहां उन्होंने सबसिडी को इनकीज किया है जैसे पावर सैक्टर, फुड, फर्टीलाइजर सैक्टर में सैन्ट्रल गवर्नमेंट सबसिडी रिड्यूस करने जा रही थी उस सबसिडी में बढ़ोतरी करके सराहनीय काम किया है। हरियाणा प्रदे 1 एक कृषि प्रधान प्रदे 1 है। सिंचाई सुविधाओं के बारे में सरकार ने 412 करोड रुपये का जो बजट में वि ेश प्रोविजन किया है उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र हैं। खाद और बीज जैसी चीजों पर वि ेश ध्यान देकर उसके लिए भी सरकार ने वि ेश राशि का प्रावधान इस बजट में पे 1 किया है। इसका एक जो सकारात्मक पहलू है वह यह है कि केन्द्र सरकार के स्तर पर सेलटैक्स की समान दर स्वीकर की गई है और उस युनीफार्म दर का पालन करते हुए भी एक डायनामिक बजट प्रस्तुत किया है। खासकर हमारा जो एग्रीकल्चर सैक्टर है उसमें ज्यादा उत्पादन करने के लिए एम0 आई0 टी0 सी0 और जो दूसरी सिंचाई सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि करके सरकार ने सराहनीय काम किया है। चेयरमैन सर, मैं मेवात क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं वह क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से व आर्थिक दृष्टि से पिछडा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मेवात क्षेत्र में सिंचाई के लिए या तो मेवात कैनल या फिर आगरा कैनल से पानी मिलता है। लेकिन आगरा कैनल की मैनेजमेंट का कार्य उत्तर प्रदे 1 की सरकार के हाथों में है जिसके कारण हमें अपना पूरा पानी समय

पर नहीं मिल पाता। तत्कालीन चौधरी देवी लाल जी की सरकार में भी मैं विधायक था उस समय भी मैंने इस बात को उठाया था और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इस सदन में लाया गया था। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आगरा केनाल की मैनेजमेंट का कार्य सरकार अपने हाथों में ले इसके लिए चाहे केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई समझौता किया जाये। ताकि मेवात ऐरिया को अपने हिस्से का उचित पानी मिल सके। सभापति महोदय, जैसे कि आप जानते हैं कि समतल भूमि होने के कारण मेवात क्षेत्र का हरियाणा प्रदेश के उत्पादन में काफी योगदान रहा है। माननीय सदस्य श्री बलबीर पाल भाह ने गौ हत्या के बारे में मेरे हलके का जिक्र किया। इसलिए मैं उनके सवाल का जवाब देना वाजिब समझता हूँ। सभापति महोदय, मैं उस हलके का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसमें 36 बिरादरी हैं। भायद इन्होंने सुना है देखा नहीं है कि साम्प्रदायिक सदभाव कैसा होता है। एक बात मैं यहां पर जरूर मुसलमान एक थे उनकी तब भी आपस में लड़ाई नहीं हुई। वहां पर हिन्दु-मुसलमानों के दो गुट थे कभी भी पाल एक तरफ होती थी और दूसरी तरफ जाट भारोद और धिकलोथ मुसलमानों की पाल होती थी। ये जाट और मुसलमान की दो पाल थी इन दोनों गुटों की लड़ाई ही होती थी। लेकिन जैसे की भाह साहब ने गउ हत्या की बात की है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश: सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है क्योंकि यहां पर कोई बजट पर स्पीच नहीं है।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): सभापति महोदय, मेरी एक सबमिशन है कि कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों ने 2-3 नई परम्पराएं शुरू की हैं। पहले किसी बात की शुरुआत कर देते हैं जब उस बात का जवाब दिया जाता है तो सारे साथी खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य श्री बलबीर पाल भाह ने मेवात क्षेत्र की इस सदन में चर्चा की है तो हमारी पार्टी के साथी ने उसका जवाब देना शुरू किया तो अब वे इसका एतराज कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री भगवान सहाय रावत: सभापति महोदय, मैंने तो एक मिनट की भी चर्चा नहीं की कि माननीय कांग्रेस के सदस्य उसी में तिलमिला गए हैं। मेरे हलके का नाम आया था इसलिए मैं उनकी बात का जवाब देना जरूरी समझता था। सभापति महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है इसलिए कृषि के क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करके इस सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाया है जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इसके अतिरिक्त सोशल सेक्टर के बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आदरणीय देवी लाल जी ने सामाजिक क्षेत्र में समाज कल्याण हेतु 36

बिरादरी के लोगो के लिए एक समान व्यवस्था करके, समान पैं उन देकर जो सराहनीय कार्य किया है, मैं समझता हूं कि उनके लिए एक इतिहास लिखा जाना चाहिए और हम सभी सदस्यों को एकमत होकर प्रस्ताव पास करना चाहिए। यह निहायत ही एक अनुकरणीय कदम है। सरकार ने जो हरिजनो की लडकी की भाडी के लिए 5100 रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी है उसके बारे में मैं रिपीटी उन में नहीं जाना चाहता, लोग सुनते सुनते थक जाते हैं। यह इतनी कल्याणकारी योजना है जिसका बजट में स्पेशल प्रोविजन किया गया है इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। एजुकेशन का मुद्दा एक मुख्य मुद्दा है। मैं एक अध्यापक रहा हूं। मुझे सौभाग्यवश दूसरी बार इस विधानसभा में आने का मौका मिला है। मैं हथीन क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं। मैं भौक्षणिक दृष्टी से अपने क्षेत्र पर आपका दो मिनट का समय लेना चाहूंगा। सभापति महोदय, फखर के साथ कहता हूं कि चौ० देवी लाल जी ने उटावड में एक पौलिटैक्निक कालेज खोला जो कि हमारे मेवात क्षेत्र में पडता है, जहां पर मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड के द्वारा कार्य किए जा रहा है लेकिन भौक्षणिक दृष्टी से हमारा क्षेत्र लडकियों की शिक्षा में बहुत पीछे है। लोगो ने मुख्यमंत्री महोदय से पौलिटैक्निक कालेज की स्थापना के लिए प्रार्थना की और कालेज खोल दिया गया था। इस बजअ में शिक्षा के लिए टोटल 1352.99 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। जब मुख्यमंत्री महोदय पलवल के पौलिटैक्निक कालेज उटावड में गए थे तो वहां उनको उनकी लोकप्रिय नीति

सरकार आपके द्वार के द्वारा हमारी ग्राम पंचायतो का एक डैपुटे न मिलता था जिसमे लोगो ने उनको सम्बोधित करते हुए कहा था कि हमारे इलाके की एक ही मांग है कि बहीन मे जो 900 बीघा जमीन पडी हुई है वहां पर रिनल सेंटर और एग्रीकल्चर कालेज की स्थापना के लिए हमसे किए गये वायदे को पूरा करें। सभापति महोदय, मैं आपके मायम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस कालेज की स्थापना के लिए कोई कदम उठाना चाहिए और इस बजट मे उसको कोई प्रावधान होना चाहिए था अन्यथा भविश्य मे सरकार इस बात को ध्यान में रखे। उटावड पौलिटैक्निक कालेज की स्थापना वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत की गई थी और उसके साथ नारनौल मे भी एक पौलिटैक्निक कालेज की स्थापना की गई थी। दोनो कालेजो का इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधारभुत सुविधाएं बराबर की है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां के कालेजो मे आज भी नान इंजीनियरिंग के 2 कोर्सिज है और इंजीनियरिंग का केवल एक ही कोर्स है। जबकि टैक्नीकल कालेजो मे सारे इंजीनियरिंग कोर्सिज होते है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने नीलोखेडी और रोहतक के कालेजो को जहां पर सारी सुविधाएं पूर्ण रुप से उपलब्ध थी, उटावड के पौलिटैक्निक कालेज घोशित कर दिया। इसी आधार पर मैं सरकार से निवेद करना चाहूंगा कि उटावड के पौलैटैक्निक कालेज में इंजीनियरिंग के और कोर्स भुरु किए जाएं। आज पुरे दक्षिणी हरियाणा के लोगो की एक भूख और प्यास है कि उनके मेवात

एरिया मे कोई युनिवर्सिटी खोली जाए। जवाहर लाल नेहरु युनिवर्सिटी दिल्ली के पास लगती है जहां पर सम्पूर्ण भारत बसता है। हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र मे युनिवर्सिटीज पहले से ही है, मेवात एरिया मे युनिवर्सिटी खेल जाने से हम पूरे हरियाणा को दिल्ली की तुलना मे खडा कर देंगे। मै चौधरी औम प्रकाश चौटाला जिन्होने देवी लाल जी की गोद में, उनके चरणो मे राजनीतिक शिक्षा ग्रहण की है, से और उनकी सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपा करे। इसके लिए जवाहर लाल नेहरु युनिवर्सिटीर के बिल्कुल साथ अरावली हिल्स के साथ जमीन भी उपलब्ध हैं और सारी फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय की भावनाओ का आदर करते हुए इनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होने कर रहित बजट प्रदेश के लोगो को दिया। इसके साथ ही मै अपना स्थान ग्रहण करता हू। (धन्यवाद)

श्री सीता राम (डबवाली अनुसूचित-जाति): सभापति महोदय, आपके माध्यमे से बजट के उपर मुझे बोलने का समय मिला इसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं और वित्त मंत्री महोदय ने जो कर रहित बजट सदन मे प्रस्तुत किया है उसके लिए मै उनको भी बधाई देता हूं। सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान डबवाली हलके की समस्याओ की तरफ दिलाना चाहूंगा। पिछली सरकारो ने इसहलके के प्रति भेदभाव की नीति अपनाई और इस हलके मे विकास के नाम पर कोई भी कार्य नही

किया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस हलके की तरफवे विशेष रूप से ध्यान दें। ताकि वहां के लोगों की भी समस्याएं दूर हो सकें। सभापति महोदय, सिरसा जिले के अंदर डबवाली में कालेज के लिए जमीन अधिग्रहण हुई थी लेकिन बाद की सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं चौटाला साहब से अनुरोध करूंगा कि वहां पर सरकारी कालेज बनवाया जाए। सभापति महोदय, यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। इसी कारण से वहां पर उद्योग पलायन कर रहे हैं। मेरा भी मौजूदा सरकार से अनुरोध है कि डबवाली को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ इलाका घोषित किया जाये ताकि वहां भी नये नये उद्योग लग सकें और वहां के युवकों को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि डबवाली में बहुत ही भयंकर अग्निकांड हुआ था। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार या नीति बनाये कि उस कांड में जिन लोगों की जानें गईं उनके परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाये। सभापति महोदय, यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहां के किसानों की माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर कृषि पर आधारित ऐसा उद्योग लगाया जाये जिससे वहां के किसानों की माली हालत सुधर सके। सभापति महोदय, इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए अंत में मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री दरियाव सिंह (झज्जर, अनुसूचित जाति): सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने कर रहित बजट प्रस्तुत किया इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झज्जर जिले की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहूँगा कि झज्जर जिला तो बन गया है लेकिन वहाँ पर जिले जैसे सुविधाएँ नहीं हैं। वहाँ पर रेलवे लाइन भी नहीं है। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि वे केन्द्र सरकार से बात करके वहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाने का प्रबंध करवायें। सभापति महोदय, झज्जर भाहर के अंदर बस अड्डा नहीं है और न ही बस का डिपो है इसे सब डिपो बना रखा है। इस बारे में मैं चौटाला साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पर बस-अड्डा और सब-डिपो की जगह बस डिपो बनवाया जाये। सभापति महोदय, चौटाला साहब ने अपने 8 महीने के कार्यकाल में यह साबित कर दिया कि वे ही हरिजनो के सबसे बड़े हितैशी हैं। वे जो कुछ कहते हैं वह करके दिखाते हैं। सभापति महोदय, बहन जी अनिता यादव कह रही थी कि झज्जर के अंदर हरिजन की लडकी की भादी के समय जो कन्यादान का पैसा 5100/ रुपये मिलता है वह कन्यादान का पैसा नहीं मिला। ये बात वे बिल्कुल गलत कह रही थी। क्योंकि झज्जर के अंदर सभी को यह पैसा मिला है। एक आध केस ऐसा हो सकता है जिसके कागज पूरे न होने की वजह से उसको ये पैसे न मिले हो बाकी सभी हरिजन लडकियों की भादी के वक्त 5100/ रुपये कन्यादान के रूप में सरकार की तरफ से मिले हैं। सभापति महोदय, चौटाला साहब ने

बुढापा पैँ 100 रुपये से बढाकर 200 रुपये करके बहुत ही अच्चा काम किया और अपना वायदा भी पूरा किया। सभापति महोदय, चौधरी देवी लाल जी और चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी ही ऐसे नेता हिन्दुस्तान और हरियाणा मे है जो अपना वायदा निभाते है। कांग्रेस के नेता भी है, चौधरी बंसी लाल जी भी है, ये जो कुछ कहते है वह नही करते। अपना वायदा पूरा नही करते। लेकिन चौधरी देवी लाल जी और चौटाला साहब ने जो कहा है वह करके दिखाया है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सरिता (कलानौर, अनुसूचित जाति): सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूँ। बजट मे बहुत से प्रावधान रखे गये है जो कि बहुत ही सराहनीय है। हरियाणा मे आधारभूत सुविधाओं के लिए विशेष ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य, अनुपूरक पोषण, आवासीय क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान करना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को इस बजट मे रखा गया है। इसके अलावा चुंगी समाप्त करना, अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट बहाल करना, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नई मंडियों के विकास और वर्तमान मंडियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, मंडी व्यापारियों को जनवरी 2000 से 21 वस्तुओं पर मार्केट भुल्क दो प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत

करना, पंजु धन सहायह को सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा पंजु धन विकास बोर्ड का गठन करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य सरकार ने किये है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख् मंत्री जी का ध्यान अपने हलके कलानौर की तरफ दिलाना चाहती हूं। यह बहुत ही पिछडा हुआ हलका है। अगर इसे सुधारने के लिए 10 साल भी मिले तो भी कम है। अध्यक्ष महोदय, 1995 मे कलानौर मे आई0 टी0 आई0 के निर्माण के लिये नीवं पत्थर रखा गया लेकिन उसके लिए ऐसी जगह चुनी गई जो बहुत ही गहरी है। अगर इस आई0 टी0 आई0 के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये भी मिलते है तो 10 लाा रुपये उसकी गहरी जमीन को मिटटी भरने मे और उसका लैवल सडक के बराबर करने मे लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मे आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपने हलके की ओर दिलाते हुए यह बताना चाहती हूं कि इस हलके में पानी की भी बहुत समस्या है और निर्माण के लिए टैण्डर तो पास हो चुके है लेकिन काम भुरु नहीं हुआ। वहां पर सडको पर मिटटी भी डाली हुई है और पत्थर रोडी-वगैरह भी पडी है लेकिन काम भुरु होने के बाद भी अधुरा पडा हैं। इन सडको के नाम इस प्रकार है: बनियानी से माडोधी तक, भाली से गददी खेडी तक का 2 किलोमीटर का रास्ता, सांगा हेडा से पिलाना तक का पक्का रोड, आंबल से निगाना रोड, बहुजमान पुर से छोटा सिंहपुरा तथा जींदारण से बेरी रोड तक का 1 किलामीटर का कच्चा रास्ता। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि अभी तक मेरे

हलके की अनदेखी की गई है। मेरे हलके के साथ बडा ही सौतेला व्यवहार हुआ है। मेरे हलके की पूर्व विधायिका ने इस हलके की अनदेखी की है और मेरे हलके मे सुधार नाम की कोई चीज नही है। मेरे हलके मे ि शिक्षा का भी बडा अभाव है। खेरडी गांव मे एक आठवीं तक का स्कूल है इस स्कूल को भी अपग्रेड कराकर दसवीं तक कराये क्योंकि यहां की हमारी जबान जवान बेटियो को जीपो और बसो मे लटक कर भिवानी या कलानौर आना पडता है। कलानौर मे एक ही भवन मे सुबह और भाम की दो दो क्लासिज लगती है इसलिए मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां प स्कूल के औ कमरो का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा खेडी गांव मे बच्चो के लिए कोई स्कूल नही है। निगाण और सांगाहेडा मे यातायात की भी बडी असुविधा है। इसलिए मै आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ी से प्रार्थना करती हूं कि इन गावों मे बस सेवाओ को बहाल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मै आपका धन्यवाद करती हू।

श्री रामफल कुण्डु (सफीदो): अध्यक्ष महोदय, 14 मार्च को हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पे ा किया है मै उसके समर्थन मे बोलने के लिए खडा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पे ा किया है यह एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा बजट है। सरकार ने 2000-2001 की वार्षिक योजना मे सभी वर्गों के उत्थान के लिए पैसे का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, औम प्रका । चौटाला जी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि मैं सभी वर्गों को 24 घंटों बिजली दूंगा। हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने अल्प काल के समय में ही सभी वर्गों को 24 घंटे बिजली देकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बिजली की सप्लाई ठीक ढंग से हो सके इसलिए हर पावर हाउस के ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। इतना ही नहीं जहां जहां पर बिजली की तारे बदलने की आवश्यकता है वहां पर तारे भी बदल जा रही हैं। ये सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हर जगह 24 घंटे बिजली लोगों को बराबर मिलती रहे। इस एक कार्य के लिए मैं पुनः चौटाला जी का धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। हमारी सरकार ने अल्प समय के अन्दर ही नहरों की सफाई करके, उनकी गाद आदि निकलवा कर और उनकी खुदाई करवा कर हर टेल तक पानी पहुंचाया है। इसके अलावा सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए 770 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस स्कीम पर भी जल्दी से जल्दी कार्य भुरु करवाने का फैसला लिया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वृद्धावस्था व विधवाओं की पेंशन को भी पहले से दुगना करके 200 रुपये प्रति मास करके एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सरकार ने इन लोगों

की जो पैं ान डबल की है उसके लिए मै भी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हू।

अध्यक्ष महोदय, सरकार आपके द्वार जो प्रोग्राम सरकार ने चलाया था उसके तहत जो जो वायदे वहां पर किए गए थे उन सब पर 90 की 90 कान्स्टीच्युएंसी मे काम चल रहा है। कई साथियो ने आरोप तो लगाया कि जो जो वायदे मुख्य मंत्री जी ने इस प्रोग्राम के तहत किए थे उन पर काम नहीं हुआ लेकिन इन विरोधी भाइयो मे से किसी ने यह नहीं कहा कि हमारे हलके मे सरकार आपके द्वार के तहत यह वायदा किया था और उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र मे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो जो वायदे किए थे उन सब को पूरा किया जा रहा है। भजन लाल जी ने भी कहा था कि सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत इतने वायदे कर लिए है कि वे आने वाले 30सालो मे पूरे नहीं हो सकते। स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहता हूं कि आने वाले 30 महीनो मे सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत जो जो वायदे किए थे वे सभी के सभी पूरे कर लिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो सडके 7-8 साल से टूटी पडी थी उनका पैच वर्क भी सरकार ने नवम्बर तक मुक्कमल करवा दिया है और अब आने वाले मई जून महीने तक उन पर कारपेट का काम भी पूरा कर लिया जायेगा। अंत मे स्पीकर साहब, मै इस

बजट का समर्थन करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब श्री सुरजमल जी बोलेंगे।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप उनही के मैम्बर्ज को बोलने का समय दे रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी पार्टी के मैम्बर्ज को बोलने के लिए आप समय दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी आपकी पार्टी को अब तक 300 मिनट में से 126 मिनट का समय दिया जा चुका है। मैं सभी को पार्टी अनुपात के हिसाब से बोलने के लिए समय दे रहा हूँ। अब श्री सुरजमल जी बोलेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) दलाल साहब, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए आपकी बात रिकार्ड नहीं की जा रही है। (विघ्न) जो दलाल साहब बोल रहे हैं रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) श्री सुरज मल जी अब आप बोलें।

श्री सुरज मल (राई): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समयप्रदान किया। वित्त मंत्री जी ने जो कर रहित बजट पेश किया है उसके

लिए वे बधाई के पात्र है। मेरे से पहले बजट पर बोलने हुए मेरे साथियो ने काफी बातें उठाई है। अध्यक्ष महोदय, सभी ने बजट को सराहा है ओर मै भी इस बजट की सराहना करता हू। मै आपके माध्यम से अपने हलके की कुछ बातें मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके राई 12-13 सालो से ओपोजी इन का ही विधायक रहा है। इसलिए हर सरकार ने राई हलके की उपोक्षा की है। चाहे चौधरी भजन लाल जी का राज रहा हो या चौधरी बंसी लाल जी का राज रहा हो लेकिन मेरे हलके मे कोई विकास के काम नही हुए है। (विघ्न) मै अपने हलके की एक दो महत्वपूर्ण बाते माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हू। मेरा हलका यमुना के साथ लगता है यमुना के साथ लगती हमारी जमीनो को जबरदस्ती यू0 पी0 के लोग बो रहे है तथा हमारी फसले जबरदस्ती काट ले जाते है। वहां पर बडा खतरा है। लेकिन किसी भी पिछली सरकार ने इस ओर ध्यान नही दिया है और इस बात का कोई समाधान नही ढुंढा है। दीक्षित अवार्ड के बावजूद यू0 पी0 के लोग बजरदस्ती उन जमीनो को बो रहे है और हमारी अपनी जमीनो पर हमे फसल नही बोने देते है। मै मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत करवाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं दीक्षित अवार्ड को लागू करवाएं तथा हमारी जमीने जिन पर जो हमारा हक है हमें दिलवाया जाए। पिछली किसी भी गवर्नमेंट ने दीक्षित अवार्ड का लागू करने का प्रयास नही किया। अब जब कि हमारी अपनी सरकार आई है तो मै उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस बारे ध्यान देंगे और हमारा हक हमें

दिलवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके राई के अन्दर रेत की खाले है तथा गवर्नमेंट उनको नीलामी पर ठेकेपर छोडती है। लेकिन ठेकेदार क्या काम करते है कि गवर्नमेंट से जो ठेके लेते है उन ठेको को आगे बेच कर लोगो से नाजायत तौर पर जबरदस्ती जमीने किराये पर लेते है और वक्त पर उन लोगो को पैसा भी नही दिया जाता है जिसके कारण हमारे लोगो को काफी परे ानी होती है। गवर्नमेंट का कर बचाने के लिए उन खालो के बजाए जबरदस्ती दूसरी जगहो का इस्तेमाल करते है तथा काफी रुपया इस ढंग से वे ठेकेदार कमाते है तथा गवर्नमेंट को दिए जाने वाले कर को भी चोरी करते है। सरकार को चाहिए कि इस पर पूरा ध्यान दे कर काम करे तो इसमे सरकार को बहुत बडी आमदनी भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, राई गांव मे मार्किटिंग बोर्ड ने मण्डी बनाने के लिए जमीन एकवायर की हुई है लेकिन वहां पर आज तक मण्डी का काम नही हुआ है। वह काफी जमीन है और ऐसे ही पडी हुई है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि राई गांव मे मण्डी बनाने का काम करवाएं। हमारे एरिया के अंदर लडकियो का कोई कालेज नही है। हां सोनीपत भाहर मे कालेज है। हमारे यहां पर लडकियां 12वीं जमात तक पढकर घरों मे बैठ जाती है क्योंकि उनको कालेज मे पढने के लिए भाहर जाना पडता है जोकि बहुत दूर है। बसों मे लडकियो को चढने नही दिया जाता है और उनको बहुत ही मु् कल का सामान करना पडता है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि मुरथल मे लडकियो का एक कालेज बनाया जाए ताकि उनको आगे

पढने का मौका मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके मे एक बीयर फ़ैक्ट्री थी चौधरी भजन लाल जी आए तो इन्होने उसको बिल्कुल बंद ही कर दिया। उस फ़ैक्ट्री मे 300-400 के करीब लोग काम करते थे और वे बेरोजगार हो गए। इस बारे मे हमने चौधरी औम प्रका । चौटाला जी को बताया तो उन्होने 30-40 को काम पर लगवाया है। मै चौधरी साहब से फिर से कहूंगा कि वहां पर लोग काम करते थे उनको दोबारा से काम पर लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के वक्त मुरथल मे 30 बैड का एक हास्पिटल मंजूर किया गया था। उस वक्त वहां की पंचायत ने उसके लिए 70 हजार रुपए जमा करवाए थे। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर 500-600 एकड जमीन बेकर पडी हुई है उस पर कुछ लोग नाजायजकब्जा करना चाहते है। हम उस जमीन को गवर्नमेंट को फ्री मे देना चाहते है। अगर सरकार उस जमीन को एक्वायर करके वहां पर कोई एग्रीकल्चर संस्थान खोल दे तो बहुत ही अच्छा होगा उससे वहां के लोगो को भी फायदा होगा। मैने जो बातें कही है उस पर सरकार गौर करे और उन कामो को करवाने की कृपा करे यही मेरा सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय अभी तक रुलिंग पार्टी से 6 सदस्य बोल चुके है लेकिन हमारी तरफ से कोई भी सदस्य नहीं बोला है। हमें भी बोलने का समय दें। अगर आप ही हमें बोलने का समय नहीं देंगे तो हम अपने हलके की बात कैसे कह पायेंगे।

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी 21 में से 7 मैम्बर्ज आपके बोले हैं।

मुख्यमंत्री (श्री औम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि अपोजी इन इस बात से सहमत थे कि जो सदस्य गवर्नर साहब के एड्रेस पर नहीं बोले हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए। आपको तो स्पीकर साहब की उदारता का आभार प्रकट करना चाहिए। (विधन) चौधरी साहब, यह संख्या के हिसाब से है आप 30 पर निपट कर रह गए हैं। तब यह हुआ था कि सब के सब बोलेंगे आज आप सात बोल चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संख्या के हिसाब से इन्हें बता दें, समय के हिसाब से बता दें और इनकी रैंकिंग के हिसाब से बता दें कि इनको कितना समय बोलने का मिलना चाहिए। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठें। मैं विपक्ष के नेताओं को बताना चाहूंगा कि विपक्ष की तरफ से 126 मिनट बोले हैं।

श्री भजन लाल: स्पीकर साहब, अगर दो सदस्य उस साईड से बोले हों तो एक सदस्य उधर से भी बोलना चाहिए (विधन) 6 सदस्य उधर की साईड से बोल चुके हैं तो हमारी तरफ से भी एक सदस्य को आप बोलने के लिए समय दें। जब तक मैम्बर्ज बोलना चाहे आप उनको समय दें चाहे आपको हाउस का समय ही क्यों न बढ़ाना पड़े। आप हाउस का समय बढ़ा दें।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया हाउस चल रहा है। जब से विधान सभा सैान बैठा है तब से ट्रेजरी बंचिज की तरफ से भी और अपोजीान की तरफ से भी पूरा कोओपरेान मिल रहा है। हमारे विपे के नेता ने जो बात कही थी हमने तो उस पर ही ऐग्री किया है। जैसे उन्होंने कहा था कि 89 मैम्बर्ज को जो हाउस मे है इसमे जो सदस्य अभी तक बोलने से रह गए है उन सभी को बोलने का पहले मौका मिलना चाहिए। उसमें चाहे वह ट्रेजरी बंचिज के मैम्बर हो या विपक्ष के हो, चाहे इंडीपेंडैन्ट मैम्बर हो, चाहे किसी अन्य पार्टी से हो और चाहे वह आपकी पार्टी के हो। इनके कहने के अनुसार ही आप हाउस की कार्यवाही चला रहे है। सर, ऐसा पहली बार हो रहा है वरना तो मै इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी और मांगे राम गुप्ता जी उस समय मंत्रिमंडल मे थे तो 7-3-96 को जो बजट पेा हुआ था वह बजट 35 मिनट मे ही पास हो गया था। उस समय केवल एक ही मैम्बर बोला था।

श्री भजन लाल: आप उस समय भाग गए होंगे।

श्री सम्पत सिंह: चौधरी साहब, हम भागे नहीं थे बल्कि हमें बोलने ही नहीं दिया गया था। अगर हमें बोलने ही न दिया जाए तो ये मांिल ले आए तो हम क्या कर सकते थे। इतनी जान तो हममे भी नहीं थी। एक मांिल हो तो अलग बात है ये

तो दो सौ मार ली लाकर यहां पर खडे कर देते थे। ऐसे मे हमारे क्या बर्ता की बात थी?

श्री भजन लाल: सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अब जो हाउस मे मार ली खडे हैक्या ये वी0 आई0 पी0 है। इन्होने यहां पर सारे पुलिस के जवान खडे कर रखे है। इनमे से आधो को तो मै जानता हू। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ये तो सारे पास होल्डर्स है।

श्री भजन लाल: पास तो इनको देने पडते है। मै इनको जानता हूं इनमें आधे पुलिस वाले है। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै विपक्ष के नेता और भूतपूर्वा मुख्यमंत्री को बताना चाहूंगा कि ये तो सारे पास होल्डर्स है। ये सारे अपने पास दिखा सकते है।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मै इस्तीफा दे सकता हूं अगर इनमे से आधे पुलिस वाले न हो तो। मै जानता हूं कि ये पुलिस वाले है।

श्री सम्पत सिंह: पता नही आप क्या क्या करोगे। आप तो पहले भी कह चुके है कि इस्तीफा दूंगा लेकिन आपने कभी दिया नही। आपने यह भी कहा था कि मै कीकर से लटटकर मर जाउंगा लेकिन आपने कभी ऐसा नही किया। (विघ्न) हमने तो आपकी पूरी सुरक्षा रखी हुई है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, आपने तो सबको समय देने के लिए कहा था। (विधन) मंत्री जी हर बात टोटिंग वे मे करते हैं। (विधन)

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, अपोजी इन ने जैसा सुझाव दिया था उसी सुझाव की टाईम लीडर आफ दी हाउस ने की थी जो मैम्बर अभी तक बोलने से रह गए हैं वे पहले बोलेंगे। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं कि दस या 15 मिनट हाउस का समय बढ़ाने की जरूरत है तो आप बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को आपने बुलवाना है तो यह आपने ही देखना है। सर, जिस ढंग से आप कार्यवाही चलाना चाहते हैं उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है हमारा आपको पूरा कोओपरे इन मिलेगा। जिस तरीके आप हाउस चलाना चाहते हैं वैसे आप चलाएं। (विधन)

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मे भी बोलना चाहते हैं आप हमें समय दें।

श्री अध्यक्ष: अगर आप बोलना चाहते हैं तो अनिल विज क्या करना चाहते हैं। वे भी तो बोलना चाहते हैं इसलिए आप उन्हें बोलने दें।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर डिस्क इन के लिए तीन बजे तक का टाइम तय किया था इस टाइम को पांच बजे तक करिए ताकि सभी सदस्य बजट पर बोल सकें।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, टाइम पूरा मिल जाता है लेकिन इनके कहने से कल की एक सिटिंग गई।

श्री अध्यक्ष: ठीक है बजट पर बोलने के लिए आधे घंटे का समय और दिया जाता है। अब श्री अनिल विज बोलेंगे।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, बजट पर अपने विचार रखने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी सरकार के लिए जो सबसे कठिन काम होता है वह होता है अपने कार्यों को प्लान करना। नीतियां तो बहुत बन जाती हैं लेकिन उन नीतियों को लागू करने के लिए धन को मुहैया कराना सबसे कठिन काम होता है There is an old sayings 'Plan your work and work your plan' किसी भी काम को करने के लिए व किसी भी सरकार को चलाने के लिए यह दोनों पार्ट बुत आव यह होते हैं। Plan your work.

अगर वर्क को प्लान नहीं किया जाता तो उसका करना कठिन होता है। Plan your work and work your plan. जो योजना बनाई जाती है उस योजना पर कार्य करना भी आव यक होता है। जब यह पार्ट पूरी तरहसे सजगता से, पूरे सुझबुझ से व सोच से किए जाते हैं तब ही कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। मैं समझता हूँ कि प्रोफ़ैसर सम्पत सिंह जी ने जो बजट इस विधान सभा के प्रथम सत्र में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने काम को जो कि बहुत ही कठिन काम था उसे बखुबी निभाने की कोशिश की।

है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जो भापथ ग्रहण की वह कुरुक्षेत्र की धरती पर की है। हम सब जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है वह धर्मक्षेत्र है गीता का प्रथम भूलोक है— धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवा चैव किमकुमर्त सनजे। यानी जो पहला भूलोक है वह भूलोक की कुरुक्षेत्र को अनादि काल से सनातन काल से धर्मक्षेत्र मानता है। इस सरकार ने उस धर्मक्षेत्र पर जो भापथ ग्रहण की है मैं इस बजट से ऐसा महसूस करता हूँ कि उस धर्मक्षेत्र की भावना का पूरी तरह से समावे । इस बजट में किया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यानी जो हमारा धर्म है हमारे धर्म की जो सबसे मूल भावना है उसमें यह कहा गया है कि — सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारा जो धर्म है वह किसी वर्ग विशेष जाति के लिए अलग से नहीं है बल्कि हमारे धर्म में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना का पूरी तरह से पालन किया गया है। समाज के सभी वर्गों के लिए चाहे वह विकलांग हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह विधवा हो सबके लिए इसमें कुछ न कुछ सोचा गया है। वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये की गई है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारे जो जवान सीमा पर भाहीद होते हैं उनके बारे में सोचा गया है उनकी भी सहायता राशि बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दी गई है। इसमें कर्मचारियों के बारे में भी सोचा गया और कहा गया कि अन्य मांगों के साथ साथ कर्मचारियों को पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कर्मचारियों के वेलफेयर की बात है, इस बजट

मे कर्मचारियों को 504 मकान बनाकर देने की बात कही गई है यह एक अच्छी बात है और इससे कर्मचारियों को रिहायगी मकानों की दिक्कत में राहत मिलेगी। यह एक अच्छा कदम है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कर्मचारियों का हैड क्वार्टर का क्षेत्रफल बढ़ाकर 60 किलोमीटर तक की सीमा तक कर दिया जाये तो इससे कर्मचारियों को मकानों की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पंजाब और दिल्ली में ऐसा किया जा रहा है। अगर यह सीमा बढ़ाई गई तो जो कर्मचारी चण्डीगढ़ में मकान नहीं बना सके वे सस्ते मकानों में अम्बाला और पटियाला में जाकर रह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ज्यादा जोर दिया गया है जिसके लिए 2530 करोड़ रुपये की प्लान आउट ले कर इस बजट में तैयार किया गया है। जिसमें से 1632 करोड़ रुपये का प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बजट में किया गया है। जहां तक बिजली की बात है। बिजली में सुधार के लिए इस बजट में 626 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें बताया गया है कि जो पिछली सरकार के समय केन्द्रीय पूल से हमें 19 प्रति एत बिजली मिलती थी उसको बढ़ाकर 27 प्रति एत करने में यह सरकार कामयाब रही है। इस बजट में फरीदाबाद में 143-143 मेगावाट के गैर पर आधारित दो संयंत्र बनकर तैयार हो गये हैं और तीसरी इकाई के छः महीने के अंदर अंदर बनकर तैयार होने का जिक्र किया गया है। हमें उम्मीद है कि इस इकाई के पूरा होने पर हमारी बिजली की समस्या

काफी हद तक दूर हो जायेगी। बिजली के बारे में आगे यह बताया गया है कि संप्रेशण और जनरेटन के लिए इस बजट में काफी प्रावधान किया गया है। 220 केवी के सब-स्टेशन से की जाती है उसके अलावा अम्बाला कैंट में बिजली की सप्लाई का दूसरा वैकल्पिक साधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि तेपला के 220 केवी सब-स्टेशन को भीघ्न चालू करने का ध्यान सरकार को देना चाहिए। अगर तेपला का सब-स्टेशन अम्बाला कैंट से जोड़ दिया जाता है तो फिर अम्बाला कैंट में बिजली की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। अम्बाला कैंट में रेलवे का कार्यालय है, कन्टोनमेंट है, पीओ एण्ड टीओ का कार्यालय है, एमओ ईओ एसओ वगैरा का इन्स्टालेशन है। अगर किसी कारणवश धुलकोट के सब-स्टेशन में कोई खराबी हो जाती है तो अम्बाला कैंट को बिजली सप्लाई करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाढ़ राहत के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यह एक अच्छी बात है। क्योंकि हर साल हरियाणा प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप हो जाता है जिससे काफी बर्बादी हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमने अम्बाला कैंट और भाहर के लिए तीन चरणों में होनी वाली योजना तैयार की थी जिसके दो चरण पूरे हो चुके हैं, अगर तीसरा चरण भी पूरा हो जाये तो अम्बाला कैंट बाढ़ मुक्त भाहर घोषित किया जा सकता है इस तीसरे चरण पर 23-24 लाख रुपये का खर्चा होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, रोडज के लिए बजट में काफी प्रावधान किया गया है। मैं यह पूछना

चाहता हूँ कि क्या इसमें भाहरो की सडके भी शामिल होगी जिनको ठीक करने का काम किया जायेगा। क्योंकि आज सबसे अधिक कठिनाई भाहरो की गलियों की है। बजट में कहा गया है कि गावों की गलियों को पक्का कराया जाएगा, वह जो ठीक है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारि है कि भाहरो की सडको की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बजट में सडको की मरम्मत के लिए जितने पैसे का प्रावधान किया गया है उसमें से भाहरो की सडको को भी हिस्सा मिलना चाहिए। भाहरो की गलियों की सडको को पक्का करवाने के काम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पीने के पानी की समस्या की ओर भी इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पीने के पानी के लिए सरकार ने अपने संकल्प को दोहराया है। यह सरकार प्रदेश के लोगों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाने का टारगेट अचीव करना चाहती है और इसके लिए बजट में अनेको योजनाओं का जिक्र किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अम्बाला, रोहतक और भिवानी में इन योजनाओं को लागू करवाने की तरफ वह ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आजाद विधायक हूँ मुझे पूरे हरियाणा का तो ज्ञान नहीं है लेकिन मैं अपने भाहर अम्बाला छावनी के बारे में जानता हूँ कि आज वहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि आज सही मायने में मुझे भी नहाकर यहाँ आने में बहुत कठिनाई का अनुभव करना पडा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अम्बाला छावनी में साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर बावल की

इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसके लिए केन्द्र से 400 करोड़ रुपये की मंजूरी भी आ चुकी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी ज्यादा देरी साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनने में हुई है उतना ही ज्यादा ध्यान इसकी ओर दिया जाए ताकि यह बाकि सेंटर्स के बराबर आ सके। अध्यक्ष महोदय, हेल्थ के बारे में की योजनाएं बनाई गई हैं। लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यूरोपियन कमीशन से 1000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त करके एक योजना तैयार की जा रही है। पूरे हिन्दुस्तान में 21 जिलों का चयन किया गया है जिसमें से तीन जिले हरियाणा के होंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तीन जिले जी० टी० रोड के साथ लगते हुए लिए जाएं क्योंकि इस रोड पर एक्सिडेंट्स ज्यादा होते हैं और मरीजों को पी० जी० आई० या रोहतक मैडिकल कॉलेज तक पहुंचाते पहुंचाते काफी मरीजों की जिंदगियां खो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अम्बाला के सरकारी अस्पताल की 75 बेड्स की कैपैसिटी को बढ़ाकर 100 बेड्स किया जाए। शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने गवर्नर एड्रेस पर भाषण देते हुए बताया कि हम नई शिक्षा नीति भी बनाने जा रहे हैं। मैं इसका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा की जो नीति बनाएं उसके बारे में सभी से विचार विमर्श करें और सभी से राय लें और वे लें भी रहे हैं जिसका मुझे पता

भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वे शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाएं और उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सब को शिक्षा के एक समान अवसर मिल सके। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि जो एडिड स्कूल है वहां के शिक्षकों को 16-18 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मैं समझता हूँ कि शिक्षकों को पहली तारीख को ही तनख्वाह मिल जानी चाहिए नहीं तो वह पूरे मन से बच्चों को नहीं बढा सकेंगे। (विधन)

श्री रामकिान: अध्यक्ष महोदय, अध्यापक बच्चों को शिक्षा नहीं देते। वे तो सिर्फ अपनी तनख्वाह बनाने के लिए स्कूल जाते हैं

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, भाई रामकिान जी जो बात कह रहे हैं वह मैं तो नहीं कह सकता और नहीं ऐसी मेरी संस्कृति है। यह बात तो रामकिान जी ही कह सकते हैं।

श्री रामकिान: अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी चाहे तो स्कूलों में चेंकिंग करवा ले, वहां पर अध्यापक बच्चों को पढाने की बजाए हुक्का पीते हैं। (विधन)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने व्यापारियों को भी सहूलियतें देने के लिए काफी कार्य किए हैं। सेल्जटैक्स के फार्म 14 व 15 को खत्म किया है और 50 लाख

रुपये तक की सैल्फ-असैसमेंट की स्कीम लागू की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा जहां पर यह व्यवस्था लागू की गई है। मैं सरकार का इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नगरपालिकाओं की हालत सुधारने की भी व्यवस्था बजट में की है। भाहरो का विकास करने के लिए पहले गवर्नर एड्रेस में भी और अब बजट में भी बात कही गई है। स्पीकर सर, सरकार ने चुंगी समाप्त करके बहुत ही सराहनी काम किया है। इसके लिए मैं दिल से सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। जो कर्मचारी सरप्लस थे उनको भी सरकार ने दूसरे विभागों में एडजैस्ट किया है। इसके लिए भी मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि भाहरो की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम गावों को बेहतर बनाना चाहते हैं। वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ैसिलीटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि हर घर के सामने गली पक्की हो, सीवरेज की एक लाइन हो, पीने का पानी हो, स्ट्रीट लाइट हो। ये सुविधाएं हर भाहर में मुहैया कराने के लिए सरकार कोई न कोई योजना जरूर बनानी चाहिए और कोशिश करे कि भाहरो की सीवरेज व्यवस्था भी सुदृढ़ की जाये। खासतौर से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भाहरो में जो ग्रुप लैट्रिंग बनी हुई है वे ओल्ड टाईप की है। उनको भी सुलभ भौचालय में प्राथमिकता के आधार पर बदलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सदस्यगण, बजट पर तकरीबन सभी सदस्य बोल चुके हैं। जो मैम्बरज अभी तक बोल नहीं पाये हैं, वे बजट की जो डिमांडज आएंगी उन पर बोल सकते हैं। अब वित्त मंत्री जी अपना उतर देंगे।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रुलिंग देने से पहले एक बार पुनर्विचार कर लें। हमारी आपसे विनती है कि हमारे जो मैम्बरज बजट पर बोल नहीं पाये हैं उन्हें 5-5 मिनट बोलने के लिए समय दे तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आपने 5 मैम्बरो का नाम दिया था जबकि आपकी पार्टी के 7 मैम्बर बोल चुके हैं। एक तरह से आपकी पार्टी के एक तिहाई सदस्य बजट पर बोल चुके हैं।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप इन्हे 5-5 मिनट बोलने के लिए दे दें। आप हाउस की कार्यवाही का समय चाहे 2 घंटे बढ़ा ले, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है हाउस का समय आधे घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री भजन लाल: आप सिर्फ हमारे मैम्बरज को 5-5 मिनट बोलने के लिए समय दे दें।

श्री औम प्रका 1 चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हाउस की कार्यवाही का सिर्फ आधा घंटा बढ़ाया जा रहा है न कि इनके मैम्बरज को बोलने के लिए आधा घंटा बढ़ाया गा है।

श्री धर्मबीर (तो 11म): अध्यक्ष महोदय, यहां पर ट्रेजरी के मैम्बरो ने बोलते हुए कहा कि यह बहुत ही बढिया बजट है और कर रहित बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे मे मेरा कहना यह है कि यह बजट कर रहित न होकर काम रहित बजट है। इस बजट मे कही पर यह नही द ार्या गा कि कहां से पैसा आएगा और उस आये हुए पैसे के कैसे कैसे काम होंगे। सरकार ने अपना जो बजट पे ा किया है वह घाटे का बजट पे ा किया हैं अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर बजट को कर रति दिखा दिया जाता है और बाद मे जनता पर टैक्स लाद दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो टैक्स लगाने हो वे बजट के दौरान ही लगाने चाहिए न कि बाद मे। आज हमारे पास काम करने के लिए पैसा कहा ंसे आएगा उसके कोई साधन इस बजट मे नही द ार्ये गए। सरकार जो काम करना चाहती है वह सारा कर्ज लेकर करना चाहिए। यदि सरकार कर्ज के माध्यम से काम करेबी तो फिर ऐसा कब तक चलेगा। दि किसी घर का मालिक काम न करे और अपनी आय के साधन न जुटाये और कर्ज लेकर ही काम करता रहे तो फिर वह कितने दिनों तक कर्ज लेकर अपने घर को चला पायेगा। बजट को देखने से पता चलता है कि हमारी मौजूदा सरकार की भी यही द ा लगती है। सरकार के अपनी

आय के कोई साधन नहीं है बल्कि कर्ज लेकर काम चला रही है। सारे काम कर्ज लेकर ही सरकार करती रही तो यह हरियाणा के हित में नहीं होगा। बजट को पढ़ने से मालूम हुआ कि सरकार को अपनी आय से सिर्फ 1600 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार इस राशि से हरियाणा का विकास कर पायेगी? यदि सरकार ने अपनी आय के साधन नहीं बढ़ाये तो आने वाले 5-7 सालों में हमारे राज्य का बिहार से भी बुरा हाल हो जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार को अपनी आय के साधन जुटाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि सरकार के पास आय के साधन हो सके। (शोर एवं विघ्न)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय धर्मबीर जी से मेरा निवेदन है कि वे हमें सुझाव दें कि कौन से सख्त कदम उठाये जिनसे सरकार के पास आय के साधन अधिक हो सके। (शोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, हम तो इनसे सुझाव मांग रहे हैं कि ये हमें बताएं कि कौन से कदम उठायें। (शोर एवं विघ्न)

श्री धर्मबीर: अध्यक्ष महोदय कल जो बजट पेश किया गया था उसको मैंने पढ़ा है। इस साल जब चुनाव हुए तो नैनल लोक दल के उम्मीदवार कहते थे कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बेरोजगार युवकों को नौकरियां देंगे लेकिन बजट पढ़ने से मालूम हुआ कि नौकरियों देने की बात इस बजट में कहीं पर नहीं की गई है। अगर किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं

दे सकते तो इस बजट का क्या फायदा। अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वे मजबूर हो कर गलत रास्ते पर चलने लगेंगे। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए कोई स्कीम जरूर लाएं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्री ट्रेडों में एजुकेशन ले कर आते हैं कि आई0 टी0 आई0 या पोलिटैक्निक संस्थानों से जो युवक टैक्नीकल ट्रेडों में एजुकेशन ले कर आते हैं केवल उनही लोगों को वहां पर नौकरियां दी जाएं। इन फैक्टरीयों में बाहर के लोगों को नौकरियां नहीं दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक और प्रार्थना करना चाहूंगा। विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि 100 से बढ़ा कर 200 रुपये की गई है। ये खुद भुक्त भोगी है इसलिए विकलांगों को जो परसेंटेज है उसको कुछ कम करे। विकलांग पेंशन के लिए केवल वही लोग पात्र हैं जो 70: विकलांग हैं अगर इस विकलांगता की परसेंटेज को 30: कर दिया जाए तो कुछ और ऐसे विकलांग लोगों को भी वह पेंशन मिल सकती है जो कि काम करने के योग्य नहीं है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में जो अधुरे काम पड़े हुए हैं इनकी बाबत मैं कहना चाहूंगा। खासकर सड़कों, नहरों और पब्लिक हेल्थ के ऐसे काम जिन पर 90: काम हो चुका है और केवल 10: काम भोश बचा है इस 10: काम को पैसे की कमी को पूरा करके इस साल में जरूर करवाने का प्रावधान बजट में करे ताकि जो पुराना खर्च हो चुका है वह पैसा वेस्ट न जाए और वे

स्कीमें लोगो के काम भी आ सके। मैने पहले भी जिक्र किया था खासकर जुई नहर तथा सिवानी नहर के दोनो तरफ सीपेज है इसलिए एम० आई० टी० सी० के माध्यम से वहां पर ट्यूबवैल्वज लगवाए जाए ओर उस पानी को नहर मे डाला जाए ताकि टेल पर भी पूरा पानी मिल जाए और वहां पर जो सेम का इलाका है वहा सेम खत्म हो सके। दूसरी तरफ जहां पर मोधे नहीं है वहा पर नए मोधे दिए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां पर उंचे उंच टिले है उन टिब्बो पर सिंचाई करने के लिए करीब दस साल पहले 100 स्प्रिंकलर सैटस खरीदे थे। ये स्प्रिंकलर सैटस जब से खरीदे है बेकार पडे है और इनका यूज नहीं किया जा रहा है इस कारण जो पैसा इन सैटस को खरीदने पर लगाया गया था वह वेस्ट गया और कोई काम इनसे नहीं लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि उन स्प्रिंकलर सैटस को दोबारा से युज किया जाए ताकि जो पैसा बेकार खर्च किया हुआ पडा है उसका कुछ फायदा प्रदे त्वासियो को हो सके। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: धर्मबीर जी, आप ये सारी बाते पहले भी कह चुके है इसलिए इनका रिपीट न करे। (विध्न) उनही बातो को दोहराने का कोई लाभ नहीं है।

श्री धर्मबीर: अध्यक्ष महोदय, भिवानी भाहर के साथ हमारी जो जुई कैनल जाती है गवर्नमेंट कालेज के पास से जो गन्दा नाला गुजरता है उस नाले का पानी इस नहर मे डाल दिया

जाता है जिसकी वजह से सारे एरिया में सांस की बीमारी फैल गई है। इसलिए उस गन्दे नाले के पानी का नहर में डालने से रोका जाए मुख्य मंत्री जी ने भी एक बात कही है और इस बजट भाषण में भी वह बात है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए नये प्रकार के फूलों और फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं लेकिन उन चीजों के लिए जब बिजली कनेक्ट नहीं लेने जाते हैं तो उनसे कम रियल बिल लिया जाता है। इस सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से बिजली के कर्मि रियल बिल की जगह नार्मल बिल ही चार्ज किए जाए।

श्री अध्यक्ष: आप इस बारे में पूरी डिटेल लिखकर सरकार को दे दें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री धर्मवीर: अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं को-ओपरेटिव सिस्टम के बारे में भी कहना चाहूंगा। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात की तरह को-ओपरेटिव सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र गुजरात और बीकानेर में यह सिस्टम है वैसी ही को-ओपरेटिव सिस्टम यहां पर लागू किया जाना चाहिए और उस सिस्टम का प्रबन्ध लोगों के हाथों में देना चाहिए। इस बारे में हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री हुड्डा जी ने भी कहा है कि इसको एग्यामिन करवा कर इसी प्रकार का को-ओपरेटिव सिस्टम लागू किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से

ज्यादा लोगो की भागीदारी उसमे हो सके। आज बीकानेर मे डेयरी सिस्टम का जा कर देखे। बीकानेर डेयरी वाले अपने आप फीड भी देते है, पशु खरीदने के लिए पैसा भी देते है जिसका वजह से गरीब आदमी का गुजारा बडे अच्छे ढंग से हो रहा है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि को-ओप्रेटिव सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि गरीब आदमियो का पालन पोशण ठीक ढंग से हो सके। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की भामलात भूमि पर कुछ लोगो ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया है। पहले जब भी कोई गांव बसता था तो उसके आस पास कुछ एरिया खाली छोडा जाता था ताकि वहां पर लैंड लैस लोगो की भेड बकरिया चारा चर सके। लेकिन अब उन जमीनो पर कब्जा कर लिया गया है। आप इस समस्या के समाधन के बारे मे कुछ करे। स्पीकर सर, एजुकेशन प्रदेस के लिए बहुत जरुरी है। यह सरकार एजुकेशन मे किस प्रकार से बढावा दे रही है उस पर हमे ऐतराज है। एजुकेशन बोर्ड मे जनरल सैक्रेटरी ओर सैक्रेटरी कमिन्टर रैंक के होने चाहिए और आप वहां पर अनपढ लोगो को लगा रहे है। इस बारे मे सरकार विचार करे। धन्यवाद।

भाक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन का ध्यान आज घटित एक अप्रिय घटना की तरफ दिलाना चाहूंगा। श्री जे.0 एस.0 राजू, पूर्व राज्य सभा के सदस्यथे उनका आज सुबह हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया

है। वे 64 वर्ष के थे। आज सुबह उन्होंने छाती में दर्द होने की
िकायत की तो उनको हास्पिटल ले जाया गया। रास्ते में ही
उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चे छोड़ गए
हैं। वे 1989 से 95 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे
1967 से 1980 तक तमिलनाडु असेंबली के सदस्य चुने गए थे।
आज वे इस संसार में नहीं रहे हैं मैं अपनी हार्दिक सांत्वना उनके
परिवार के प्रति प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, दिवंगत आत्मा के प्रति
सदन के नेता ने अपने जो विचार प्रकट किए हैं मैं भी अपने
आपको उनकी भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूँ। इस दिवंगत
आत्मा के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं भागेक
संतप्त परिवार को सदन द्वारा प्रकट की गई संवेदना पहुंचा दूंगा।
अब मैं दिवंगत आत्मा के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए दो
मिनट का मौन धारण करने के लिए सभी माननीय सदस्यों से खड़े
होने का अनुरोध करता हूँ।

(इस समय दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन के
सदस्यों ने खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया)

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राम किान (बवानी खेडा, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष
महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं
आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान

प्रदे 1 है। यह जो बजट है इसमें सबसे ज्यादा बातें गन्ने के बारे में कही गई है। मेरे हलके में तो गन्ने की बिजाई होती है और न ही कोई गन्ने की पिराई की मिल है। हमारे यहां पर गन्ना बवानी खेडा में लग सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वही पर गन्ने की पिराई के लिए मिल लगाई जानी चाहिए ताकि वहां के लोगो को रोजगार मिल सके। उनको कोई काम धन्धा मिल सके। मेरे हलके के लोगो को तो यह भी नहीं पता कि गन्ना पैदा कैसे होता है। (विधन) जो सरकार हमारे हक देगी वही हमारी सरकार है। इसी तरह से चावल की बात रही। चावल का भाव देने से मेरे हलके को क्या फायदा हुआ क्योंकि चावल तो हमारे यहां होता ही नहीं है। (विधन) अगर चावल सिरसा में हो सकता है तो बवानीखेडा हलके में भी हो सकता है। अगर हमारे यहां पर सरकार चावल पैदा नहीं कर सकती तो फिर वह हमारे यहां पर फ़ैक्टरी ही लगवा दे ताकि हमारे यहां के नौजवानो को रोजगार मिल जाए और उनकी बेरोजगारी दूर हो जा। इसके अलावा मैं नहरी पानी की मांग पहले भी करता रहा हूं और आज भी यह मांग उठा रहा हूं कि हमें दो हफते नहरी पानी मिलना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि यह सरकार हमें पूरा पानी देगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शिक्षा की बात है। आजकल तो सरकारी स्कूल है उनमें टीचर्स जाते ही नहीं है अगर जाते भी हैं तो एक हफते में एक बार जाते हैं और हुक्का पीकर वापस आ जाते हैं उनकी कोई चैकिंग नहीं होती। मेरी सरकार से मांग है कि जजिल 'लेवल पर कोई चैकिंग टीम भेजी जानी चाहिए जो सरकारी

कर्मचारी सही कामम नही करते उन्हे ससपैंड किया जाए और उन्हे घर बैठा दिया जाए। हमारी सरकार कहती है कि हमने स्कूलो के लिए इतना पैसा दे दिया। लेकिन केवल पैसे से क्या होता है जब सामान ही नही होगा तो फिर स्कूलो मे डांगर ही जाएंगे। इसी तरह से गावों मे ही हमारी बहन बेटियो के लिए कालेज होने चाहिए क्योंकि एक गरीब मजदूर अपनी बेटी को गांव से बाहर पढने के लिए नही भेज सकता। उसके पास इतना पैसा भी नही है कि वह भाहर मे उसको भेज सके। इसलिए उसकी लडकी गहर मे पढने से कतराएगी। वह दूसरी अमीर लडकियो को देखकर भार्माएगी कि हम तो इतने गरीब घर के है और वे इतनी अमीर घर की है। इसलिएगांव मे कालेज होने चाहिए। अगर ऐसा होगी तो हमारे बच्चे पढने के काबिल हो जाएंगे और बाद मे उनको नौकरी भी मिल सकेगी। स्पीकर साहब, आज प्राईवेट स्कूल चलाने वाले फीस के रुप मे बच्चे से बहुत पैसा मंगाते है। अगर सरकारी सकूल नही होंगे तो गरीब के बच्चे तो बिना पढे ही रह जाएंगे। इसलिए जब तक उनको सही िाक्षा नही मिलेगी तब तक वे नही पढ सकेंगे। दवाई सरकार तो देती है लेकिन वे सारी दवाई प्राईवेट दुकानो मे बेच देते है उनकी कोई चैकिंग ही नही होती। जिसके कारण गरीब जनता को कोई दवाई नही मिलती इसलिए इस बारे मे जिला लेवल पर चैकिंग होनी चाहिए। हफते मे तीन दिन इनको जाकर चैकर करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी पब्लिक को दवाई मिल सकेगी और उनका सही इलाज हो सकेगा। स्पीकर साहब, गरीब कन्याओ के लिए सरकार द्वारा जो 5100

रुपये दिये जाते हैं उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि उनको एक चीनी की बोरी और चालीस किलो बेसन भी दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जब कोई आदमी हमारे घर आएगा तो उससे हमारी इज्जत बढ़ेगी। स्पीकर साहब, अगर 36 बिरादरियों को एक करना है तो ऐसा होना ही चाहिए। पैसा पैसे की जगह काम करेगी और रात-रात की जगह काम करेगा।

श्री अध्यक्ष: अब श्री रघुबीर सिंह कादयान जी बोलेंगे। आपको पांच मिनट का समय दिया जाता है।

श्री रघुबीर सिंह कादयान (बेरी): धन्यवाद स्पीकर सर, मैं बजट के पक्ष में या विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ वित्त मंत्री जी खुद इस बात का फैसला करें। क्योंकि जिस दिन बजट हाउस की टेबल पर रखा गया। बजट पेश होने का बाद जब हम गए तो बड़ी बड़ी किताबों का एक गठठा दिया गया और उसके बाद किताबों का एक और गठठा दिया गया। कई माननीय सदस्यों से वह किताबें उठी नहीं। किस के पेट में दर्द हो गया।

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब, टू दि प्वायंट बोलिए।

श्री रघुबीर सिंह कादयान: स्पीकर सर, ये सारी बातें और ऐस्टीमेट्स बनाने में काफी दिन का समय लगा होगा। मेरे हिसाब से किसी सदस्य में इतनी महारत नहीं है कि वह इस सारे के सारे गठठों को पढ़ सके और उसको समझ सके, पढ़ तो सकता

है लेकिन जैसा खुद वित्त मंत्री जी ने बताया कि पढने लगूं तो हफता लग जाएगा और आपने हमे इस पर चर्चा के लिए एक दिन का समय दिया है मेरा सुझाव है कि सभी सदस्यों के लिए बजट के उपर समझने का और जो उसकी टर्मिनोलोजी है, उसकी इकोनिमिक्स है उस पर कोई ट्रेनिंग या वर्क शाप कंडक्ट की जानी चाहिए। कम से कम जैसे यह बजट हफते मे पढा जा सकता है तो एक हुते के बाद अगर सैंशन हो तो सइस पर रचनात्मक सुझाव आ सकते है। दूसरे जहां तक मै कहूं कि बजट पढा या नजर दौडाई तो ऐसा कुछ नही किया। लेकिन जो सबसे पतली बुक बजट एकाउंट ए ग्लान्स है, दूसरा जो संपत सिंह जी ने बजट भाषण पढा इस सारे मामले को जब हम मोटा मोटा देखते है तो पाते है कि स्टेट के जितने रिसोर्सिज है वह सारे के सारे तनखाहो मे यानी कि नान प्लान ऐक्सपेंडिचर मे और लोन की अदायगी मे ही बंट जाते है। नये असैट्स के लिए सरकार के पास कोई पैसा नही है। लगभग पूरे पूरे प्लान कर्जो से पूरे करने की नीयत साफ झलकती है। मै आपके सामने एक सुझाव रखूं कि जैसे बजट एकाउंट ए ग्लान्स मे वित्त मंत्री जी ने 1999-2000 मे रैवेन्यू रिसीट्स मे बजट ऐस्टीमेट दिया है 6901 करोड और रिवाइज ऐस्टीमेट 5979 करोड रुपये दिया है इसमे सीधा सीधा एक हजार करोड रुपये का डाउन फाल है। यह आपका रिकार्ड बता रहा है। इसमे जिसतरह से बजट ऐस्टीमेट दिया है 6755 करोड रुपये का, उसमे कितना ऐग्जरेसेशन है क्या ये रिकरिंग रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट उसको पूरी कलैक्शन है। क्योंकि इसमे जो बताया गया है

कि टैक्स रैवेन्यू 1999-2000 में बजट ऐस्टीमेट्स में 4406 करोड़ रुपये थे और इसके रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में वे 4186 करोड़ रुपये हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री अपने भाषण में यह कहते हैं कि हमने टैक्स रिक्वरी को बीस प्रति सेंट बढ़ाया है। परन्तु इस रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में तो 300 करोड़ रुपये टैक्स रैवेन्यू का डाउन किया गया है। इसके बारे में वित्त मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, तीसरा मैं रैवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कहना चाहता हूँ। रैवेन्यू एक्सपेंडिचर का सारा का सारा नॉन प्रोड्यूसिंग इन 8097 करोड़ रुपये है जोकि टोटल एक्सपेंडिचर का 85 प्रति सेंट है। आपके बजट और बजट एट दी ग्लॉस में फिगर बदले हुए हैं। वित्त मंत्री जी बताये कि आपका बजट ठीक है या बजट एट ए ग्लॉस ठीक है? हेल्थ, एजुकेशन, रुरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर आदि पर 11.2 प्रति सेंट बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें से 2.02 प्रति सेंट कृषि पर खर्च किया जाना है जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हितैशी बनते हैं। मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि बजट के हिसाब से टोटल पैसे का 100 में से 2 प्रति सेंट कृषि पर खर्च किया जाना है। रुरल रिसोर्सिज पर 16 प्रति सेंट खर्च करना आपने इस बजट में दिखाया है। 16 प्रति सेंट में से 15 प्रति सेंट तो सैलरी ऐस्टीबिलिसमेंट पर खर्च हो जाता है, उसके बाद हेल्थ विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है और रुरल डेवलपमेंट विभाग भी है। इसके साथ साथ बजट के पेज नम्बर 6 पर दिखाया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब, आपका एक मिनट और बाकी है।

श्री रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, बजट के पेज नम्बर 6 पर दिखाया गया है कि 64.05 फीसदी बजट बिजली पर, इरीगे ान पर, ट्रांसपोर्ट पर, रोड्ज पर खर्च होगा। जिसमे से बिजली पर 9.44 प्रति ात, इरीगे ान पर 7.79 प्रति ात, ट्रांसपोर्ट पर 4.14 प्रति ात, रोड्ज पर 5.82 प्रति ात और टोटल 27.19 प्रति ात रुपीज गोज मे दिखाया गया है। वित्त मंत्री जी इसमे से कहा पर कटौती कर सकते है क्योंकि उन्होने 4.5 फीसदी बजट खर्च करने को कहा है और रुपीज गोज मे 27.19 है।

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब आप दस मिनट बोल चुके है, अब आप बैठ जाइए।

श्री रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, यह बडी चिंता का विशय है कि हमारा 34.37 प्रति ात बजट ब्याज के भुगतान और ऋण की अदायगी पर खर्च हो रहा है। आज प्रदे ा किस दि ाा मे जा रहा है और प्रदे ा के लोगो के हितो को किस दि ाा मे यह सरकार ले जा रही है। क्योंकि उन पर तो ऋण का भार डाला जा रहा है। इसलिए मै इस सरकार को आने वाले भविश्य के बारे मे चेतावनी के रुप मे बताना चाहता हूं कि सरकार इस बोर में कुछ आव यक कदम उठाये।

श्री अध्यक्ष: ादयान साहब आप दस मिनट बोल चुके हैं, अब आप बैठ जाइए।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब जो कुछ कह रहे हैं वह तस्वीर का दूसरा रूप है। लोन रिपेमेंट 17.03 प्रति ात है और इंटरस्ट पेमेंट 13.5 परसेंट है। who is responsible for re-payment. ये रिपेमेंट और सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी हम लोग नहीं उठाएंगे तो कैसे सरकार चलेगी। ि ाक्षा के लिए कुल बजट का 11.92 परसेंट रखा गया है और इतनी राशि पहली बार बजट में एजुके ान के लिए रखी गई है जबकि सेंटर गवर्नमेंट में 6 प्रति ात से ज्यादा ि ाक्षा के लिए बजट में नहीं रखा गया है। ि ाक्षा के लिए इस बार हरियाणा का बजट सबसे ज्यादा है। इस बात के लिए सबको सरकार की प्र ांसा करनी चाहिए। (ाोर) जो मैं कह रहा हूँ वह बजट एट ग्लॉस में दिया हुआ है। (ाोर)

श्री अजय सिंह (रिवाडी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सम्पत सिंह जी ने 14 मार्च को जो बजट पेश किया है, मेरे हिसाब से यह बजट दि ाहीन है और किसी प्रकार से भी विकासोन्मुख नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि इसमें जो 2530 करोड रुपये का वार्षिक योजना के आकार का जिक्र किया गया है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें तकरीबन 295 करोड रुपये का घाटा है जो कि पिछले साल का था। इसी प्रकार सरकार ने अपने संसाधन जुटाने के लिए

आटोमोबाईल, लग्जरी आईटम पर सेल्ज टैक्स बढ़ाए है और यूनिफार्म टैक्स भी बढ़ाए है। मै समझता हूं कि ये टैक्स लगाने से सरकार को 150 करोड रुपये की राहत होगी। लेकिन सरकार ने अपने संसाधन जुटाने के बारे में किसी भी कार्यवाही का जिक्र नहीं किया है। इसके साथ साथ ही मै सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि हुडडा, मार्किटिंग बोर्ड और जितने भी बड़े बड़े बोर्ड और कारपोरेट्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को सरकार अपनी प्लान आउट ले में शामिल करे। उसी प्रकार से सरकार एक रिसोर्स मोब्लाइजेशन इकलॉमिक कमेटी गठित करे इस कमेटी के मैम्बर सरकारी अफसरों और खास तौर से पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो जो इस बारे में अपने सुझाव दे सकें। इस सरकार ने कुछ टैक्सों को अबोलिशन करने का भी काम किया है खासतौर से रुरल डिवैल्पमेंट सैस 2 परसेंट अबोलिशन किया गया है, मुझे इस बार को लेकर आपत्ति है क्योंकि उसका सीधा असर किसानों के ऊपर पड़ता है। एव0 आर0 डी0 एफ0 जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें वगैरह बनती हैं, को भी बहुत भारी घाटा पहुंचा है। उसी प्रकार समय समय पर सरकार कुछ सेल्ज टैक्सों को कम करती है, कुछ को ज्यादा करती है। उसके बारे में सरकार एक व्हाइट पेपर इरू करे। जिसके द्वारा यह बताया जाए कि जब से हरियाणा बना है तब से किस चीज पर कितना टैक्स कम किया गया है और कितना बढ़ाया गया है और ये क्यों कम या ज्यादा किए गए हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि हरियाणा में कई ऐसी फैक्ट्रीयां काम कर रही हैं जिनके हैंड आफिस दिल्ली में बने हुए

है, रसीदे भी उनकी दिल्ली में कटती है और जो टैक्स हरियाणा में दिया जाना चाहिए वह दिल्ली में दिया जाता है। इसलिए इसके बारे में बकायदा एक कानून बनाया जाए कि अगर कोई फैक्ट्री हरियाणा में चल रही है तो उसकी जितनी भी कन्साइनमेंट है, वह हरियाणा में ही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए ताज्जुब होता है कि इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग के अंदर इनटेक की कपेसिटी 1998-99 में 15792 थी। जो अब कम होकर 14997 हो गई है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा सरकार टैक्नीकल पजुकेट्स के बारे में सीरियस नहीं है। अध्यक्ष महोदय इसी से मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश द्वारा 1996 में डैबिट के तौर पर 6212 करोड़ रुपये लिया गया था। जो कि 2001 में 15216 करोड़ रुपये हो जाएगा। यानि सरकार का ले-आउट 2530 करोड़ रुपये है और 2001 में सरकार के उपर 15216 करोड़ रुपये लोन के डैबिट के रूप में हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में रि-पेमेंट 1932 करोड़ रुपये की होगी, जो इकनॉमिक सर्वे आफ इंडिया में दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर पर पावर सैक्टर के बारे में कहना चाहूंगा जिसके लिए सरकार ने 626.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बारे में मुझे यह आपत्ति है कि सरकार यह बताये कि इस पैसे की इन्वेस्टमेंट के आपके क्या प्रोग्राम हैं? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एस्टीमेट कोस्ट 7 हजार करोड़ रुपये होगी। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट में जो ऐड वर्ल्ड बैंक से मिली थी उसके बारे में जिक्र नहीं किया कि कितने पैसे लोन के रूप में

वहां से मिले थे और कितने पैसे और मिलने वाले हैं तथा वर्ल्ड बैंक की इस बारे क्या क्या बातें हैं? अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक ने सरकार को इस बारे धमकी दी है कि उनके लीगल एग्रीमेंट की भातों को 3-4 कारपोरे इंज पूरी करने में असफल रही है। इस ओर सरकार अपना ध्यान दें क्योंकि प्रदेश की जनता इस बात के लिए बहुत चिंतित है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जो पावर रिफोमर्ज चौधरी बंसी लाल जी के समय में चालू किये गये थे उनके बारे में सरकार अपनी नीति स्पष्टकरे कि सरकार टोटल कंवर्न आफ लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में वैल्यू बेस सर्विसिज के बारे में, टैरिफ के रैगुलैशन करने के बारे में भी सरकार क्या कदम उठा रही है? अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार पावर प्रोजेक्शन की क्वांटिटी चाहे कितनी भी बढ़ा ले लेकिन जब तक 11 के 0 वी 0 की लाईनों को ठीक नहीं किया जायेगा तब तक बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष महोदय पावर के बारे में इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें ट्रांसपियरेंसी होनी चाहिए। चाहे टैरिफ का मामला हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से लोन का मामला हो, पावर क्षेत्र में पूरी तरह से ट्रांसपियरेंसी होनी चाहिए। मैंने बजट पढ़ा है, इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि पावर के बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप 2 मिनट में वार्ड अप करें।

श्री अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में वाईड अप कर दूंगा। मैं कृषि के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और इस क्षेत्र के लिए बजट में 111 करोड़ रुपये दिए गए हैं। भुगर केन का प्रोड्यूसन 1996-97 में 9.2 लाख टन था जो घटकर 1997-98 में 6.8 लाख टन हो गया। मेरे कहने का मकसद यह है कि भुगर केन के अंदर भी डिकलाईन हो रहा है और इसी तरह से फुडग्रेज के अंदर भी डिकलाईन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 1998-99 में फुडग्रेज का प्रोड्यूसन 121.23 लाख टन था जो 1999-2000 में घटकर 116.15 लाख टन हो गया। अध्यक्ष महोदय, केवल आयल सीड में थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, वह भी इसलिए कि हमारे यहां पर सुरजमुखी की खेती अच्छी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, इरीगेशन के बारे में आर0 आर्इ0 डी0 एफ0 और नाबार्ड के तहत रिवाडी और महेन्द्रगढ जिलों में जो फल्ट प्रॉटेक्शन की 36 स्कीमें हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि उनको रिस्टोरिंग एक्सटेंशन आफ एगिजिस्टिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए जो टोटल स्कीम थी वह 508 थी जिसमें से केवल 58 कम्प्लीट की गई हैं। तकरीबन 90 स्कीमें ऐसी हैं जिनको टच भी नहीं किया है। पिछली सरकारों ने जान-बूझ कर उन स्कीमों को टच नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: कप्तान साहब, अब आप बैठ जाइए। आपका समय पूरा हो चुका है। जो सदस्य बोलने के लिए रह गये हैं अब

ये डिमाण्डज पर बोल सकते हैं। काफी समय हो चुका है। साढ़े सात घंटे का समय दिया गया है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लें।
(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कप्तान साहब, आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पांच मैम्बरो ने बोलना था और चार मैम्बर बोल चुके हैं। एक मैम्बर अभी बाकी है उसको भी पांच मिनट का समय दें। उसमें क्या फर्कपडता है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ। (विघ्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, अभी आप बैठिए। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पर बाद में बोल लेना (गोर)

श्री अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी तो सुन लें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कप्तान साहब, आपकी भी अभी तक तसल्ली नहीं हुई। आपने 5 मिनट बोलना था और 10 मिनट से ज्यादा आप बोल चुके हैं। आप बैठिए। (गोर)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता के कहने पर आपने आधा घंटा समय बढ़ाया और वह सारा समय इनको ही मिला। सरकारी पक्ष की तरफ से इस समय कोई भी सदस्य नहीं बोला है।

श्री अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लें। (गोर)

श्री अध्यक्ष: कप्तान साहब, आप बैठिए। आप लोग भाषण बाजी बाद में कर लेना। यहां पर बजट पर बहस हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। आप लोगों को डिमाण्ड और ग्रान्ट्स पर भी बोलने का मौका मिलेगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर को बोलने दे। पांच मिनट में क्या फर्क पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आपके कहने पर ही हाउस का समय आधा घंटा बढ़ाया गया था और इस समय सवा चार बजने जा रहे हैं जबकि 3:00 बजे तक का समय था। (गोर) आगे एप्रोप्रिए इन बिल आएंगे, डिमाण्डज आएंगी उन पर बोल लेना। उन पर आप किस को बुलवाएंगे। (गोर)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठिए। आपके बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। (गोर) आपने आधे घंटे का समय बढ़ाने के लिए कहा था और आपके कहने पर ही आधा घंटा बढ़ा दिया था।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर को पांच मिनट बोलने दें।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप तो बड़े सुलझे हुए और अच्छे पार्लियामैन्टेरियन हैं। आपको इस तरह से बार बार खड़े नहीं होना चाहिए। आप बैठिए। (गोर)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने विपक्ष के नेता के कहने पर आधा घंटा समय बढ़ाया। हमारी तरफ से आधे घंटे में कोई भी नहीं बोला। सारा का सारा समय आपने इनको दिया। (गोर)

श्री अध्यक्ष: इन-प्रोपो नेट सबसे ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। और ज्यादातर मैम्बर दो-दो बार बोल चुके हैं। (गोर)

श्री रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब, आप बैठिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश: स्पीकर साहब, *****

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, जो बोल रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य को बोलने दें।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आपके 9-10 सदस्य बोल चुके हैं। आप बैठिए।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके सामने से लीडर आफ दि हाउस से निवेदन है कि हमारे जो एक दो मैम्बर बोलने से रह गए हैं उन्हें आप 5-5 मिनट बोलने का समय दें। (गोर एवं विघ्न)

श्री सम्पत सिंह: चौधरी साहब, अब से पहले जितनी बार भी आपने समय बढ़ाने के लिए स्पीकर साहब को कहा, स्पीकर साहब ने समय बढ़ाया। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: स्पीकर साहब, हमारे मैम्बर 7-8 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर लेंगे। आप हाउस का समय और बढ़ा लें।

श्री सम्पत सिंह: चौधरी साहब, जितना टाईम आप लोगो को दिया है आप हरियाणा विधान सभा का रिकार्ड उठा कर देख लें, इतना समय कभी भी विपक्ष को नहीं दिया गया। (शोर एवं विघ्न)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो हमारे दो सदस्य रह गए हैं उनको आप बोलने के लिए समय दे दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप लोगो को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। जो मैम्बर्ज रह गए हैं वे बाद में बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप लोगो को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। जो मैम्बर्ज रह गए हैं वे बाद में बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रका 1 चौटाला): चौधरी भजन लाल जी, पहले हम भी और आप भी हाउस के सदस्य रह चुके हैं। आज आप अधिकार की बात करते हैं। आपके समय में जब हम कहते थे कि हमें समय दे दिया जाये तो उस वक्त मैम्बर के अधिकार कहां चले गए थे? जब मैं विपक्ष में था तो उस वक्त विपक्ष का नेता होने के नाते मुझे 30 मिनट से ज्यादा का समय कभी नहीं दिया गया। आप अपने भासनकाल का टाईम याद करो। अब बजट पर आपके 21 सदस्यों में से 10 सदस्य बोल चुके हैं।

गवर्नर एड्रेस पर भी आपके तकरीबन सभी सदस्य बोले हैं। स्पीकर साहब, ने बड़ी उदारता के साथ आप सभी को बोलने का समय दिया। आपने उनका धन्यवाद करने की बजाये कह दिया कि स्पीकर साहब बोलने के लिए समय नहीं दे रहे, यह गलत बात है। आप वाक आउट करना चाहते हैं तो बे तक करें। अब और समय नहीं चढेगा क्योंकि स्पीकर साहब ने वित्त मंत्री जी को बोलने के लिए समय दे दिया है। अब आप लोग ध्यान से इनका उतर सुनें।

श्री भजन लाल: हमने तो अपने समय में आपको बोलने से कभी रोका नहीं। आप ही हमारी बात सुनने की बताये वाक आउट करके चले जाते थे। (शोर एवं विघ्न) यह कही होता है कि एक ही सदन में बजट पर बहस होकर उसे पास कर दिया जाये। आपसे निवेदन यही है कि हमारे मैम्बर रह गए हैं उन्हें आप डिमांड पर बोलने का आ वासन दे दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठिये।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 5-5 मिनट अगर सभी को बोलने के लिए समय दे दिया जाये तो उससे क्या फर्क पडता है। (शोर एवं विघ्न)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय यह बात ठीक नहीं है, कुछ लोग बोलना चाहते हैं उनको बोलने का समय दिया जाना चाहिए। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठिए। (विघ्न)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य चुनाव जीतकर सदन में आये हैं कोई किसी के रहमोकरम से सदस्य बनकर नहीं आया है। इसलिए जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहत है उनको बोलने का समय मिलना चाहिए। (विधन) अगर आप चाहे तो आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन आपको हमें बोलने के लिए समय तो देना ही चाहिए। (विधन)

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी, अगर आप चाहे तो खुद सदन से बाहर जा सकते हैं। मैं आपको हाउस से बाहर नहीं निकालूंगा। यदि मैं आपको हाउस से बाहर निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। (शोर एवं विधन)

वाक-आउट्स

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमारे साथियों को बोलने का समय देना नहीं चाहते तो हम वाक आउट करके जाते हैं।

श्री औम प्रका । चौटाला: अभी डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है इसलिए चौधरी भजन लाल जी आप वाक आउट करके न जाएं।

श्री भजन लाल: जब बोलने के लिए समय नहीं दे रहे तो हम वाक आउट करके जा रहे हैं।

(इस समय इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक आउट करके चले गए)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठिए। ये मेरी परमिशन के बगैर जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। दलाल साहब, बोलने के लिए 35 मिनट का समय दिया गया था। आप तो केवल अपनी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। पार्टियों के हिसब से आपका केवल सात मिनट का समय बनता था। लेकिन फिर भी आपको बोलने के लिए 35 मिनट का समय दिया गया है। आपके अलावा और भी बहुत से सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। अब वित्त मंत्री जी बजट पर हुई बहस का जवाब देंगे। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो मैं भी वाक आउट करता हूँ।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया के माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल भी सदन से बाहर चले गये)

वर्ष 2000-2001 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): स्पीकर सर, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर बोलने से पहले मैं एज पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर बोलना चाहता हूँ। हम लोग विपक्ष के सदस्यों द्वारा जो

बाते कही गईं वे सभी सुनते रहे हैं। आज ही नहीं जिस दिन से सदन भंग हुआ है उस दिन से लेकर अब तक हमने ओपोजी इन की हर बात को सुना। उनको बोलने के लिए आपने मैक्सिमम टाइम दिया है। आज तक कभी भी ओपोजी इन पार्टी के लोगों को बोलने के लिए इतना टाइम नहीं मिला विशेष कर सारे ही हाउस के मैम्बर ने कंट्रीब्यूट किया। इतनी बड़ी संख्या में इंडिविजुअल मैम्बर आज तक कभी नहीं बोले। जो सारी बातें उन्होंने कहनी थी वे तो उन्होंने कह ली अब वे केवलमात्र इस बात से यहां से उठकर चले गए हैं कि हाउस को फेस नहीं करना चाहते। चुनाव में वे पब्लिक को फेस नहीं कर पाए और अब हाउस के अंदर भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने खुद जो जगलरी डंग से आंकड़े पेश करने की बात की थी उन बातों का जवाब दिया जाना था। उन लोगों में हिम्मत होनी चाहिए थी कि उन बातों का जवाब सुनते। उनके द्वारा अनपार्लियामेंटरी तरीके से वाक आउट करना ठीक नहीं है अगर वाक आउट का कोई समय होता तो कुछ और बात थी। विपक्ष के नेता ने जितना टाइम मांगा अपने बार बार दिया लेकिन उसके बावजूद भी केवल मात्र एक तमा पेश करने के लिए उन्होंने वाक आउट कर दिया। जब बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया और कुछ सुनने की हिम्मत उनमें नहीं थी केवलमात्र अखबारी खबर बनाने के लिए उन्होंने यह वाक आउट किया है। उनका यह वाक आउट वास्तव में वाजिब नहीं है। स्पीकर सर, आपकी इजाजत से अब मैं रिप्लाइ देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय सदन में कल बजट एस्टीमैट

2000-2001 रखा गया था। आज बह से उस पर बहस चल रही थी बहुत से सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए और कुछ आलोचनाएँ भी की हैं। सुझाव और आलोचनाओं को मैं बड़े सब्र से सुन रहा था और उनको नोट कर रहा था। जो जो भी हाउस में हैल्थी डिस्कशन हुई है मैंने उनको नोट किया है। सर, समुचे विपक्ष को चाहिए तो यह था कि इस बजट का वैल्यू कम करते। इस भाताब्दी का यह पहला बजट पैसा हुआ है। इतने वित्तीय बोझ के बावजूद इस सरकार ने अच्छा काम किया है यह सब आप जानते हैं। एक तरफ चुंगी माफ हुई, उससे कितना बोझ पड़ा है। यह सबको पता है। वृद्धावस्था पेंशन, हैल्थकेअर पेंशन, भाहीदों के आश्रितों की पेंशन वगैरह से स्टेट एक्सचेंजर पर 3 गुणा बर्दन पड़ा है जिसको बढ़ाकर 320 करोड़ रुपये करना पड़ा है। इसी तरह से जो भुगर केन के दाम बढ़ाये हैं वह रिकार्ड तोड़ दाम हैं। आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतने दाम नहीं बढ़ाये जो कि हरियाणा सरकार ने बढ़ाए हैं। आज ही हरियाणा में भुगर केन के दाम 110 रुपये प्रति क्विंटल हैं। बहुत से आईटमों पर मार्केट फीस दो से एक प्रतिशत की है। कन्यादान की स्कीम शुरू की है। टैक्सों पर भी कई स्कीमों बनी हैं जिससे लोगों को राहत मिलेगी। इन बातों को ये सुनते तो कुछ बात बनती। लेकिन ये गलत तरीके से अपनी ड्यूटी करके यहां से बाहर चले गए। बहुत से सदस्यों ने यहां पर बहुत सी बातें कही। मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। यहां पर सदस्यों ने जो ग्रीवेंस रखी अपनी मांगें रखी मैंने वह सब नोट कर ली हैं। मैं उस बारे में कहना चाहूंगा कि हम

उनको विभिन्न विभागों को भेज देंगे। आप सब को मालूम है कि उन पर एस्टीमैंट बनते हैं उन पर सरकार सिरीयसली सोच समझ कर काम करवाएगी। जैसा पहले की सरकारों के वक्त में भेदभाव किया जाता था हम वैसा नहीं करेंगे। हमारे लिए 90 के 90 विधान सभा के हलकों बराबर हैं। जैसे कि भागी राम जी ने बताया कि कुछ हलकों को जानबूझ कर इग्नोर किया गया था उनको हम प्राथमिकता देंगे और वहाँ के काम करवाएंगे लेकिन बाकी हलकों में भी हम काम करवाएंगे किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। विपक्ष के सदस्यों ने अपने भाषण में बोलते हुए बताया कि हमने घाटे का बजट पेश किया है। सर, मांगे राम जी और हुड्डा जी यहाँ से उठकर चले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर यह रिवायत रही है कि अगर सदन में किसी ने गलत फिगर दी है तो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आता है। चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ लीडर ऑफ दी अपोजीशन होते हुए और और मेरे खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन आया था। अगर हम चाहते तो जो मांगे राम गुप्ता जी यहाँ पर बोल रहे थे और इसी तरीके से रघुबीर सिंह जी भी बोलकर चले गए थे। सर, अगर इन लोगों की बात की जाए तो जो फिगर उन्होंने दी थी, उसके आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। मैं इन बातों पर बाद में आऊंगा। पहले मैं बजट घाटे के बारे में बताना चाहता हूँ। सर, हमें तो विरासत में यह घाटा मिला था। 24 जुलाई, 1999 को जब चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी थी उस वक्त घाटा 150 करोड़ रुपये का था

लेकिन उसके बाद यह घाटा 31 मार्च को बढ़कर 196.77 करोड़ हो गया। स्पीकर सर, मैक्सिमम घाटा तो उनके वक्त का ही है। हमने तो रिकवारी बढ़ायी ही है। बहुत मुसतैछी के साथ इस सरकार ने काम किया है, इनफोर्समेंट बड़ी ईमानदारी से की है। स्पीकर सर, जब हमने सत्ता संभाली थी उस वक्त एक्सार्ज तो माईनस में आ गया था और सेल्ज टैक्स की इंकीज एक प्वायंट कुछ की थी जो अब बढ़कर 13.5 हो गयी है। स्पीकर सर, इस तरह के एफर्ट्स आपकी सरकार ने किए हैं और तभी जाकर के यह रिकवारी बढ़ी है। जब इन चीजों की रिकवारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि घाटे की पूर्ति भी होगी। मांगे राम गुप्ता जी कह रहे थे कि उन्होंने अपने समय में प्लस में बजट पेश किया था। अब वे यहां पर हैं नहीं वरना उनके खिलाफ प्रिवलेज का मोशन बनता है। स्पीकर सर, उनके बजट के बारे में भी मैं यहां पर बताना चाहूंगा। 1991-92 के साल में 31 मार्च को जो ओपनिंग बैलेंस था वह माईनस 62.13 करोड़ रुपये का था जबकि वे कह रहे थे कि हमने प्लस का बजट पेश किया था। इसी प्रकार 1994 में जो ओपनिंग बैलेंस था वह माईनस 1.14 करोड़ रुपये का था। वे अब चले गए वरना मैं उनको बताता स्पीकर सर, 500 प्लस 91.88 यानी 592 करोड़ रुपये कहां चले गए क्या वे अपनी जेब में लेकर चले गए? क्या वे अपने साथ लेकर चले गए? स्पीकर सर, इसी तरह की गलत बयानबाजी उन्होंने की थी लेकिन अब वे इन बातों को छोड़कर चले गए क्योंकि सही सुनना उनको बर्दाश्त नहीं था। स्पीकर साहब, हमने घाटा पूर्ति के लिए बजट में प्राविजन रखा है

कि कैसे हम इसे पूरा करेंगे। इसी तरह से युनिफार्म सेलज टैक्स की बात आयी। सर, यह अब हरियाणा प्रदेश में लागू कर दिया गया है हालांकि दूसरे प्रदेशों ने चुनावों से पहले ही यह लागू कर दिया था। स्पीकर सर, भारत सरकार के वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलायी थी उसमें बड़ी सदभावना के साथ यह एग्रीमेंट हुआ था कि सभी राज्य युनिफार्म सैलज टैक्स लागू करेंगे। सर, यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले हम कहते थे कि हमारा बिजनेस माइग्रेट होकर दिल्ली चला गया, पंजाब वाले कहते थे कि उनका बिजनेस राजस्थान या हरियाणा चला गया और यू0 पी0 वाले कहते थे कि उनका बिजनेस दिल्ली चला गया यानी सभी स्टेट्स अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बात कहते हैं उनकी अलग अलग ओब्जेक्टिव्स थी। लेकिन बाद में बड़े अच्छे तरीके से यूनिफार्म सैलज टैक्स की पालिसी बनी। उस समय हम इसको लागू नहीं कर सकते थे क्योंकि चुनाव आ गये थे और अगर हम ऐसा करते तो चुनाव अचर संहिता आड़े आ जाती। लेकिन चुनावों के बाद हमने युनिफार्म सेलज टैक्स लागू किया है। अब इससे 75 करोड़ रुपये की आमदनी होगी और इस तरह से भी घाटा पूरा होगा। इसी प्रकार से जो दसवां सेंट्रल फाईनेंशियल कमीशन था उसने भोयर्स आफ सेंट्रल टैक्सिज की 26 परसेंट की बजाए 29 परसेंट फालतू इंकी मान ली थी। उन्होंने सेंट्रल टैक्सिज में स्टेट भोयर्स 26 परसेंट की बजाए 29 परसेंट मान लिया था लेकिन यह एरियर्स भी अभी तक आए नहीं हैं। स्पीकर सर, हमारा अनुमान है कि यह

एरियर करीब 155 करोड रुपये के आएंगे। अगर गुप्ता जी होते तो ये तर्क हम उनको भी बताते क्योंकि वे कह रहे थे कि घाटै को कैसे मीट आउट करेंगे। परंतु वे चले गए। स्पीकर सर, हमे तो विरासत मे ही 150 करोड रुपये का घाटा मिला था। उल्टे हमने तो रिकवारी करके रैवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की है। स्पीकर सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, इंटलिजेंट है। सारे देश की इकोनोमी मे रिसैशन आ रहा था जैसे मैं पहले कह रहा था कि पाकिस्तान ने कैसे युद्ध किया, उन दिनों कैसे हालात थे। यह तो हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था थी जो एग्रीकल्चर बेस्ड है। जापान या कोरिया जैसे लोगों की इकोनोमी तो ऐसे हालात में फेल हो जाती, वे भिखमंगे हो जाते और उनको कोई भीख भी न देता। ये तो हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था है जिस पर हमें फख है कि एक तरफ तो बोर्डस पर हमारे देश के जवानो ने देश की सीमाओ की रक्षा करने मे अपनी जान की बाजी लगा दी जिसमें हरियाणा प्रदेश का सबसे ज्यादा योगदान है। हमारे यहां कृषि के भंडार है और अनाज का जो उत्पादन है उसमे हरियाण प्रदेश ने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया है। मेरे कहने का मतलब है कि इन विपरीत हालातो मे हमने इतना अच्छा उत्पादन किया है जिससे हमारी इकोनोमी रिसैशन से बाहर आ रही है। जब इकोनोमी रिसैशन से बाहर आयेगी तब ग्रोथ बढेगी, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का उत्पादन बढेगा, इंडस्ट्रीयल उत्पादन बढेगा। नयी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी आई है। इस बारे में मैं लम्बी चौडी बात न करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने जो पॉलिसी लागू की है इससे

काफी निवे । किया है वह कितना कैटेलाइज हो चुका है जिससे अपने आप पता लग जाएगा कि हरियाणा प्रदेश की इकोनोमी किधर जाएगी और किस तरह से घाटे को पूरा करेगी। जो नयी औद्योगिक नीति आई है और कैटेलाइज हुई है उससे फरवरी 2000 तक जो निवे । आए है वह 2641 करोड़ के आए है और पाइप उद्योग लगाने के लिए 252 करोड़ रुपये आए है टोटल 2900 करोड़ की इन्वैस्टमेंट कैटेलाइज हो चुकी है इससे आप अंदाजा लगा सकते है कि इकोनोमी को कितना चढाव मिलेगा और इसे 64600 लोगो को रोजगार मिलेगा। सुबह कह रहे थे कि जॉब्स के लिए प्रबंध नहीं कर रहे है। विकास से इम्प्लौयमेंट मिलता है सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती। जब तक प्रदेश का बहुमुखी विकास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। सडक, स्कूल, अस्पताल, कालेज और नहरे बनेगी तो अपने आप लोगो को रोजगार मिलेगा। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो कैसे विकास होगा? अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि प्रदेश के क्या हालात थे जब वर्तमान सरकार ने पदभार संभाला था सारा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया था चाहे सडको की बात हो, या नहरो की बात हो या स्कूलो की बात हो या चाहे अस्पतालो की बात हो सारा का सारा स्ट्रक्चर रिवाइज करने का फैसला किया और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत घर घर गए और जिन लोगो की बात कोई सुनता नहीं था उनकी बात सुनी। जो लोग चंडीगढ आकर घुम घुम कर चले जाते थे उनकी बात को सुनकर हरियाणा प्रदेश के विकास को भुरु किया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जब प्रदेश में

विकास के काम होंगे तो घाटे का बजट होगा। मांगे राम गुप्ता जी भी कोई विकास कार्य नहीं कर पाए थे सिर्फ गलत आंकड़े देकर चले गए थे। अध्यक्ष महोदय, यह बजट रोजगारोन्मुखी बजट है इससे रोजगार मिलेगा। अब मैं अग्रोहा मैडिकल कालेज के कर्ज की बात कहना चाहूंगा। कर्ज के बारे में उन्होंने बड़े ही जगलरी और ड्रामाटिक तरीके से गलत फिगरज पे कर देने की कोशिश की और जहां तक कर्ज का सवाल है, यह कर्ज कोई नयी बात नहीं है। स्वाभाविक है कि ग्रोइंग स्टेट है जिसको ग्रो करना है उसको कर्ज लेना पड़ेगा। बाकी जो नहर के सिस्टम को सुधारना है उसके लिए डबल्यू० आर० सी० पी० है उसका काम आज से नहीं है 5-6 साल से चल रहा है। हमारी कोशिश यह होगी कि इसको एग्जिस्ट कराये। नाबार्ड से लोन लेते हैं इरीगेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ताकि हमारे एग्रीकल्चर सैक्टर में मजबूती आये। पावर सैक्टर के लिए भी लोन लेना पड़ता है इससे हमारा पावर सैक्टर मजबूत होगा। अगर पावर सैक्टर मजबूत होता है तो स्वाभाविक है कि कृषि क्षेत्र मजबूत होगा (इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री रामपाल माजरा जी चेयर पर पदासीन हुए) सभापति महोदय, आप भी पैडी एरिया से संबंध रखते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पावर सैक्टर मजबूत नहीं होगा तो किसानों की पैडी के सीजन में क्या हालत होगी। चेयरमैन साहब, आपको याद होगा कि 1987-88 में चौधरी देवी लाल जी ने किसानों को बिजली देरक रिकार्ड तोड़ पैडी की पैदावर करवायी थी और इस बार चौधरी औम प्रकाश

चौटाला जी ने किसानों को पूरी बिजली देकर पैडी की रिकार्ड तोड़ पैदावार करवायी है। चेरमैन सर, आज तक हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है कि सत्ता पक्ष की सरकार को चुनाव के समय हमें नैगेटिव वोट जनता ने दिया है। पूरे देश में या तो आन्ध्र प्रदेश की सरकार है या पश्चिमी बंगाल की सरकार है जिनको जनता ने चुनाव के समय पोजीटिव वोट दिया है। आज हरियाणा प्रदेश देश का तीसरा राज्य है जिसको सरकार को चुनाव के समय जनता ने पोजीटिव वोट दिया है और पोजीटिव मैनडेट दिया है। आज चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी की सरकार को वर्क्स का आधार पर दोबारा चुनकर 36 बिरादी के लोगों ने यह सरकार बनाई है। दूसरी बात कही गई कि कर्जा कैसे मिलेगा। विपक्ष के साथियों ने तो यह बात ऐसे कह दी जैसे यह सारा का सारा 15217 करोड़ रुपये का कर्जा वर्तमान सरकार ने ही किया है। जब वर्तमान सरकार ने पदभार संभाला उस समय कर्जों की राशि 12750 करोड़ रुपये थी। और कहते ऐसे हैं जैसे यह सारा कर्जा हमने ही लिया हो। अगर वर्तमान कर्जों की राशि को हम देने में सक्षम हो जायेंगे तो एक दिन हरियाणा प्रदेश टैक्स फ्री स्टेट और कर्जा फ्री स्टेट बन जायेगा और ऐसा तभी संभव है जब कि सरकार स्थिर हो। इस बार जिस प्रकार चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार को लोगों ने मैनडेट करके भेजा है उसी हिसाब से हरियाणा प्रदेश बहुमुखी विकास यह सरकार करेगी। चेरमैन साहब जैसे कि श्री मांगे राम गुप्ता जी ने अग्रोहा मैडिकल कालेज के बारे में बात की और आनन फानन में ही औम प्रकाश

जिंदल ने भी इस बारे में अपनी बात की। चेयरमैन साहब, जैसे एग्रीमेंट चौधरी देवी लाल जी ने किया था वैसा एग्रीमेंट आज तक कभी नहीं हुआ क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मैडिकल कालेज की 99 प्रतिशत रिकरिंग ग्रांट सरकार दे और वह कालेज प्राइवेटली अरेंज्ड कालेज हो। चौधरी देवी लाल जी को एक तरफ महाराजा अग्रसेन जी के नाम से लगाव था और दूसरी ओर अग्रवाल कम्यूनिटी के साथ लगाव था तथा तीसरा हरियाणा स्टेट से लगाव था। हरियाणा प्रदेश को चार मैडिकल कालेज की जरूरत थी। उस समय केवल एक ही मैडिकल कालेज रोहतक में था। चौधरी देवी लाल जी ने हिम्मत करके 99 प्रतिशत ग्रांट अग्रोहा मैडिकल कालेज को दी थी। स्पीकर सर, मैचिंग ग्रांट स्कीम में 50 प्रतिशत ग्रांट पब्लिक की तरफ से आती है और 50 प्रतिशत ग्रांट सरकार देती है। इस ग्रांट से उस कालेज के लिए इक्विपमेंट आदि खरीदे जाते हैं। लेकिन चौधरी भजन लाल जी एक्विपमेंट खरीदने वाली उस ग्रांट को बंद कर गए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए जो ग्रांट दी जाती थी उसको चौधरी बंसी लाल जी ने खत्म कर दिया। अब चौधरी भजन लाल जी को वे श्री मांगे राम गुप्ता जी को तो इसके लिए एग्रीमेंट करना चाहिये था क्योंकि श्री मांगे राम गुप्ता जी तो अग्रवाल कम्यूनिटी से हैं। श्री औमप्रकाश जिंदल जी भी अग्रवाल कम्यूनिटी से हैं। इसलिए उनको भी एग्रीमेंट करना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी की सरकार में श्री मांगे राम गुप्ता जी शामिल थे और दूसरी सरकार में श्री औमप्रकाश जिंदल पार्टी के

सदस्य थे। अब दोनों ही माननीय सदस्य वाक आउट कर गए। इसके बाद श्री मांगे राम गुप्ता जी ने सात करोड़ रुपये देने की बात रखी। चेयरमैन सर, जब डिमाण्ड आती है तभी एल0 ओ0 सी0 रिली कर दी। इसके बाद उनकी डिमाण्ड आई 50 लाख रुपये निर्माण कार्यों के लिए चाहिए क्योंकि उन्होंने इसकाम के लिए टैण्डर इंवाइट किए हुए है। वे 50 लाख रुपये भी रिलीज कर दिए। मैंने पहले भी कहा था कि यह सरकार इस बारे में बिल्कुल कटिबद्ध है। पिछली बार बजट में अग्रोहा मैडिकल कालेज के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान था और इस साल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैडिकल कालेज को रिकोग्नाइज करने के लिए जितना पैसा चाहिए था उसके लिए चौधरी देवी लाल जी ने जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट की कंडी शर्तों के आधार पर उस एग्रीमेंट की एक एक लाइन को, एक एक भाग को पूरा करने के लिए यह सरकार तैयार है, कटिबद्ध है और यह सरकार उसको पूरा करेगी। इसी तरह के सेलज टैक्स के बारे में औम प्रकाश जिंदन जी और मांगे राम जी ने कहा कि उन्होंने 2-3 आईटम जिन पर उन्होंने सैलज टैक्स कम किए थे, बहुत ही छोटी आईटम थी। 1987 से 1991 में जब देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे और बाद में श्री औम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय 65 आईटमों पर सैलज टैक्स या तो खत्म कर दिए गए थे या फिर कम कर दिये गए थे। उस समय यह कितना सराहनीय काम किया गया था। अब भी व्यापारियों के हित सरकार के हाथों में सुरक्षित है। मुख्यमंत्री महोदय ने जो हाई पावर कमेटी बनाई उसमें कांग्रेस

पार्टी का जो नोमिनी था उसको व्यापारी वर्ग के अध्यक्ष के रूप में भामिल किया गया। जबकि इस कमेटी में जो व्यापारियों का प्रतिनिधि होता है वह इन्फ्रिस्पैक्टिव आफ एनी पार्टी एफिलिएट होता है। पिछली सरकारों के समय में अपने विचारों के लोगों को अपने चहेतों को जो पिछलग्गू टाइप होता है। पिछली सरकारों के समय में अपने विचारों के लोगों को, अपने चहेतों को जो पिछलग्गू टाइप के होते हैं उनको इस कमेटी में भामिल कर लिया जाता था। ऐसा काय्य करके मुख्यमंत्री श्री औम प्रकाश चौटाला जी ने कितनी उदारदिली दिखाई है, इनको इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके तहत 50 लाख तक के सैल्फ असैसिज़, 80 प्रतिशत सेल्ज टैक्स असैसिज़, 80 प्रतिशत व्यापारी कवर हो जाते हैं। अब उनको दफतरो के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी वजह से ही व्यापारियों ने भी श्री औम प्रकाश चौटाला जी को मेन्डेड किया है सभापति महोदय, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमने कई आइटम्स पर मार्किट फिस 2 प्रतिशत से घटाकर एक परसेंट की है। इन सब बातों के लिए इन लोगों को एप्रोपियेट करना चाहिए। कर विवाद स्कीम के बारे में भी हम सोच रहे हैं तथा और भी कई स्कीमों में हम लागू करने जा रहे हैं। पिछली सरकार के समय डी0 इ0 टी0 सी0 के दफतरो में टैक्स पेयी व्यापारियों के लिए बैठने के लिए प्रबंध नहीं होता था। हमारी सरकार ने अब उन व्यापारियों के लिए बैठने के लिए सैपरेट अरैन्जमेंट करवा दिया है, पीने के लिए पानी का भी इंतजाम करवा दिया है। पुरानी सरकारों में उनको चोर के रूप

में आंका जाता था और आज की सरकार उनको टैक्स पेयी के रूप में आंक रही है, उनको एक कंट्रीब्यूटर के रूप में आंक रही है। यही कारण है कि लोगो ने श्री औम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर इज्जत दी है। सभापति महोदय, किसानो की बात करते हुए यहां कहा गया है कि बजट में इतने परसेंट एग्रीकल्चर के मामले में जगलरी की गई है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि क्या पावर एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है, इरीगेशन एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है और दूसरी चीजें पैस्टीसाइड, इनसेक्टीसाइड, फर्टीलाइजर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई नहीं है? हर चीज एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इन सब चीजों के बजट के बारे में हमने जो प्रावधान किया है उस बारे में तो ये लोग बात नहीं करते हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने युनीफोर्म सेल्ज टैक्स लागू करते समय भी किसानो के हितों पर निगार रखी है। युनीफार्म सेल्ज टैक्स पोलिसी लागू होने के बावजूद भी हमने फर्टीलाइजर, पेस्टीसाइड, इनसेक्टीसाइड को इसमें शामिल नहीं किया है। क्योंकि इन तीनों चीजों का किसान ने डायरेक्ट संबंध है। इससे सरकार को 75 करोड़ रुपये का नुकसान होगा परंतु हमारी सरकार को किसानो के हित प्यारे हैं न कि 75 करोड़ रुपये। इसी तरह से मांगे राम जी जाते जाते कह गए कि रुरल डिवैल्पमेंट फण्ड के लिए बजट में 35.10 करोड़ रुपये रखे गए हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि पिछली बार 31 मार्च तक रुरल डिवैल्पमेंट फण्ड के लिए 120 करोड़ रुपये का एस्टीमेट रखा गया था परंतु इस साल कई चीजों पर मार्केट फीस जमा करने के कारण यह

एस्टीमेट 110 करोड रुपये का आ रहा है। यह रुरल डिवैल्पमेंट फण्ड विकास के कार्या पर ही खर्च होगा। आज यह सरकार हरियाणा प्रदे 1 के हर गांव की सडको को ठीक करवा रही है। सडको के गढढे भरवाने का काम यह सरकार पूरा करवा चुकी है। 30 मई तक सारे हरियाणा प्रदे 1 की टोटल सडको की मुरम्मत करवा दी जाएगी। इससे बढिया काम हमारी सरकार और क्या करेगी। सभापति महोदय, मांगे राम जी कह गये कि हमने प ु-पालन और मछली पालने के लिए बजट मे पैसा नही रखा। इस बारे मे मै कहना चाहूंगा कि वे बजट ठीक तरह से पढते तो है नही औरऐसे हीकुछ ही कह देते है। सभापति महोदय, बजट के पेज-17 पर कृशि, प ुपालन, बागवानी, मझली पालन, डेरी विकास तथा हरियाणा कृशि वि वविद्यालय हेतू वर्ष 2000-2001के लिए 308.03 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है और मांगे राम जी ने कहा कि इसके लिए हमने कोई पैसा नही रखा। इसी तरह से चेयरमैन सर, मांगे राम जी ने कहा कि हमने पुलिस के वैलफैयर के लिए बजट मे कोई पैसा नही रखा। मुझे तो यह कहते हुए भार्म आती है कि वे पांच साल तक वित्त मंत्री कैसे रहे। वे बिना पढे लिखे कुछ भी कह गये। चेयरमैन सर, पुलिस का जो मेजर हैड है उसमे 2055 करोड रुपये है। नोन प्लान मे पहले 363.94 करोड रुपये जमा रखा गया था और वर्ष 2000-2001 के लिए 396.73 करोड रुपये रखा गया है चेयरमैन साहब, इसी तरह से प्लान के लिए पिछले साल जो 6 करोड रुपये रखा गया था उसकी जगह 8 करोड रुपये इस साल के प्लान बजट मे रखे है।

चेयरमैन सर, इसी तरह से मांगे राम जी ने कहा कि हार्टिकल्चर के लिए जो 12.50 करोड रुपये रखा है वह कहां से आयेगा। इस बारे में भी बजट में चर्चा नहीं की गई। इस बारे में बताना चाहूंगा कि यह एक आन गोइंग प्रोसेस है और फरवरी 2000 तक इसमें 6 करोड रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 5.91 करोड रुपये हार्टिकल्चर के लिए और प्रोवाइड किये जायेंगे। इस तरह से ये 12.50 करोड रुपये के करीब बनते हैं इस तरह से यह पैसा अपने आप मीट-आउट हो जायेगा। चेयरमैन सर, चौधरी बंसी लाल जी ने एक सुझाव भी दिया था और भांका भी जाहिर की थी कि जो हिसार घग्गर ड्रेन का प्रोजैक्ट है, क्योंकि वह और स्टेटस से संबंधित है इसलिए उसके बारे में साथ लगती स्टेटस आब्जैक्टिवान उठायेगी। इस बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार तो इसे सकता है कि आब्जैक्टिवान करे लेकिन पंजाब और हिमाचल आब्जैक्टिवान नहीं करेंगे। चेयरमैन सर, मैं बंसी लाल जी को बताना चाहूंगा कि इस प्रोजैक्ट के लिए एक कमेटी बनी हुई है और सी० डबल्यू० सी० (फल्ड) का मੈबर उस कमेटी का चेयरमैन है। उन्होंने इस ड्रेन के लिए उ बकायदा क्लियरेंस दे दी है। क्लियरेंस के बाद ही यह प्रोजैक्ट भुरु किया गया है। स्पीकर सर, डा० कादियान जी ने भी कहा था कि इरीगे टिवान के उपर, पावर के उपर, ट्रांसपोर्ट के उपर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 64.5% रुपये रखे हैं, उसके बारे में यह नहीं बताया गया कि यह पैसे कहां से आयेगा और कैसे इसको यूज किया जायेगा। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह 64.5: पैसा आउट आफ प्लान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर

खर्च किया जाएगा। यह बजट मे भी लिखा हुआ है। ये लोग बजट के बारे मे किताब तो पढते नही है और कुछ भी कह देते है। सभापति महोदय, यह 64.5% पैसा पप्लान हैड में 2530 करोड रुपये रखा गया है उस पैसे मे से ही इन्फास्ट्रकचर पर खर्च होगा। इसी तरह से जिंदल साहब को अपनी इंडस्ट्री की तकलीफ थी। उन्होने कहा कि सेल टैक्स ट्रिब्यूनल के मैम्बर जुडिाियल हो, फलाना हो, परमानेंट हो, रैगुलर हो, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। इस तरह की बातो का इन्होने यहां जिक्र किया हे जबकि कोर्ट मे विचाराधीन केस के बारे में जिक्र सदन मे नही किया जा सकता। हिसार मे मै0 जिंदल स्ट्रिप्स लि0 के नाम से इनकी कम्पनी है। इस कम्पनी द्वारा ओनरेबल पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट मे केस डाला हुआ है। Now, the matter is pending with the Hon'ble High Court जबकि यहां ये सुझाव दे रहे है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इस तरह की बातो का इनको इस सदन में जिक्र नही करना चाहिए था। क्या ये अपनी कम्पनी का इन्ट्रस्ट वॉच करने के लिये विधान सभा मे आये हैया लोगो को इंट्रस्ट वाच करने के लिए आये है। थोडा बहुत इस बात का ध्यान तो इनको रखना चाहिए। (इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिंदल साहब ने गजट नोटिफिके ान के बारे मे कहा कि इनको गजट नोटिफिके ान होने का कोई पता नही चलता है। मांगे राम गुप्ता जी ने भी इस तरह की बात की थी। किसी ने जिंदल साहब को कुछ टाईप करके दे दिया जिसको वे यहां पढ रहे थे। इनको पता कुछ है

नहीं, बोलना कुछ आता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक गजट नोटिफिके इन का सवाल है, इससे जो रिलेवेंट इन्फर्मे इन है वह बिल्कुल प्रोम्पटली बकायदा प्रैस के थ्रू दी जाती है और अब तो आप इस बात को भी एप्रीं एट करेंगे कि इसको भी डिपार्टमेंट ने इन्टरनेट वेब साइट में फीड कर दी है। अब जिंदल साहब जब मर्जी जो इन्फर्मे इन लेना चाहे वह इन्टरनेट वेब साइट पर ले सकते हैं। आज कल तो बड़े बड़े व्यापारियों ने बकायदा इंटरनेट लगा रखे हैं। इससे फालतू और क्या सुविधा सरकार दे सकती है। आज अगर कोई गजट नोटिफिके इन आती है तो उसी टाइम इन्टरनेट वेब साइट में फीड कर दी जाती है। जब मर्जी कम्प्यूटर को खोलकर पता कर लें। इससे बड़ी सुविधा हरियाणा सरकार और क्या दे सकती है। इन्होंने तो आलोचना के लिए भी आलोचना करनी है। अध्यक्ष महोदय, राई की मझड़ी के बारे में माननीय सदस्य चौ० सूरजमल ने जिक्र किया था। पहले भी कई सदस्यों ने गवर्नर एड्रेस के टाइम इस मण्डी के बारे में जिक्र किया था। यह परियोजना भी हम बकायदा सिरे चढाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार ने भी एक प्लान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 1 पर खानपुर कलां में इसी तरह की मण्डी बनाने की एक परियोजना बनाई है। अगर वे भी इस योजना को बना लेते हैं तो हमारी इस योजना पर चाहे कितना भी पैसा क्यों न खर्च कर लें वह कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए हमने दिल्ली सरकार के साथ मैटर टेक अप किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के साथ बात की है कि हमारे यहां आलरेडी यह परियोजना है

और आप अपनी इस परियोजना को रहने दे और हमे अपनी परियोजना को कान्टीन्यू करने दे। ताकि इस प्रोजैक्ट पर हमारी जो ग्रोथ बाकी है उसको हम पूरा करें। हमने इस मैटर को सीरियसली टेक-अप किया हे जबकि आज तक किसी भी सरकार ने इस मामले को टेक-अप नहीं किया। केवल उस पर ये लोग झुड झंकार करते रहे। इन लोगो को तो इस बात के लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए और इस काम मे मदद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष के सदस्य कहते है कि फलड कन्ट्रोल मे केवल 20 करोड रुपया रखा है। मै इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 20 करोड रुपया कैसे रखा है। डब्ल्यू० आर० सी० पी० मे फलड कंट्रोल का पैसा है, रुरल इंफरास्टरकचर डिवैलपमेंट फण्ड में फलड का पैसा है और नाबार्ड मे भी फलड कंट्रोल का पैसा है। यह 20 करोड रुपया तो प्लान आउट ले मे स्टेट की तरफ से खर्च होना है इसके अलावा फलड कन्ट्रोल का काम दूसरी ड्रेनो वगैरा को बनाकर किया जाएगा। जिन ड्रेनो के प्रोजैक्ट चल रहे है उन प्रोजैक्टो को भी पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब बिलो-पोवैरटी लाइन की बात आती है। अध्यक्ष महोदय, आप भी चुनावो के दौरान गावो मे गए, हम भी गये। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले सभी गावो मे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ओपन दरबार लगाए थे और उस समय मुख्यमंत्री जी को लोगो की िकायतें मिलती थी कि फलाना बिलो पोवरटी लाठन मे है, मेरा कार्ड नहीं मिला है। हालांकि 1998 मे बी० पी० एज० का सर्वे हो चुका था जिसकी सूची मे पांच लाख 64 हजार

नाम बरे थे फिर भी सी० एम० साहब ने 29-11-99 को आदे 1 जारी किए कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति रह गये है जिनका नाम सर्वे के दौरान उस सूची मे नही जोडा गया है उनके नाम जोडने के लिए भी कार्यवाही की जाए। सी० एम० साहब के आदे 10 के मुताबिक सर्कुलर जारी हो चुका है और जो आवेदन आए है उन पर कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा नये आवेदन भी विभाग को दिया जा सकते है उन पर बकायदा कार्यवाही की जाएगी और सर्वे पूरा किया जाएगा। इससे बडा सराहनीय काम और क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल तीन चार बार इस प्रदे 1 के मुख्यमंत्री रह चुके है और विपक्ष मे तो इनको बैडने का थोडा ही समय मिला है। इन्होने कहा कि पावर सैक्टर मे 800 करोड रुपये की एग्रीकलचर के लिए सबसिडी रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि वह अमाउंट 800 करोड रुपये नही बल्कि 846.40 करोड था जिसमे से 1998-99 की कै 1 सबसिडी केवल 364 करोड रुपये की थी ओर 482.50 करोड रुपये तो लोन की एडजस्टमेंट थी। इस तरह इनकी फिगरज मिक्स हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, जैसा गलत ब्यानी मांगे राम जी कर रहे थे उसी तरह से हुडडा साहब भी गलत ब्यानी कर रहे थे कि अब याहं बैठे नही हैं वे अपने आपको राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का अध्यक्ष मानते हैं वे पार्लियामेंट के मैम्बर भी रह चुके है और अपने आपको सीनियर आदमी कहते है। हुडडा साहब ने अपने भाशण मे कहा कि महाराष्ट्र मे गन्ने के दाम 76/- रुपये प्रति क्विंटल दिये

है जबकि हरियाणा सरकार ने 110/ प्रति क्विंटल गन्ने के दाम दिये हैं। जहां तक रिकवारी का सवाल है तो हमारी सरकार की रिकवारी ओन एन एवरेज 9% है। कभी कभी किसी एक आधी मिल की रिकवारी 10 तक आ जाती है जबकि महाराष्ट्र की रिकवारी 12% से 14% रहती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर गन्ने की फसल तकरीबन 10 महीने में तैयार हो जाती है जबकि महाराष्ट्र में एक साल में बहुत अधिक आती है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में तो गन्ने के दाम 76 रुपये प्रति क्विंटल हैं जबकि हमारे यहां पर 110 रुपये प्रति क्विंटल हैं। गवर्नर एड्रेस पर बोलते हुए हुड्डा साहब ने गन्ने की प्राइस के बारे में बहुत गलत ब्यानी की है। अध्यक्ष महोदय, जैसे उन्होंने यहां पर गलत ब्यानी की है उस हिसाब से तो उनके खिलाफ प्रिविलिज मोशन आ जाना चाहिए था। सदन के दूसरे सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं वे नोट कर लिए गए हैं। विपक्ष के सदस्यों ने रचनात्मक तरीके से बजट पर विचार प्रकट न करके आलोचनात्मक तरीके से अपने विचार प्रकट किए हैं। अन्त में स्पीकर साहब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो बजट हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए प्रस्तुत किया है उसे युनानीमसली पास किया जाये। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष का चुनाव

Mr. Speaker: Now, election of Deputy Speaker will be conducted. I call upon the Hon'ble Chief Minister to propose the name for the election of the Deputy Speaker.

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, पुरानी ट्रेडी मैन को बरकरार रखते हुए स्पीकर सत्ता पक्ष से चुना गया है। विपक्ष की तरफ से यह मांग उठती रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष की तरफ से चुना जाना चाहिए। चूंकि स्पीकर सत्ता पक्ष का होता है, उस पद पर आप चुने जा चुके हैं और आपने अपनी पार्टी से वे उसकी प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो यह मांग हमारे विपक्ष की तरफ से उठी है। अब हाउस में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वह तो इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। इस समय विपक्ष के रूप में सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार सदन में उपस्थित है। जो आजाद उम्मीदवार चुन कर आए हैं उनकी संख्या विपक्ष के दूसरे नम्बर पर आती है। आजाद उम्मीदवारों की गिनती को मध्यनजर रखते हुए मेरे विचार से उनमें से एक सदस्य को डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनना चाहिए। श्री गोपी चन्द गहलोत जी जो गुडगांव से जीत कर हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए हैं वे काबिल उम्मीदवार हैं। स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री गोपी चन्द गहलोत जो कि सदन में उपस्थित हैं, को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाये।

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, श्री औम प्रकाश चौटाला जी ने श्री गोपी चन्द गहलोत जी के नाम को उपाध्यक्ष के नाम के लिए प्रस्तावित किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

Mr. Speaker: Motion moved-

That Shri Gopi Chand Gahlot, a member of the Haryana Legislative Assembly, who is present in the House, be elected as Deputy Speaker of the Assembly.

Is there any other proposal please?

Voices: No.

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि सदन के नेता ने श्री गोपी चन्द गहलोत जी को जो आजाद उम्मीदवार चुन कर सदन में आये हैं, सदन के उपाध्यक्ष के लिए उनके नाम का प्रस्तावित किया है। चौधरी गहलोत जी बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता हैं। मैं इनके नाम का उपाध्यक्ष पद के लिए समर्थन करता हूँ। हमें उम्मीद है कि ये हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। इसलिए मैं पुनः सदन के नेता का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने गोपी चन्द जी के नाम का जो उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। और इनके नाम का अनुमोदन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे। अतः मैं

इनके उपाध्यक्ष चुने जाने पर इन्हें बधाई देते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

श्री राम भगत: अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता आजाद उम्मीदवारों का जो मान-सम्मान बढ़ाया है उसके लिए मैं सदन के नेता का धन्यवाद करता हूँ। और श्री गोपी चन्द जी के उपाध्यक्ष चुने जाने के नाम का अनुमोदन करते हुए और इन्हें धन्यवाद देते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

Mr. Speaker: Since there is only one proposal before the House that Shri Gopi Chand Gahlot be elected as Deputy Speaker. I declare him duly elected as Deputy Speaker of the Assembly Unanimously. (Thumping) I request him to take the seat of the Deputy Speaker.

(As this stage, Shri Gopi Chand Gahlot Excorted by the Chief Minister and Shri Krishan Pal, a member of the Bharatiya Janata Party and many other independent Members, occupied the seat of the Deputy Speaker) (Thumping)

17:00 बजे

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गोपी चन्द गहलोत की को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के पद पर चयन करने के लिए इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अब तक की उन सारी परम्पराओं को बरकरार रखा। श्री गोपी चन्द गहलोत जी एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और एक वकील के रूप में बहुत लम्बे समय तक उन्होंने लोगों की सेवा

की है। कानून का ज्ञाता होने की वजह से छोटे मोटे विवादों और बखेड़ों को सुलझाने में भी उनको कठिनाई का सामान नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी ग़रसरुट्स से आया हुआ व्यक्ति आम नागरिक की समस्याओं और दिक्कतों को सुलझाने में बहुत ही चतुर होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण यकीन, वि वास ओर भरोसा है कि आपकी तरह ही श्री गोपी चन्द जी भी इस पद की गरिमा को बरकरार रखेंगे तथा सारे हाउस को वि वास में लेकर सदन के हर सदस्य को अपनी तरफ से पूरा मान तथा सम्मान प्रदान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता के तौर पर और सभी सदन के सम्मानित सदस्यों की तरफ से मैं उपाध्यक्ष महोदय को यह वि वास दिलवाऊंगा कि हमारी तरफ से आपको भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री गोपी चन्द गहलोत जीख आज आप युनानीमसली हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्विवाद चुने गए हैं उसके लिए इस महान सदन को बड़ी खुशी महसूस हुई है तथा सारे हरियाणा प्रदेश को भी इससे बड़ी खुशी महसूस होगी क्योंकि एक सुयोग्य, पढा-लिखा, कानून का ज्ञाता और बड़े नर्म तबीयत के इंसान को हरियाणा विधान सभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर निर्विवाद चुना गया है। भगवान श्री गोपी चन्द गहलोत जी को ऐसी ताकत दे कि वे अपने इस गरिमामई पद को ग्रहण कर इसे गरिमामयी ढंग से चलायें तथा राज्य तथा अपने लोगों को विकास और भलाई के रास्ते पर चलाएं। भगवान

हर मामले में उनकी मदद करे ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: इस महान सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी और दूसरे सदन के सभी साथियों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। मैं अपनी ओर से आप सबको विवास तथा आवासन दिलाना चाहता हूँ कि इस पद की गरिमा को मैं पूर्ण रूप से कायम रखुंगा तथा अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही को आप सब के सहयोग से रूलज और पार्लियामेंटरी कन्वेंशन के मुताबिक चलाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मैं आप सबसे खासकर लीडर आफ दी ओपोजीशन जो मेरे साथ बैठते हैं से भी सहयोग की आशा करता हूँ। मुझे पूर्ण विवास है कि आप सभी मुझे अपना पूरा सहयोग देंगे ऐसी उम्मीद और अपेक्षा आप सब से करता हूँ। एक बार पुनः आप सब को धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करता हूँ विशेष तौर पर हाउस के नेता का आभार प्रकट करता हूँ। मैं हर किमत पर सदन की गरिमा को कायम रखुंगा। विशेषकर नवआगतों के हितों की रक्षा करने की कोशिश करूंगा।

वर्ष 2000-2001 के बजट पर अनुदानों की मांग पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion and voting on the Demands for Grants on Budget for the year

2000-2001 will take place. as per the past practice and to save the time of the House, the demands on order paper (Nos. 1 to 25) will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Member can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding Rs. 6975000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 1- Vidhan Sabha*.

That a sum not exceeding Rs. 1087397000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 2- General Administration*.

That a sum not exceeding Rs. 4562442000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 3- Home*.

That a sum not exceeding Rs. 755766000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 4- Revenue*.

That a sum not exceeding Rs. 399500000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 5- Excise & Taxation.*

That a sum not exceeding Rs. 7977525000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 6- Finance.*

That a sum not exceeding Rs. 2880169000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 7- Other Administrative Services.*

That a sum not exceeding Rs. 3899113000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 8- Building and Roads.*

That a sum not exceeding Rs. 13069733000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 9- Education.*

That a sum not exceeding Rs. 5983554000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 10- Medical and Public Health.*

That a sum not exceeding Rs. 328144000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 11- Urban Development.*

That a sum not exceeding Rs. 575468000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 12- Labour and Employment.*

That a sum not exceeding Rs. 4633144000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.*

That a sum not exceeding Rs. 218074000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 14- Food and Supplies.*

That a sum not exceeding Rs. 9143500000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 15- Irrigation.*

That a sum not exceeding Rs. 336343000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 16- Industries.*

That a sum not exceeding *Rs. 2314854000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 17- Agriculture.*

That a sum not exceeding *Rs. 1037793000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 18- Animal Husbandry.*

That a sum not exceeding *Rs. 98392000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 19- Fisheries.*

That a sum not exceeding *Rs. 670765000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 20- Forest.*

That a sum not exceeding *Rs. 930221000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 21- Community Development.*

That a sum not exceeding *Rs. 243815000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 22-Co0Operation.*

That a sum not exceeding *Rs. 4704037000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 23-Transport.*

That a sum not exceeding *Rs. 16021000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 24- Tourism.*

That a sum not exceeding *Rs. 3792610000* for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 25- Loans and Advances by State Government.*

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही से बजट पर बहस चल रही है। बजट से ही ये डिमाण्डज राईज होती है। आलरेडी इन पर सब बोल चुके हैं। अगर हाउस सहमत हो तो इन सबको इकट्ठा ही पास कर लिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

Mr. Speaker: Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 6975000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 1- Vidhan Sabha.*

That a sum not exceeding Rs. 1087397000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 2- General Administration.*

That a sum not exceeding Rs. 4562442000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 3- Home.*

That a sum not exceeding Rs. 755766000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 4- Revenue.*

That a sum not exceeding Rs. 399500000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 5- Excise & Taxation.*

That a sum not exceeding Rs. 7977525000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 6- Finance.*

That a sum not exceeding Rs. 2880169000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 7- Other Administrative Services.*

That a sum not exceeding Rs. 3899113000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 8- Building and Roads.*

That a sum not exceeding Rs. 13069733000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 9- Education.*

That a sum not exceeding Rs. 5983554000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 10- Medical and Public Health.*

That a sum not exceeding Rs. 328144000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 11- Urban Development.*

That a sum not exceeding Rs. 575468000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 12- Labour and Employment.*

That a sum not exceeding Rs. 4633144000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.*

That a sum not exceeding Rs. 218074000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 14- Food and Supplies.*

That a sum not exceeding Rs. 9143500000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 15- Irrigation.*

That a sum not exceeding Rs. 336343000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 16- Industries.*

That a sum not exceeding Rs. 2314854000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 17- Agriculture.*

That a sum not exceeding Rs. 1037793000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 18- Animal Husbandry*.

That a sum not exceeding Rs. 98392000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 19- Fisheries*.

That a sum not exceeding Rs. 670765000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 20- Forest*.

That a sum not exceeding Rs. 930221000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 21- Community Development*.

That a sum not exceeding Rs. 243815000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 22- Co-Operation*.

That a sum not exceeding Rs. 4704037000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 23- Transport*.

That a sum not exceeding Rs. 16021000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 24- Tourism*.

That a sum not exceeding Rs. 3792610000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2000-2001 in respect of charges under *Demand No. 25- Loans and Advances by State Government*.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House stand adjourned till 9:30 A.M tomorrow the 16th March, 2000.

(The Sabha then adjourned till 9:30 A.M. on Thursday the 16th March, 2000).